



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2019/आषाढ़ 11, 1941

No. 181]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2019/ASHADHA 11, 1941

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2019

विषय : पावरटेक्स इंडिया के तहत निटिंग एवं निटवियर क्षेत्र के विकास के लिए 01.07.2019 से 31.03.2020 तक के लिए व्यापक योजना के दिशा-निर्देश।

सं. 1/6/2018-पीएल.— निटिंग और निटवियर क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र है तथा वस्त्र निर्यात में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा, निटिंग और निटवियर इकाइयां मुख्यतः एमएसएमई इकाइयां हैं जो लुधियाना, त्रिपुर, कोलकाता, सूरत, बेंगलूरु आदि जैसे मुख्य क्लस्टरों में स्थित हैं। हालांकि, निटिंग और निटवियर इकाइयों को निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी स्तर की नई मशीनों की स्थापना के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत लाभों के लिए कवर किया गया है, निटिंग और निटवियर उद्योग/क्षेत्र के लिए अवसरचना विकास, ऋण सुविधा, क्लस्टर में अपेक्षित सामान्य सुविधाओं, कच्चे माल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव इत्यादि पर केंद्रित कोई योजना नहीं है। इसलिए वस्त्र मंत्रालय ने निटिंग और निटवियर उद्योग/क्षेत्र में हस्तक्षेप करने/सुविधा प्रदान करने/सहायता करने का निर्णय लिया था तथा दिनांक 05.06.2017 को वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में निटिंग और निटवियर उद्योग/क्षेत्र के स्टेक धारकों के साथ एक बैठक की थी। उद्योग एवं वस्त्र मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त सुझावों/इनपुट के आधार पर एक योजना अर्थात् पावरटेक्स इंडिया के तहत निटिंग एवं निटवियर क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक योजना अनुमोदित की गई थी जो 01.07.2019 से 31.03.2020 तक लागू रहेगी।

1. संघटक एवं उद्देश्य

क.सं.	संघटक	उद्देश्य
1.	निटिंग एवं निटवियर क्लस्टरों में उद्योग/संघों द्वारा पीपीपी पद्धति के आधार पर नए सेवा केन्द्रों की स्थापना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग/संघों की सहभागिता से पीपीपी पद्धति के आधार पर क्लस्टरों में नए सेवा केन्द्र स्थापित करके निटिंग एवं निटवियर क्लस्टरों में परीक्षण, प्रशिक्षण, नमूना विकास, परामर्श देना, समस्या निवारण, सुविधा सेवाओं के लिए पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना है।
2.	निटिंग एवं निटवियर क्लस्टरों में टीआरए/ईपीसी संघों द्वारा चलाई जा रही	वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) (अथवा) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) अथवा किसी अन्य वस्त्र उद्योग संघ द्वारा संचालित वर्तमान विद्युत्करघा सेवा

	मौजूदा पीएससी/संस्थानों का आधुनिकीकरण और उन्नयन	केन्द्रों/संस्थानों में निटिंग एवं निटवियर उद्योग के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण/परीक्षण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित मशीनरी प्रदान करना
3.	निटिंग एवं निटवियर इकाइयों के लिए ग्रुप वर्क शेड योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान (अथवा) नए क्लस्टर में आधुनिक निटिंग मशीनों तथा/अथवा निटवियर के लिए ग्रुप वर्क शेड की स्थापना को सुकर बनाना है जिससे व्यापार प्रचालनों के लिए अपेक्षित स्केल ऑफ इकोनॉमी प्राप्त होगी तथा अधिक स्थान, कार्य परिवेश तथा कार्यक्षमता में सुधार के रूप में कार्य चालन की स्थिति में सुधार होगा, ताकि वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके।
4.	निटिंग एवं निटवियर इकाइयों के लिए यार्न बैंक योजना	इसका उद्देश्य विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीजी)/निटिंग इकाइयों के कंसोर्टियम को व्याज मुक्त कारपस निधि प्रदान करना है ताकि वे थोक दर पर यार्न की खरीद कर सकें तथा लघु निटिंग इकाइयों को उचित मूल्य पर यार्न दे सकें, जिससे यार्न की बिक्री पर विचालियों/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के दलाली प्रभारों से बचाव होगा।
5.	निटिंग एवं निटवियर इकाइयों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र योजना	निटिंग एवं निटवियर इकाइयों को प्रोसेसिंग, डाईंग, प्रिंटिंग, डिजाइन विकास, परीक्षण सुविधाओं, ईटीपी आदि जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न निटिंग एवं निटवियर क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना है।
6.	निटिंग एवं निटवियर इकाइयों के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना (स्टैण्ड अप इण्डिया योजना)	निटिंग एवं निटवियर इकाइयों को पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे निवेश आवश्यकताओं (सावधि ऋण) के लिए अनु. जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग से संबंधित नए उद्यमियों के लिए अपनी ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
7.	निटिंग एवं निटवियर इकाइयों के लिए सुविधा प्रदान करना, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता, अध्ययन, सर्वेक्षण, बाजार विकास एवं प्रचार	<p>निटिंग एवं निटवियर इकाइयों को हेल्पलाइन, पंजीकरण सेवाओं, एसएमएस अलर्ट, बैंक सेवाओं इत्यादि जैसी सुविधा सेवाएं।</p> <p>निटिंग एवं निटवियर योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल।</p> <p>निटिंग एवं निटवियर इकाइयों के लाभ के लिए योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों के बारे में सूचना का प्रचार करना।</p> <p>निटिंग एवं निटवियर इकाइयों को क्लस्टर स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों के विपणन के लिए मंच प्रदान करना।</p> <p>इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में निटिंग एवं निटवियर योजनाओं का प्रचार।</p>

उपरोक्त सभी योजनाओं का कार्यान्वयन वस्त्र आयुक्त द्वारा अपने कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पीएससी तथा किसी अन्य संगठन/एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।

उपर्युक्त सभी संघटक के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

II. निटिंग एवं निटवियर क्लस्टरों में नए सेवा केन्द्रों की स्थापना।

1. उद्देश्य

भारत सरकार निटिंग एवं निटवियर क्लस्टरों में परीक्षण प्रशिक्षण, नमूना विकास, परामर्शी सेवा, समस्या निवारण, सुविधा सेवाएं प्रदान करने के लिए नए निटिंग एवं निटवियर सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

2. निटिंग सेवा केन्द्रों (केएससी) की स्थापना

(क) प्रस्ताविक केएससी की स्थापना सरकारी-नैरसरकारी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति के आधार पर की जाएगी।

(ख) निटिंग एवं निटवियर उद्योग/स्टेक धारक सेवा केन्द्रों के संचालन के लिए एक संघ गठित करेंगे जिसे निटिंग एवं निटवियर सेवा संघ कहा जाएगा। निटिंग एवं निटवियर उद्योग/संघ नए निटिंग सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि एवं भवन की व्यवस्था करेंगे तथा उनका प्रबंधन करेंगे।

(ग) नमूना जांच के मामले में पहले आओ पहले जाओ के नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा यह प्रोद्योगिकी द्वारा संचालित किया जाएगा। निर्यात स्वीकृत के लिए नमूना की तत्काल जांच रिपोर्ट के मामले में अतिरिक्त 'एक्सप्रेस प्रभार' वसूल किया जाएगा।

(घ) केएससी के संचालन के लिए आवर्ती व्यय, स्टैकधारकों/उद्योग संघों द्वारा वहन किया जाएगा।

(ङ) वे सेवा केन्द्रों में विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रयोक्ता प्रभार निर्धारित करने के स्वतंत्र होंगे, तथापि संघों द्वारा निर्धारित प्रयोक्ता प्रभार इस संबंध में वस्त्र आयुक्त/वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के अध्यधीन होगा ताकि अपेक्षाकृत छोटे एवं वित्तीय रूप से कमजोर इकाइयों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

3. वित्तीय सहायता

केएससी के लिए प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित जांच उपस्करों एवं मशीनरी की खरीद के लिए 200 लाख रुपए प्रति केन्द्र तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के लिए जांच उपस्करों एवं मशीनरी की संकेतक सूची अनुबंध क-1 पर दी गई है। तथापि, कलस्टर्स के स्टैकधारक प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित जांच उपस्करों एवं मशीनरी का निर्धारण अपनी आवश्यकता के अनुसार 200 लाख रुपए की समग्र सीमा के भीतर करेंगे। केएससी के लिए अपेक्षित किसी अतिरिक्त उपस्कर की खरीद, स्टैकधारक द्वारा स्वयं अपनी लागत पर की जाएगी।

4. केएससी की निगरानी

(क) संघ द्वारा स्थापित केएससी, वस्त्र आयुक्त के पर्यवेक्षण और निरीक्षण/लेखा-परीक्षण के अध्यधीन होंगे

(ख) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, निटिंग एवं निटवियर केन्द्र के कार्यकरण का पर्यवेक्षण एवं मॉनीटर करेगा।

5. दुरुपयोग के प्रति सुरक्षा उपाय

(क) पीएसी/वस्त्र आयुक्त/वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार निर्धारित अवधि के अंदर वित्तीय सहायता का उपयोग न करने/ दुरुपयोग करने तथा केएससी का गठन पूरा करने में विलंब होने के मामले में जारी की गई धनराशि, कार्यान्वयन एजेंसी से राशि जारी करने की तारीख से राशि की वापसी की तारीख तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण व्याज सहित वसूल की जाएगी।

(ख) परियोजना अनुमोदन समिति (पावरटेक्स इण्डिया के तहत) के निर्णय/निर्देश अंतिम होंगे।

6. शिकायत निवारण

इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी शिकायतें वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत की जाएंगी जो इन शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

निहार रंजन दाश, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क1

निटवियर सेवा केन्द्र की स्थापना करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों तथा इनके लागत की अनुमानित सूची

क. परीक्षण प्रयोगशाला:

(i) भौतिक परीक्षण

क्रम. संख्या	मशीन का नाम	संख्या	अनुमानित दर (रुपए)	कुल राशि (रुपए)
1.	स्वचालित रैप रील	1	35,000/-	35,000/-
2.	इलेक्ट्रॉनिक एनालिटिकल बैलेस	1	1,25,000/-	1,25,000/-

3.	इलेक्ट्रॉनिक ली स्ट्रेंथ टेस्टर	1	2,00,000/-	2,00,000/-
4.	इलेक्ट्रॉनिक ट्विस्ट टेस्टर	1	1,00,000/-	1,00,000/-
5.	सिंगल यार्न स्ट्रेंथ टेस्टर (इलेक्ट्रॉनिक टाइप)	1	42,00,000/-	42,00,000/-
6.	ग्रे स्केल के साथ लॉन्डरो मीटर	1	35,000/-	35,000/-
7.	ग्रे स्केल के साथ क्रॉक मीटर	1	25,000/-	25,000/-
8.	पर्सपीरोमीटर	1	20,000/-	20,000/-
9.	एयर कंडीशनर (1.5 टन)	1	35,000/-	35,000/-
10.	प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप	1	3,00,000/-	3,00,000/-
11.	यार्न इवेन्नेश टेस्टर यूटी-5	1	80,00,000/-	80,00,000/-
कुल				1,30,75,000/- रुपए

(ii) फैब्रिक एवं रसायन परीक्षण मशीनें एवं उपकरण

क्र. संख्या	मशीन का नाम	संख्या	अनुमानित दर (रुपए)
1.	बीसली बैलेंस	1	10,000/-
2.	फैब्रिक स्ट्रेंथ टेस्टर	1	3,50,000/-
3.	फैब्रिक सैंपल कटिंग मशीन	1	25,000/-
4.	यूवी कैबिनेट	1	30,000/-
5.	क्रीस रिकवरी टेस्टर	1	10,000/-
6.	टम्बल ड्रायर	1	80,000/-
7.	वेट एंड ड्राई फास्टनेस टेस्टिंग मशीनें	1	40,000/-
8.	कंप्यूटराइज्ड कलर मैचिंग यूनिट	1	2,50,000/-
9.	अब्रेशन टेस्टर	1	5,00,000/-
कुल			12,95,000/- रुपए

ख. निटवियर के निर्माण पर प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास

अपेक्षित मशीनों और उनकी अनुमानित लागत की सूची:

	मशीन की किस्म	मात्रा	अनुमानित लागत
1.	क्लच मोटर के साथ सिंगल निडल लॉक स्टिच	25	6,87,500/-
2.	डबल निडल लॉक स्टिच	1	70,000/-

3.	बटन होल	1	2,50,000/-
4.	बटन स्विच	1	85,000/-
5.	ओवर लॉक	1	85,000/-
6.	आर्म मशीन की फीड	1	1,70,000/-
7.	कंप्यूटर कंट्रोल के साथ लॉक स्विच	1	70,000/-
8.	पैटर्न कटिंग टेबल (2'6"×6'×6')	1	35,000/-
9.	कटिंग मशीन (स्ट्रेट नाइफ)	1	80,000/-
10.	कटिंग मशीन (राउंड नाइफ)	1	70,000/-
11.	अटैचमेंट और टूल किट	1	60,000/-
12.	प्रेसिंग टेबल एंड आयरन	1	13,000/-
13.	फ्यूसिंग मशीन	1	30,000/-
14.	आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (हार्डवेयर और साफ्टवेयर सिस्टम)	कंप्यूटर, प्रिंटर एवं लैन कनेक्शन	3,50,000/-
15.	फर्नीचर आदि	-	1,50,000/-
16.	गारमेंट साफ्टवेयर (सीएडी)	4	4,00,000/-
कुल			26,05,500/-

ग. फैब्रिक एम्ब्रायडरी एवं निटिंग प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास

	मशीन की किस्म	मात्रा	अनुमानित दर (रु.)	अनुमानित लागत
1.	क्रम के साथ कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रायडरी मशीन (मल्टी हेडेड)	1	15,00,000/-	15,00,000/-
2.	आईटी अवसंरचना (हार्डवेयर एवं सीएडी सिस्टम)	6 कंप्यूटर, प्रिंटर एवं सीएडी साफ्टवेयर	3,00,000/-	3,00,000/-
3.	सिंगल जर्सी निटिंग मशीन	1	50,000/-	50,000/-
4.	ऑटो स्ट्रीपर के साथ सिंगल जर्सी निटिंग मशीन	1	80,000/-	80,000/-
5.	रिब मशीन	1	50,000/-	50,000/-
6.	क्लर/कफ मशीन	1	50,000/-	50,000/-
7.	फर्नीचर आदि		-	1,00,000/-
कुल				21,30,000/-

ड अन्य

क्र. संख्या	मशीन का नाम	संख्या	दर (रुपए)	कुल राशि (रुपए)
1.	पुस्तकालय एवं बैठक कक्ष	--	--	50,000/-
2.	स्क्रीन के साथ एलसीडी प्रोजेक्टर	01	1,00,000/-	1,00,000/-
3.	डीजी सेट 15 केवीए	1	2,00,000/-	2,00,000/-
4.	फर्नीचर एवं फिक्सर	--	--	1,00,000/-
5.	फैक्स	1	30,000/-	30,000/-
6.	यूपीएस	1	3,00,000/-	3,00,000/-
कुल				7,80,000

यह सूची संपूर्ण नहीं है, यह केवल उदाहरण स्वरूप है। कलस्टर की आवश्यकता अनुसार किंहीं अन्य मशीनों/उपकरणों का निर्णय लिया जाएगा।

II. टीआरए/ईपीसी आदि द्वारा संचालित मौजूदा विद्युत करघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन**1) उद्देश्य**

भारत सरकार निटिंग और निटवियरके उद्योग के विकास के लिए प्रशिक्षण/परीक्षण के लिए मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) (अथवा) ईपीसी (अथवा) किसी अन्य वस्त्र उद्योग संघों द्वारा संचालित मौजूदा विद्युतकरघा सेवा केंद्रों/संस्थाओं को व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

2) वित्तीय सहायता

क) ऐसे केंद्रों/संस्थाओं के सुदृढीकरण/आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा **20 लाख रुपए प्रति केंद्र** तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ख) नए निटवियरसेवा केंद्रों (केएससी) जो पीपीपी मॉडल पर कार्य करेंगे, के अनुभव के आधार पर मौजूदा विद्युत सेवा केंद्रों (पीएससी) को विद्युतकरघा एवं निटिंग सेवा केंद्र (केएससी) जो पीपीपी मॉडल पर प्रचालित किए जाते हैं, में परिवर्तित किए जाने की संभावना तलाशी जाएगी।

3) दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय

क) पीएससी/वस्त्र आयुक्त/वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित निर्धारित अवधि के भीतर केएससी की स्थापना को पूरा करने में विलंब होने की स्थिति में जारी की गई निधियों की वसूली राशि जारी करने की तारीख से उसे लौटाने की तारीख तक प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के साथ क्रियान्वयन एजेंसी (आईए) से की जाएगी।

ख) परियोजना अनुमोदन समिति (पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत) के निर्णय/निदेश अंतिम हैं।

4) शिकायत का निवारण

योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शिकायतें वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत की जाएंगी जो शिकायत का निवारण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

III. समूह वर्कशेड योजना**1.0 उद्देश्य**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा अथवा नए कलस्टरों में आधुनिक निटिंग एवं निटवियर मशीनों की स्थापना के लिए समूह वर्कशेडों की स्थापना करना है जो व्यापार करने के लिए अपेक्षित अर्थव्यवस्था का विस्तार करेगी और कलस्टर में निटिंग और

निटवियर इकाइयों को संगठित करेगी और अधिक स्थान, कार्य के वातावरण के संबंध में कार्य की स्थितियों में सुधार करेगी, विश्व बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए उनकी कार्य दक्षता में सुधार लाएगी।

2.0 प्रचालन की अवधि

समूह वर्कशेड योजना दिनांक 01.07.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि तक प्रचालनशील रहेगी।

3.0 योजना का कार्यक्षेत्र

इस योजना के अंतर्गत वर्कशेडों के निर्माण में आधुनिक निटिंग और निटवियर क्षेत्र की मशीन की स्थापना के लिए अपेक्षित स्थान, एयरकमप्रेसर, फैब्रिक चेकिंग मशीन एवं नमूना प्रदर्शनी कक्ष तथा कामगारों के लिए डोरमेटरी का निर्माण जैसी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं।

3.1 निटिंग इकाइयों के लिए पात्र क्षेत्र

क्र.संख्या	पात्र मशीनें	प्रति मशीन अधिकतम पात्र क्षेत्र
निटिंग मशीनें		
1.	सॉक्स निटिंग मशीन एवं फ्लैट कॉलर निटिंग	250 वर्ग फुट
2.	सर्कुलर निटिंग मशीन	600 वर्ग फुट
3.	ऑटो स्ट्रीपर (ओपन विड्थ टाइप)	1200 वर्ग फुट
4.	जैकार्ड के साथ हाई स्पीड निटिंग मशीन	1200 वर्ग फुट

उपर्युक्त क्षेत्र में निटिंग मशीन के कार्य के लिए आवश्यकता, निटिंग के लिए कच्ची सामग्री भंडारण, ग्रे फैब्रिक भंडारण, स्टोर और कलपुर्जा, ग्रे फैब्रिक चेकिंग/फोल्डिंग और पैकिंग तथा प्रशासन/उपयोगिताएं/कामगार सुविधाएं आदि शामिल हैं। तथापि लाभार्थी अपने निजी अंशदान के साथ अपेक्षाकृत बड़े आकार के क्षेत्र रख सकते हैं।

3.2 निटवियर इकाइयों के लिए पात्र क्षेत्र

क्र.संख्या	पात्र मशीनें	प्रति मशीन पात्र क्षेत्र
निटवियर मशीनें		
1.	स्टिचिंग मशीन	100 वर्ग फुट

उपर्युक्त क्षेत्र में निटवियर स्टिचिंग मशीन के कार्य के लिए आवश्यकता, फैब्रिक भंडारण, फैब्रिक कटिंग सेक्शन, गारमेंट चेकिंग और पैकिंग सेक्शन, स्टोर और प्रशासन/उपयोगिताएं/कामगार सुविधाएं आदि शामिल हैं। तथापि लाभार्थी अपने निजी अंशदान के साथ अपेक्षाकृत बड़े आकार के क्षेत्र रख सकते हैं।

3.3 प्रति निटिंग और निटवियर स्टिचिंग मशीन न्यूनतम 1.25 व्यक्तियों के आवास के लिए कामगारों के लिए डोरमेटरी के निर्माण के लिए अतिरिक्त सब्सिडी जिसमें पर्याप्त स्वच्छता शौचालय और स्नानागृह (स्टोर रूम के साथ रसोई और विकल्प के रूप में डाइनिंग हॉल को भी शामिल किया जा सकता है) शामिल हैं, 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान की जाएगी।

3.4 जिन लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है वे वस्त्र मंत्रालय की किसी अन्य योजना अर्थात् एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के अंतर्गत किसी अवसंरचना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगी। तथापि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई परियोजना का लाभ उठा सकते हैं।

4.0 पात्रता के मानदंड

- 4.1 पात्र लाभार्थी के अंतर्गत निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाई (अथवा) निटिंग और निटवियर क्षेत्र एवं संबद्ध उद्योग से जुड़ उद्यमी, पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसाइटी (अथवा) कोई नया उद्यमी, व्यक्तिगत रूप से (अथवा) समूह में शामिल होगा।
- 4.2 इस समूह में पृथक वैध इकाई वाले कम से कम 4 उद्यमी होंगे। वर्कशेड में कम से कम सभी प्रकार की 24 निटिंग मशीन (अथवा) 8 ऑटो स्ट्रिपर (ओपन विड्थ टाइप) निटिंग मशीन (अथवा) जैकार्ड के साथ हाई स्पीड वाली 4 निटिंग मशीनों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 4 निटिंग मशीन (अथवा) 2 ऑटो स्ट्रिपर (ओपन विड्थ टाइप) निटिंग मशीन (अथवा) जैकार्ड के साथ हाई स्पीड वाली 1 निटिंग मशीनों की स्थापना करनी चाहिए।
- 4.3 इस समूह में पृथक वैध इकाई वाले कम से कम 4 उद्यमी होंगे। वर्कशेड में सभी प्रकार की कम से कम 200 स्टिचिंग मशीनों की स्थापना की जानी है। प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 50 स्टिचिंग मशीन की स्थापना करनी चाहिए।
- 4.4 समूह वर्कशेड में निटिंग और निटवियर स्टिचिंग मशीनों का संयोजन होने की स्थिति में मशीनों की यथा अनुपात संख्या की अनुमति दी जाएगी।
- 4.5 समूह के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। तथापि जहां पर्याप्त लाभार्थी उपलब्ध हैं वहां समूह में एक परिवार के एक प्रतिनिधि को ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता है।
- 4.6 'निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाई' में निटिंग मशीनें और निटवियर स्टिचिंग मशीन, एयर कम्प्रेसर, फैब्रिक चेकिंग/कटिंग मशीनें एवं नमूना प्रदर्शन कक्ष जैसी सामान्य सुविधाएं और डोरमेटरी का निर्माण शामिल होगा।
- 4.7 इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केवल एटप्स के अनुकूल मशीनों की ही स्थापना करने के लिए अनुमति दी जाएगी। तथापि टप्स सब्सिडी का पूर्व अनुमोदन पूर्व-शर्त नहीं हो सकता है।
- 4.8 इस योजना में एक परियोजना के अंतर्गत 300 निटिंग मशीनों और 2500 निटवियर स्टिचिंग मशीनों से अधिक की परिकल्पना नहीं की गई है।

5.0 भूमि की खरीद एवं स्वीकृति

- 5.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की स्थापना करने के लिए एक कार्यपालक एजेंसी (ईए के रूप में संदर्भित) का गठन किया जाएगा। तथापि ईए को भारत सरकार की सब्सिडी के लिए लाभार्थी के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
- 5.2 ईए के अंतर्गत राज्य सरकार (अथवा) इसकी एजेंसी, अथवा एक पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसाइटी (अथवा) यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित एक कंपनी, अथवा निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों के समूह (न्यूनतम 4 लाभार्थी) अथवा स्थानीय निटिंग और निटवियर क्षेत्र तथा संबद्ध औद्योगिक संघ द्वारा यथा संशोधित सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी शामिल होगी।
- 5.3 परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले ईए के पास स्वयं की/लीज पर अपेक्षित भूमि होनी चाहिए। यदि ईए द्वारा भूमि लीज आधार पर ली गई हो तो इसके लीज की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए और ईए परियोजना प्रस्ताव के साथ पंजीकृत लीज डीड प्रस्तुत करेगा।
- 5.4 प्रस्तावित भूमि गैर-कृषि औद्योगिक भूमि होनी चाहिए और इसमें अनिवार्य रूप से संपर्क मार्ग होना चाहिए।
- 5.5 ईए के पास सरकारी प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित ले आउट और बिल्डिंग प्लान होना चाहिए।

6.0 प्रचालनात्मक दिशानिर्देश:

- 6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की स्थापना के लिए एक कार्यपालक एजेंसी (ईए के रूप में संदर्भित) होगी जिसमें राज्य सरकार (अथवा) इसकी एजेंसी, अथवा एक पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसाइटी (अथवा) यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित एक कंपनी, अथवा निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों के समूह (न्यूनतम 4 लाभार्थी) अथवा स्थानीय निटिंग और निटवियर क्षेत्र तथा संबद्ध औद्योगिक संघ द्वारा यथा संशोधित सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 अंतर्गत स्थापित कोई कंपनी शामिल होगी।

6.2 ईए मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ अनुबंध-1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार और अनुबंध-11 में संगलन सूची में सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा और इसे पीडीसी की अग्रिम प्रति के साथ वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई में विद्युतकरघा विकास सेल (पीडीसी) को इसे प्रस्तुत करेगा। वस्त्र आयुक्त का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इस आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को अपनी सिफारिश अथवा अन्यथा के साथ प्रस्ताव अग्रेषित करेगा। डीपीआर में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित ब्यौरे होने चाहिए :

- परियोजना का कार्यकारी सार
- ईए का स्वरूप: क्या सरकारी एजेंसी अथवा कोऑपरेटिव सोसाइटी अथवा निटिंग एवं निटवियर इकाइयों/स्थानीय निटिंग एवं निटवियरसंघों के समूह द्वारा स्थापित कोई कंपनी।
- भूमि के स्थान, स्वामित्व का स्वरूप (स्वयं/लीजयुक्त) और उसकी लागत का विवरण।
- वर्कशेड सहित लाभार्थियों और प्रत्येक लाभार्थी द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित निटिंग एवं निटवियर मशीनों का विवरण।
- घटक-वार परियोजना की लागत
- ईए की हिस्सेदारी को दर्शाते हुए परियोजना की वित्त पोषण की पद्धति, केंद्र सरकार और अन्य तथा ऋण
- पीईआरटी/सीपीएम के साथ माह-वार योजना को दर्शाते हुए निर्माण का कार्यक्रम
- शेडों के स्थान, सड़क/जलापूर्ति/विद्युत/नाली और अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी अवसंरचना को दर्शाते हुए परियोजना के क्षेत्र का ले-आउट

6.3 इस योजना के अंतर्गत भवन के निर्माण की लागत का अनुमान लगाने के लिए आधार के रूप में उस राज्य में सीपीडब्ल्यूडी की दरों की सूची का उपयोग किया जाएगा।

6.4 लाभार्थी (यों) को **वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-111)** के अनुसार एक लिखित वचन पत्र देना चाहिए।

6.5 सब्सिडी प्राप्त करने वाली निटिंग एवं निटवियर इकाइयों को सब्सिडी की अंतिम किस्त का वितरण किए जाने की तारीख से उसी स्वामित्व के अंतर्गत न्यूनतम 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के लिए काम करना चाहिए।

7.0 **परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी)**

इस योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाएं परियोजना अनुमोदन समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जिनमें

i) भारत सरकार की हिस्सेदारी/सहायता 2.00 करोड़ रुपए से अधिक है

अध्यक्ष	- सचिव (वस्त्र)
सदस्य	- अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
सदस्य	- संयुक्त सचिव (विद्युतकरघा)
सदस्य	- नीति आयोग का प्रतिनिधि
सदस्य सचिव	- वस्त्र आयुक्त

ii) भारत सरकार की हिस्सेदारी/सहायता 2.00 करोड़ रुपए से कम है

अध्यक्ष	- वस्त्र आयुक्त
सदस्य	- संयुक्त सचिव (विद्युतकरघा)
सदस्य	- आईएफडब्ल्यू का प्रतिनिधि
सदस्य सचिव	- अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त/निदेशक

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा/आकलन करने के लिए परियोजना अनुमोदन समिति मासिक रूप में किंतु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक कर सकती है। पीएसी 90 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच कर सकती है।

- 7.1 ईए किसी भी अनुसूचित बैंक में एक एस्क्रो खाता खोलेंगे और जीडब्ल्यूएस के लिए सभी भुगतान एस्करो खाते के माध्यम से किए जाएंगे, जिसका संचालन संयुक्त रूप से ईए के एक सदस्य तथा वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। एस्करो खाता खोले जाने के बाद ईए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार खाते का विवरण विद्युतकरघा विकास प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेगा।
- 7.2 पीएसी द्वारा परियोजना को अनुमोदन और एस्करो खाता खोले जाने संबंधी सूचना की प्राप्ति के उपरांत लाभार्थी निर्माण कार्य शुरू करेगा। शुरूआती 30% अग्रिम राशि केवल तभी प्रदान की जाएगी जब भूमि को पहले चार्ज अथवा दूसरे चार्ज के रूप में भारत सरकार के पास गिरवी रखा गया हो। यदि भूमि का गिरवी न रखा गया हो तो भारत सरकार के कुल हिस्से की शुरूआती 30% राशि को समतुल्य व्यय किए जाने पर जारी किया जाएगा।
- 7.3 ईए, वस्त्र आयुक्त को सब्सिडी जारी करने के लिए दावा प्रस्तुत करेगा।
- 7.4 परियोजना के स्वरूप में किसी परिवर्तन/संशोधन के लिए पीएसी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

8.0 स्थानीय स्तर पर निगरानी समिति (एलएलएमसी):

प्रत्येक केंद्र के लिए स्थानीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा जिसमें वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तथा स्थानीय जिला उद्योग केंद्रों के एक अधिकारी, स्थानीय निटिंग एवं निटवियर संघों और/अथवा संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। पात्र सब्सिडी को वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-IV) के अनुसार एलएलएमसी की रिपोर्ट का वास्तविक सत्यापन प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया जाएगा।

9.0 वित्तीय सहायता एवं वित्त पोषण की प्रक्रिया

- 9.1 इस योजना के अंतर्गत निर्माण के लिए सब्सिडी निम्नानुसार होगी:

सामान्य श्रेणी: अधिकतम 400 रुपए प्रति वर्ग फुट की सीमा के अध्यक्षीन समूह वर्कशेड, डोरमिटरी/कामगारों के आवास के निर्माण की इकाई लागत का 40%

एससी श्रेणी: अधिकतम 750 रुपए प्रति वर्ग फुट की सीमा के अध्यक्षीन समूह वर्कशेड, डोरमिटरी/कामगारों के आवास के निर्माण की इकाई लागत का 75%

एसटी श्रेणी: अधिकतम 900 रुपए प्रति वर्ग फुट की सीमा के अध्यक्षीन समूह वर्कशेड, डोरमिटरी/कामगारों के आवास के निर्माण की इकाई लागत का 90%

- 9.2 प्रति लाभार्थी अधिकतम अनुमेय सब्सिडी 22.00 लाख रुपए तक सीमित होगी।

- 9.3 मिश्रित श्रेणी वाले समूहों के मामले में सब्सिडी की निम्न दर को अपनाया जाएगा।

10.0 सब्सिडी को जारी करना

लाभार्थियों को भारत सरकार का हिस्सा जारी करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का अनुसरण किया जाएगा:

- 10.1 पीएसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन तथा सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ अनुबंध-V में निर्धारित प्रपत्र में पीएसी द्वारा परियोजना की स्वीकृति की तिथि से 90 दिनों के भीतर ईए द्वारा दावा प्रस्तुत करने के उपरांत भारत सरकार के कुल हिस्से की 30% राशि को अग्रिम के तौर पर जारी कर दिया जाएगा बशर्ते कि भूमि को भारत सरकार के पास पहले चार्ज तथा दूसरे चार्ज के रूप में गिरवी रखा गया हो। अन्यथा भारत सरकार की सब्सिडी की 30% की पहली किस्त ईए द्वारा सरकारी वास्तुकार द्वारा अनुमोदित निर्माण के लिए समतुल्य का व्यय किए जाने के उपरांत जारी की जाएगी। एलएलएमसी की रिपोर्ट को वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- 10.2 भारत सरकार के कुल हिस्से के 30% की दूसरी किस्त को पहली किस्त के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) तथा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी वास्तुकार द्वारा अनुमोदित समतुल्य व्यय को प्रस्तुत किए जाने और स्वीकृति की तिथि के 180 दिन के

भीतर **अनुबंध-VI** में निर्धारित प्रपत्र में उल्लिखित दस्तावेजों सहित दावे को प्रस्तुत किए जाने के उपरांत जारी किया जाएगा। एलएलएमसी की रिपोर्ट को वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

10.3 भारत सरकार के कुल हिस्से के 20% की तीसरी किस्त को सरकार अनुमोदित एक वास्तुकार द्वारा अनुमोदित निर्माण के लिए ईए द्वारा किए गए समतुल्य व्यय की प्रति तथा **अनुबंध-VII** पर निर्धारित प्रपत्र में यथा सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ स्वीकृति की तिथि से 270 दिनों के भीतर दावे की प्रस्तुति करने के उपरांत समूह वर्कशेड का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद जारी किया जाएगा। एलएलएमसी की रिपोर्ट को वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

10.4 भारत सरकार की सब्सिडी के शेष 20% के हिस्से को ईए द्वारा **अनुबंध-VIII** पर निर्धारित प्रपत्र में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किए जाने के उपरांत जारी किया जाएगा। पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित मशीनों के सफल संस्थापन तथा संतोषजनक कार्यचालन संबंधी एलएलएमसी की रिपोर्ट को वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को दावा प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

10.5 यदि भूमि को गिरवी नहीं रखा गया हो तो कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा परंतु सब्सिडी की यथा अनुपात आधार पर प्रतिपूर्ति 30:30:20:20 के अनुपात में की जाएगी।

11.0 **निगरानी एवं समीक्षा:**

11.1 योजना के क्रियान्वयन की निगरानी तथा लाभों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र आयुक्त लाभार्थियों से यथा आवश्यक दस्तावेजों/सूचना को आमंत्रण करेगा और आवश्यकता पड़ने पर इकाई(यों) का निरीक्षण करेगा।

11.2 पात्र इकाइयों द्वारा वस्त्र आयुक्त द्वारा मंगाई गई सूचना/दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने पर विफल रहने पर समूह वर्कशेड योजना के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और परियोजना के अनुमोदन की समाप्ति, अथवा प्राप्त किए गए लाभों की तत्काल वसूली और समय पूर्व समाप्ति की कार्रवाई सहित यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

12.0 **दुरुपयोग से सुरक्षा:**

12.1 जिस भूमि पर समूह वर्कशेड की स्थापना प्रस्तावित है उसका ईए के पक्ष में स्पष्ट मालिकाना हक होना चाहिए तथा यथा लागू स्थानीय निकायों, नगरपालिका प्राधिकारी, राज्य प्रशासनिक एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।

12.2 ईए को चौथी और अंतिम किस्त को जारी की जाने की तिथि से कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि तक कार्य करना होगा।

12.3 लाभार्थियों द्वारा त्रुटि से बचने के उद्देश्य से योजना के अंतर्गत अनुमोदित सभी मामलों में परिसंपत्तियों को पहले अथवा दूसरे चार्ज के रूप में गिरवी रखा जाएगा और ऐसा न होने पर लाभार्थी निधियों को जारी किए जाने से पूर्व प्रपत्र (अनुबंध-IX) के अनुसार जमानती बंध-पत्र प्रस्तुत करेगा।

12.4 सब्सिडी के गैर-उपयोग/दुरुपयोग तथा परियोजना को पूरा होने में 18 माह से अधिक के विलंब के मामलों में पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित जारी निधियों को निष्पादन एजेंसी से राशि को जारी किए जाने की तिथि से लेकर वसूली की तिथि तक 10% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज के साथ वसूला जाएगा।

12.5 पहली किस्त जारी किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि की लागत ईए को जारी की जा रही राशि (पहली किस्त) से अधिक है।

12.6 सरकारी सब्सिडी का उपयोग योजना के पैरा 7.1 में दर्शाए गए एक एस्क्रो खाते के माध्यम से किया जाएगा।

12.7 परियोजना अनुमोदन समिति (पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत) का निर्णय/निर्देश अंतिम होगा।

13.0 **परियोजना को पूरा करने की समय सीमा:**

13.1 पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना को हर प्रकार से अनुमोदन के प्रेषण की तिथि से दो वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।

- 13.2 परियोजना पूरा न होने के पर्याप्त कारण हैं, तो ईए के अनुरोध के आधार पर पीएसी समय-सीमा को दो वर्ष की अवधि के बाद एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, अन्यथा 10% का दंड लगाया जाएगा और इसे जारी की जाने वाली शेष सब्सिडी से समायोजित कर लिया जाएगा।

14. शिकायत का निवारण

योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों को वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा जो शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

अनुबंध-1

निर्दिष्ट एवं निटवियर क्षेत्र के लिए समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान किए जाने के लिए आवेदन

(क) सामान्य विवरण

1.	निष्पादन एजेंसी का नाम	
	पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय का पता	
	वर्कशेड का स्थान	
	फोन नं.	
	फैक्स	
	वेबसाइट	
	ईमेल	
2.	निष्पादन एजेंसी की प्रकृति (राज्य सरकार और इसकी एजेंसी/ पंजीकृत को-ऑपरेटिव सोसाइटी / प्राइवेट लि. कंपनी / सार्वजनिक लि. कंपनी / एलएलपी/ निटवियर संघ)	
3.	पंजीकरण संख्या एवं तिथि (प्रति संलग्न)	

(ख) परियोजना लागत एवं वित्त पोषण का विवरण

क्र.सं.	मद	वित्त पोषण (लाख रुपए)				
		निजी अंशदान	केंद्र सरकार की सब्सिडी	राज्य सरकार की सब्सिडी	वित्तीय संस्थानों से ऋण	कुल
1.	भूमि					
2.	वर्कशेड					
3.	अवसंरचना					

	क) आंतरिक सड़क					
	ग) विद्युत आपूर्ति					
	घ) जल आपूर्ति					
	ङ) नाली					
	च) अन्य					
4.	निटिश मशीन					
5.	निटवियर मशीन					
6.	डोरमिटरी					
	कुल					

(ग) परियोजना का विवरण

1.	भूमि कुल क्षेत्र वर्ग फुट में स्वामित्व की प्रकृति:	निजी/लीज
2.	वर्कशेड (क) निटिंग मशीनों के लिए कुल शेडों की संख्या (ख) निटवियर मशीनों के लिए कुल शेडों की संख्या कुल शेडों की संख्या (क) + (ख) (ग) निटिंग मशीनों के शेड के लिए वर्ग फुट में कुल क्षेत्र (घ) निटवियर मशीनों के शेड के लिए वर्ग फुट में कुल क्षेत्र (ङ.) डोरमिटरी के लिए वर्गफुट के लिए क्षेत्र वर्ग फुट में कुल क्षेत्र (ग) + (घ) + (ङ) (च) प्रति वर्ग फुट निर्माण की प्रस्तावित लागत (रुपए में)	
3.	अवसंरचना (क) विद्युत आपूर्ति (लोड मेगा वाट में) (ख) जल आपूर्ति (कि.ली. में मात्रा) (ग) नालियां (लंबाई मीटर में) (घ) अन्य	
4.	प्रस्तावित निटिंग एवं निटवियर क्षेत्र की मशीनें (क) सोक्स निटिंग एवं फ्लैट कॉलर निटिंग मशीनें	

	(ख) सर्कुलर निटिंग मशीनें	
	(ग) ऑटो स्ट्रिपर की संख्या (ओपन विड्थ टाइप)	
	(घ) जैक्कार्ड सहित हाई स्पीड निटिंग मशीनें	
5.	(क) प्रोडक्ट प्रोफाइल	
	(ख) उत्पादन प्रति दिन (किग्रा/मीटर जो लागू हो)	
	(ग) प्रतिवर्ष कुल उत्पादन (किग्रा/मीटर जो लागू हो)	
	(घ) खरीदे जाने के लिए प्रस्तावित सिलाई एवं अन्य संबद्ध मशीनों की संख्या (निटवियर क्षेत्र)	(मशीनरी की सूची भी संलग्न करें)
	(ङ) उत्पादन प्रतिदिन	पीस की संख्या
	(च) कुल उत्पादन प्रतिवर्ष	पीस की संख्या
	(छ) मूल्य एवं प्रतिशतता के रूप में निर्यात	
	(ज) प्रतिवर्ष कुल कारोबार	लाख
	(झ) प्रतिवर्ष उत्पादन की लागत	लाख
	(ञ) कुल लाभ देयता	लाख
	(ट) रोजगार की संख्या	

(घ) लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी (इकाई) का नाम	लिंग	धर्म	सामाजिक श्रेणी	प्रस्तावित वर्कशेड का क्षेत्र वर्गफुट में	प्रस्तावित मशीनें		खरीदी जाने वाली मशीनरी की प्रस्तावित लागत (लाख रुपए में)
						मात्रा	प्रकार	
	कुल							

नोट:

- (क) यदि एक से अधिक लाभार्थी एक शेड में भागीदार हैं तो उनके नाम क्रम से लिखें और उनके सामने एक शेड को संयुक्त रूप से दर्शाएं
- (ख) कृपया लाभार्थी के लिंग का उल्लेख करें : पु-पुरुष, म-महिला
- (ग) कृपया लाभार्थी के धर्म का उल्लेख करें: ह-हिंदु, म-मुस्लिम, स-सिख, ज-जैन, ई-ईसाई, अ-अन्य
- (घ) कृपया लाभार्थी की सामाजिक श्रेणी का उल्लेख करें: एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य

(ङ) रखरखाव तथा ऋण पुनर्वादायगी के लिए लाभार्थियों के संभावित अंशदान का विवरण

क्र.सं.	संघटक	राशि (रुपए में)
1.	रखरखाव की लागत का व्यौरा/वर्ष	

	(क) वर्कशेड					
	(ख) अवसंरचना <ul style="list-style-type: none">➤ बिजली की आपूर्ति➤ पानीकी आपूर्ति➤ सड़कों एवं नालियों का रखरखाव					
	(ग) निगरानी					
	(घ) कुल लागत					
	(ङ) वर्कशेड का कुल क्षेत्र					
	(च) वर्कशेड क्षेत्र की प्रति वर्ष प्रति वर्ग फुट रखरखाव लागत					
2.	<u>ऋण पुनर्अदायगी</u> * क) लिया गया कुल ऋण ख) ब्याज सहित वार्षिक पुनर्भुगतान ग) लाभार्थी द्वारा वर्कशेड क्षेत्र के प्रति वर्ग फुट आधार पर किया जाने वाला वर्ष-वार वार्षिक भुगतान	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5

(च) रखरखाव तथा ऋण पुनर्जादायगी के लिए लाभार्थियों के संभावित अंशदान का विवरण

क्र.सं.	संघटक	राशि (रुपए में)
1.	रखरखाव की लागत का ब्यौरा/वर्ष	
	(क) वर्कशेड	
	(ख) अवसंरचना <ul style="list-style-type: none"> ➤ बिजली की आपूर्ति ➤ पानीकी आपूर्ति ➤ सड़कों एवं नालियों का रखरखाव 	
	(छ) निगरानी	
	(ज) कुल लागत	
	(झ) वर्कशेड का कुल क्षेत्र	

	(ज) वर्कशेड क्षेत्र की प्रति वर्ष प्रति वर्ग फुट रखरखाव लागत					
2.	<u>ऋण पुनर्जदायगी</u>	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
	* क) लिया गया कुल ऋण ख) ब्याज सहित वार्षिक पुनर्भुगतान ग) लाभार्थी द्वारा वर्कशेड क्षेत्र के प्रति वर्ग फुट आधार पर किया जाने वाला वर्ष-वार वार्षिक भुगतान					

* यह ऋण राशि ईए द्वारा वर्कशेड के निर्माण तथा सामान्य सुविधाओं/अवसंरचना आदि के विकास, यदि कोई हो, के लिए प्राप्त की गई है।

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए:

ईए अर्थात् मैसर्स के समूह वर्कशेड स्थल का को दौरा किया और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा स्वीकृति के लिए प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है/नीचे उल्लिखित कारणों की वजह से संस्तुति नहीं की जाती है।

कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,

अनुबंध-2

जिस किसी से संबंधित हो

हम, मैसर्स (ईए), कंपनी अधिनियम, 1956/एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी के अधोहस्ताक्षरी निदेशक, एतद्वारा यह कहते हैं कि भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई निटिंग एवं निट वियर क्षेत्र विकास योजना (विद्युतकरघा तथा निटिंग एवं निट वियर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना) के अंतर्गत समूह वर्कशेड योजना (जीडब्ल्यूएस) के तहत निर्मित में स्थित वर्ग फुट क्षेत्र के आकार वाले वर्कशेड का प्रयोग केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अनुरूप मशीनरी को संस्थापित करने के लिए ही प्रयोग किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त कंपनी जीडब्ल्यूएस के अंतर्गत कंपनी तथा अधोहस्ताक्षरी लाभार्थियों द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी को जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी।

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1		प्रबंध निदेशक	
2		निदेशक	
3		निदेशक	
4		निदेशक	

उपर्युक्त संकल्प को कंपनी द्वारा दिनांक को संपन्न हुई बैठक में पारित किया गया था और कंपनी के सभी निदेशक समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में इसकी जानकारी रखते हैं।

दिनांक:

नाम :

स्थान :

पदनाम:

ईए का नाम:

ईए की मुहर:

अनुबंध-3**पीएफएमएस के साथ एजेंसी बनाने के लिए एस्क्रो खाते का विवरण प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र**

(नोट: सभी जानकारी देना अनिवार्य है)

क्र.सं.	विवरण	
1.	एजेंसी का नाम (इकाई/ईए/एसपीवी का नाम)	
2.	ईए/एसपीवी की पंजीकरण संख्या	
3.	पंजीकरण की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	
4.	पंजीकरण प्राधिकारी	
5.	पंजीकरण राज्य	
6.	टिन नम्बर	
7.	टैन नम्बर	
8.	पैन नम्बर	
9.	यूनिट का पता	
10.	शहर	
11.	जिला	
12.	राज्य	
13.	पिन कोड	
14.	संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नं.	
15.	इकाई/ईए/एसपीवी का एस्क्रो खाता संख्या/	
16.	इकाई/ईए/एसपीवी की ईमेल आईडी	
17.	बैंक का नाम	
18.	ब्रांच का नाम और पता पिनकोड सहित	
19.	बैंक का सिटी कोड	

20.	बैंक का एमआईसीआर कोड	
21.	बैंक का आईएफएससी कोड	
22.	बैंक का ब्रांच कोड	

बैंक की मुहर सहित हस्ताक्षर

इकाई/ईए/एसपीवी की मुहर सहित हस्ताक्षर

अनुबंध-4

समूह वर्कशेड की स्थानीय स्तरीय निगरानी समिति (एलएलएमसी) का सूचना प्रपत्र

क्र.सं.	एलएलएमसी रिपोर्ट का विवरण	एलएलएमसी की सिफारिश
1	समूह वर्कशेड का नाम एवं पता	
2	एलएलएमसी की तिथि	
3	बैठक का स्थान	
4	एलएलएमसी का स्तर	
5	उपस्थित एलएलएमसी सदस्यों का नाम	
6	वर्कशेड की वर्तमान स्थिति	
7	निर्मित वर्कशेड का क्षेत्र	
8	अब तक हुई वित्तीय प्रगति	
9	सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र	
10	चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र	
11	अनुमोदित वर्कशेड का कुल क्षेत्र	
12	भारत सरकार की स्वीकृत सब्सिडी	
13	जारी की गई भारत सरकार की सब्सिडी	

14	पूर्ण किए गए वर्कशेड का वर्तमान क्षेत्र/निर्माण	
15	पूर्ण कार्य की प्रतिशतता	
16	प्रस्तावित मशीनरी का विवरण	
17	संस्थापित मशीनरी की संख्या	
18	सिफारिश की गई पात्र सब्सिडी	
19	तारीख एवं समय को दर्शाते हुए एलएलएमसी के सभी सदस्यों के फॉटो	
20	समग्र टिप्पणी	

एलएलएमसी सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुबंध-5

भारत सरकार की सब्सिडी की 30% की पहली किस्त को जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों सहित ईए के आवेदन का प्रपत्र (स्वीकृति की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना)

सेवा में

दिनांक-

प्रभारी अधिकारी,

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय,

हम एतद्वारा पावरटेक्स इंडिया की समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सब्सिडी की पहली किस्त को जारी करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। हम आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहे हैं।

1. भारत सरकार के हिस्से को अग्रिम तौर पर जारी करने के मामले में पहले चार्ज और दूसरे चार्ज पर भारत सरकार की भूमि का बंधक-पत्र
2. वर्कशेड के निर्माण के लिए किए गए व्यय के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र
3. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार द्वारा समतुल्य व्यय का प्रमाणपत्र।
4. कोई अन्य विवरण।

आपसे आवश्यक एलएलएमसी का शीघ्र सत्यापन करने का अनुरोध किया जाता है।

भवदीय,

(ईए का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-6

भारत सरकार की सब्सिडी की 30% की पहली किस्त को जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों सहित ईए के आवेदन का प्रपत्र (स्वीकृति की तिथि से 180 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना)

सेवा में

दिनांक:-

प्रभारी अधिकारी,

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय,

हम एतद्वारा पावरटेक्स इंडिया की समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सब्सिडी की पहली किस्त को जारी करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। हम आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहे हैं।

1. वर्कशेड के निर्माण के लिए किए गए व्यय के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र
2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार द्वारा समतुल्य व्यय का प्रमाणपत्र।
3. मशीनरी की खरीद के लिए निधियों हेतु गठबंधन के लिए प्रत्येक लाभार्थी/निष्पादन एजेंसी के लिए संयंत्र एवं मशीनरी को खरीदने हेतु आवधिक ऋण के लिए बैंक का स्वीकृति पत्र।
4. पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी)
5. कोई अन्य विवरण।

आपसे आवश्यक एलएलएमसी सत्यापन शीघ्र करने का अनुरोध है।

भवदीय,

(ईए का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-7

भारत सरकार की सब्सिडी की 20% की पहली किस्त को जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों सहित ईए के आवेदन का प्रपत्र (स्वीकृति की तिथि से 270 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना)

सेवा में

दिनांक:-

प्रभारी अधिकारी,

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय,

हम एतद्वारा पावरटेक्स इंडिया की समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सब्सिडी की पहली किस्त को जारी करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। हम आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहे हैं।

1. भारत सरकार के हिस्से को अग्रिम तौर पर जारी करने के मामले में पहले चार्ज और दूसरे चार्ज पर भारत सरकार की भूमि का बंधक-पत्र।
2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार द्वारा समतुल्य व्यय प्रमाण-पत्र तथा निर्माण पूर्णता प्रमाण-पत्र।
3. प्रत्येक लाभार्थी/निष्पादन एजेंसी द्वारा मशीनरी आपूर्तिकर्ता को जारी अग्रिम/टोकन मनी और संयंत्र एवं मशीनरी के लिए आदेश प्रस्तुत करने के दस्तावेज।

4. दूसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी)

5. कोई अन्य विवरण।

आपसे आवश्यक एलएलएमसी सत्यापन शीघ्र करने का अनुरोध है।

भवदीय,

(ईए का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-8

भारत सरकार की सब्सिडी की 20% की पहली किस्त को जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों सहित ईए के आवेदन का प्रपत्र (स्वीकृति की तिथि से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना)

सेवा में

दिनांक:-

प्रभारी अधिकारी,

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय,

हम एतद्वारा पावरटेक्स इंडिया की समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सब्सिडी की पहली किस्त को जारी करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। हम आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहे हैं।

1. संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद पर हुए व्यय के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र।
2. प्रत्येक लाभार्थी/ईए द्वारा मशीनरी की संस्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी के इनवॉइस।
3. तीसरी किस्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी)
4. कोई अन्य विवरण।

आपसे आवश्यक एलएलएमसी सत्यापन शीघ्र करने का अनुरोध है।

भवदीय,

(ईए का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध - 9

एक सौ रुपए के न्यायिक पेपर पर प्रतिभू बंधपत्र का नमूना

अनुदान निर्मुक्त किए जाने से पूर्व निष्पादित किया जाने वाला बांड

इसे प्रस्तुत किए जाने पर सभी को जानकारी हो कि हम, मैसर्स _____, एलएलपी अधिनियम/कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित एक कंपनी/ सरकार के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक सहकारी सोसायटी और जिसका पंजीकृत कार्यालय पर है (जिसे एतदपश्चात "बाध्यताधारी" कहा गया है), पूर्णतः और दृढ़ता से भारत के राष्ट्रपति (जिसे एतदपश्चात "सरकार" कहा गया है) के प्रति _____ रुपए (..... रुपए मात्र) के लिए

सरकार द्वारा मांग किए जाने पर और बिना किसी विलंब के भुगतान किए जाने हेतु स्वयं और अपने अग्रवर्तियों तथा समनुदेशियों को इसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बाध्य करते हैं।

जबकि बाध्यताधारी के अनुरोध पर, सरकार ने वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक _____ के स्वीकृति आदेश सं. _____ (एतदपश्चात् "स्वीकृति पत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुसार, जो इन दस्तावेजों का एक अभिन्न हिस्सा है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और अनुबंध-1 के रूप में चिह्नित की गई है, बाध्यताधारी के पक्ष में _____ पर कार्यशेड के निर्माण तथा निर्दिष्ट मशीनों के स्थापन के लिए रुपए _____ (_____ रुपए मात्र) का अनुदान देने के लिए सहमत हुआ, जिसमें से रुपए _____ (_____ रुपए मात्र) की राशि का भुगतान बाध्यताधारी को किया गया है (जिसकी प्राप्ति को बाध्यताधारी एतद्वारा स्वीकार करते हैं) जिसके लिए एतदपश्चात् समाविष्ट निबंधनों एवं रीति के अनुसार बाध्यताधारी को एक बाण्ड निष्पादित करना है और बाध्यताधारी ऐसा करने के लिए सहमत हुआ है।

अब उपर्युक्त लिखित बाध्यता की शर्तें ऐसी हैं कि यदि बाध्यताधारी स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का विधिवत तथा पूर्णतः पालन करता है, तो उपरोक्त लिखित बाण्ड या बाध्यता शून्य हो जाएगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अन्यथा, यह पूरी तरह से प्रभावी रहेगी। बाध्यताधारी, यदि कोई निर्दिष्ट है तो, लक्ष्य तिथियों के अनुसार अनुदान के नियम और शर्तों का पालन करेगा।

यह कि बाध्यताधारी अनुदान का अपवर्तन नहीं करेगा या किसी अन्य संस्था (संस्थाओं) या संगठन (संगठनों) से संबंधित योजना या कार्य के निष्पादन को नहीं सौंपेगा।

यह कि बाध्यताधारी इस समझौते में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का पालन करेगा और उसके बाण्ड की शर्तों का पालन करने में विफल होने या बाण्ड का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी तथा जमानती पृथक् रूप से और संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति को अनुदान की पूरी राशि 10% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापिस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि अनुदान का कुछ हिस्सा उस अवधि के समाप्त होने के बाद व्यय नहीं किया जाता है, जिसके भीतर उसे व्यय किया जाना था, तो 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, सरकार को उसके प्रतिदाय की तारीख तक प्रभारित किया जाएगा, जब तक कि इसे अग्रेनीत किए जाने पर सहमति न हो।

बाध्यताधारी इस पर सहमत होते हैं और सरकार को ऐसे सभी मौद्रिक या अन्य लाभों के मौद्रिक मूल्य का भुगतान / अभ्यर्पण करने के लिए सहमत होते हैं जो इसके अनधिकृत उपयोग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो/ या किए गए हो (जैसे कि परिसर को पर्याप्त या पर्याप्त से कम मूल्य पर किराए पर देना या संपत्ति हेतु अनुदान के वांछित उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग), उस भवन को जिसे मुख्यतः भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा स्वीकृत अनुदान से व्यापक रूप से निर्मित/अधिग्रहित किया गया था। जहां तक सरकार को अभ्यर्पण/भुगतान किए जाने वाले उपरोक्त वर्णित मौद्रिक मूल्य का संबंध है, परियोजना अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यताधारी पर बाध्यकारी होगा।

और यह भी साक्षीबद्ध होता है कि

i) क्या स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन हुआ है, के प्रश्न के संबंध में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम होगा और बाध्यताधारी पर बाध्यकारी होगा और;

ii) सरकार इन दावों पर देय स्टाम्प झूटी वहन करेगी।

के साक्ष्यांकन में, ये दस्तावेज ऊपर लिखित तिथि को बाध्यताधारी की ओर से बाध्यताधारी के शासी निकाय द्वारा उपरोक्त वर्णित दिनांक _____ के संकल्प संख्या _____ के अनुपालन में निष्पादित किए गए, जिसकी एक प्रति अनुबंध-2 के रूप में इसके साथ संलग्न है तथा यह नीचे दर्शाई गई तिथि को कृते राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से जमानतियों तथा _____ द्वारा किया गया :-

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

कृते एवं उनकी ओर से हस्ताक्षरित

(बाध्यताधारी का नाम)

1. गवाह के हस्ताक्षर

2. गवाह के हस्ताक्षर

नाम और पता

नाम और पता

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(स्वीकृत)

कृते और भारत के राष्ट्रपति की ओर से

पदनाम : _____

दिनांक : _____

समूह कार्यशेड योजना के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के लिए सार और अपेक्षित दस्तावेजों की जांच-सूची

चरण	उद्देश्य	आवश्यकता	अपेक्षित दस्तावेजों की जांच-सूची	दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का चरण
1.	कार्य शेड के निर्माण के लिए स्वीकृति	आवेदन वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यकारी एजेंसी)ईए (द्वारा प्रस्तुत किया जाए।	दिशा निर्देशों के अनुबंध-1 में आवेदन के साथ 1. परियोजना का कार्यकारी सारांश। 2. ईए की प्रकृति। 3. ईए के नाम पर भूमि का विक्रय/पट्टा विलेख। 4. गैर-कृषि भूमि प्रमाण पत्र। 5. स्वीकृत लेआउट योजना।	कार्य शेड निर्माण के लिए स्वीकृति लेने हेतु।
2.	वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में आवेदन अग्रेषित करना	आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मंजूरी के लिए सिफारिश के साथ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को अग्रेषित करना।	1. परियोजना का कार्यकारी सारांश। 2. ईए की प्रकृति। 3. ईए के नाम पर भूमि का विक्रय/पट्टा विलेख। 4. गैर-कृषि भूमि प्रमाण पत्र। 5. स्वीकृत लेआउट योजना। 6. स्थल के चित्र।	----

चरण	उद्देश्य	आवश्यकता	अपेक्षित दस्तावेजों की जांच-सूची	दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का चरण
3.	30% की पहली किस्त जारी करने का दावा।	1. ईए को मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के भीतर दावा करना होगा। 2. संबंधित आरओ को निर्माण के 30% के पूरा होने के बारे में सूचित करना होगा। 3. आरओ को एलएलएमसी के दौरे की तारीख से 10 दिनों के भीतर एलएलएमसी रिपोर्ट को पीडीसी को अग्रेषित करना होगा।	1. सविस्डी अग्रिम रूप से जारी करने के मामले में भारत सरकार को भूमि का बंधक विलेख। 2. वर्कशेड के निर्माण के लिए किए गए व्यय का सीए से प्रमाण पत्र। 3. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार से आनुपातिक व्यय का प्रमाण पत्र। 4. निर्माण की तस्वीरें।	एलएलएमसी दौरे के दौरान।
4.	30% की दूसरी किस्त जारी करने का दावा।	1. ईए को मंजूरी की तारीख से 180 दिनों के भीतर दावा करना होगा। 2. संबंधित आरओ को निर्माण के 60% के पूरा होने के बारे में सूचित करना होगा। 3. आरओ को एलएलएमसी के दौरे की तारीख से 10 दिनों के भीतर एलएलएमसी रिपोर्ट को पीडीसी को अग्रेषित करना होगा।	1. वर्कशेड के निर्माण के लिए किए गए व्यय का सीए से प्रमाण पत्र। 2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार से आनुपातिक व्यय का प्रमाण पत्र। 3. पहली किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र। 4. निर्माण की तस्वीरें। 5. प्रत्येक लाभार्थी/ईए के लिए संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए सावधि ऋण के लिए बैंक का स्वीकृति पत्र।	एलएलएमसी दौरे के दौरान।
5.	20% की तीसरी किस्त जारी करने का दावा।	1. ईए को मंजूरी की तारीख से 270 दिनों के भीतर दावा करना होगा। 2. संबंधित आरओ को निर्माण के 100% के पूरा होने के बारे में सूचित करना होगा। 3. आरओ को एलएलएमसी के दौरे की तारीख से 10 दिनों के भीतर एलएलएमसी रिपोर्ट को पीडीसी को अग्रेषित करना होगा।	1. वर्कशेड के निर्माण के लिए किए गए व्यय का सीए से प्रमाण पत्र। 2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार से आनुपातिक व्यय का प्रमाण पत्र। 3. भवन की तस्वीरें। 4. दूसरी किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र। 5. प्रत्येक लाभार्थी/ईए द्वारा लिए संयंत्र और मशीनरी हेतु दिए गए आर्डर के दस्तावेज और जारी किया गया अग्रिम/टोकन राशि।	एलएलएमसी दौरे के दौरान।
6.	20% की अंतिम किस्त जारी करने का दावा।	1. ईए को मंजूरी की तारीख से 2 वर्षों के भीतर दावा करना होगा। 2. संबंधित आरओ को संयंत्र तथा मशीनरी की स्थापना तथा	1. संयंत्र तथा मशीनरी पर किए गए व्यय का सीए से प्रमाण पत्र। 2. संयंत्र तथा मशीनरी के बीजकों को प्रस्तुत करना।	एलएलएमसी दौरे के दौरान।

चरण	उद्देश्य	आवश्यकता	अपेक्षित दस्तावेजों की जांच-सूची	दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का चरण
		<p>चालू होने के बारे में सूचित करना होगा।</p> <p>3. आरओ को एलएलएमसी के दौरे की तारीख से 10 दिनों के भीतर एलएलएमसी रिपोर्ट को पीडीसी को अग्रेषित करना होगा।</p>	<p>3. तीसरी किश्त का उपयोग प्रमाण-पत्र।</p> <p>4. संयंत्र तथा मशीनरी की स्थापना तथा चालू होने के बारे में सीई प्रमाण-पत्र।</p>	

V. यार्न बैंक योजना

1.0 पृष्ठभूमि

निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र में छोटी इकाइयों में उच्च दर के कारण खुले बाजार से थोक में यार्न खरीदने की क्षमता नहीं होती है। वे अपने दैनिक उपभोग के लिए यार्न के स्थानीय आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हैं। स्थानीय आपूर्तिकर्ता यार्न को उच्च दर पर बेचता है और मूल्य में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाता है। इसके कारण छोटी निटिंग और निटवियर वस्त्र की इकाइयों को उचित मूल्य पर यार्न नहीं मिल पा रहा है और वे अपने उत्पादन की योजना बनाने में असमर्थ हैं। अतः, निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र की इकाइयों को उचित दर पर यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यार्न बैंक स्थापित करना आवश्यक है। इस प्रकार का यार्न बैंक यार्न की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए छोटी निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र की इकाइयों की मदद करेगा।

निटिंग और निटवियर वस्त्र उद्योग के लिए सामान्य कार्यशील पूंजी चक्र में यार्न खरीद, प्रक्रियाधीन कार्य, ग्रे स्टेज पर तह और ग्रे बुने हुए कपड़े को नकदी/उधार आदि की विक्री शामिल है, और इस चक्र पूरा होने के लिए लगभग 2- 2 1/2 महीने लगते हैं। अतः, एक वर्ष में, एसपीवी से उनके योगदान सहित कम से कम **4 - 5 बार** स्थायी निधि के संचलन की प्रत्याशा की जाती है।

1.1 उद्देश्य

छोटी निटिंग और निटवियर वस्त्र इकाइयों को थोक मूल्य पर और बड़ी मात्रा में विचौलिए/स्थानीय आपूर्तिकर्ता के प्रभारों से बचाते हुए विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) / निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र इकाइयों के संघ को ब्याज मुक्त कोष उपलब्ध कराने के माध्यम से समर्थ बनाने हेतु।

2. प्रचालन की अवधि

पावरलूम और निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक योजना के अंतर्गत एक घटक के रूप में, यार्न बैंक योजना 01.07.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए प्रचालनशील रहेगी।

3. वित्तीय सहायता

सरकार एसपीवी/संघ को प्रति यार्न बैंक में अधिकतम **200 लाख रूपए** की ब्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान करेगी।

4. पात्रता मानदंड

क. विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) का गठन एक पंजीकृत सहकारी सोसाइटी, एक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी के रूप में और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित एक फर्म के रूप में किया जाएगा।

ख. एसपीवी के गठन के लिए न्यूनतम 11 सदस्यों की आवश्यकता होगी।

ग. एसपीवी के सदस्य निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र और इसकी संबद्ध उद्योग इकाई, सहकारी समितियों, निजी उद्यमी और निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन से संबद्ध होने चाहिए।

5. पूर्व-आवश्यकता

क. विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) यार्न बैंक की स्थापना के लिए आवेदन करने से पूर्व ऊपर 4(ए) में उल्लेख किए अनुसार पंजीकृत किया जाएगा।

ख. एसपीवी निम्नलिखित हेतु वचन देगा

i. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधि के बराबर अपनी स्वयं की निधि की व्यवस्था हेतु।

ii. स्थायी निधि की सरकारी हिस्सेदारी के 25% के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने (या) भारत सरकार की हिस्सेदारी के 25 प्रतिशत हेतु कम से कम 3 साल की अवधि के लिए वैध वस्त्र आयुक्त के पक्ष में संपत्ति को गिरवी रखने, जमानती बांड, प्रोमिसरी नोट, आदि जैसे किसी वैकल्पिक विकल्प को अपनाने।

iii. कि एसपीवी के सभी सदस्य यार्न बैंक में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं।

iv. कि यार्न बैंक के लिए स्थायी निधि का उपयोग एसपीवी द्वारा एसपीवी के सदस्यों और निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र की इकाइयों के क्लस्टर में और उसके आसपास यार्न की खरीद और आपूर्ति के लिए किया जाएगा।

v. कि वे यार्न के भंडारण के लिए एक उपयुक्त वेयरहाउस, सुरक्षा/संरक्षा व्यवस्था और बीमा की व्यवस्था करेंगे।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित नमूना प्रारूप **अनुबंध-I** पर है।

6. कार्यान्वयन के निबंधन और शर्तें

एसपीवी को स्थायी निधि प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं :-

क. सरकार एसपीवी/संघ को प्रति यार्न बैंक अधिकतम 200 लाख रूपए व्याज मुक्त स्थायी निधि प्रदान करेगी।

ख. एसपीवी मंजूरी की तारीख के 60 दिनों के भीतर पीएसी द्वारा अनुमोदित निधि के बराबर अपनी स्वयं की निधि की व्यवस्था करेगा।

ग. सरकार द्वारा प्रदान की गई उक्त स्थायी निधि को एसपीवी को स्थायी निधि की सरकारी हिस्सेदारी के 25% के लिए वस्त्र आयुक्त के पक्ष में कम से कम 3 साल की अवधि के लिए वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने (या) भारत सरकार की हिस्सेदारी के 25 प्रतिशत हेतु कम से कम 3 साल की अवधि के लिए वैध वस्त्र आयुक्त के पक्ष में संपत्ति को गिरवी रखने, जमानती बांड, प्रोमिसरी नोट, आदि जैसे किसी वैकल्पिक विकल्प को अपनाने पर दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित बैंक गारंटी का प्रारूप **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

घ. एसपीवी उचित प्रलेखन, सुरक्षा/संरक्षा व्यवस्था और बीमा के साथ यार्न के भंडारण के लिए एक उपयुक्त वेयरहाउस की पहचान/प्रदान करेगा।

ङ. स्थायी निधि में भारत सरकार का हिस्सा एस्को खाते में जमा किया जाएगा जिसे एसपीवी के एक सदस्य और वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से एक सदस्य द्वारा संचालित किया जाएगा। सरकार। एसपीवी का हिस्सा जमा करने और निर्धारित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के तुरंत बाद एस्को खाते में भारत सरकार का हिस्सा जमा किया जाएगा। एस्को खाता खोलने के बाद, एसपीवी मंजूरी की तिथि के 60 दिनों के भीतर स्थायी निधि की भारत सरकार की हिस्सेदारी हेतु **अनुबंध-III** में निर्धारित प्रारूप में, संबंधित दस्तावेजों के साथ वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेगा, जो आगे दावे की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त कार्यालय में पावरलूम विकास एकक को भेजेगा।

च. यार्न बैंक के लिए उक्त स्थायी निधि का उपयोग एसपीवी द्वारा यार्न की खरीद और आपूर्ति तथा क्लस्टर में और उसके आसपास निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र की इकाइयों द्वारा आवश्यक स्टॉक को बनाए रखने के लिए किया जाएगा।

छ. एसपीवी को एक वर्ष में कम से कम 4-5 बार अपने योगदान सहित स्थायी निधि को संचालित करना चाहिए।

ज. परियोजना के कार्यान्वयन के बाद एसपीवी को वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, मुंबई को एक प्रतिलिपि के साथ, **अनुबंध-IV** में निर्धारित प्रारूप में मासिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

झ. एसपीवी को **अनुबंध-V** में संलग्न प्रारूप में यार्न की प्रत्येक खरीद और वितरण की प्रविष्टि के साथ रिकॉर्ड को ठीक से बनाए रखना चाहिए, जिसमें सदस्यों का विवरण यानि सदस्यता संख्या दी गई हो, जिसे यार्न बेचा गया है।

ज. एसपीवी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि यार्न की मांग उपलब्धता से अधिक है, तो यार्न की आपूर्ति हर सदस्य को अलग से जानी चाहिए, और किसी भी सदस्य को योजना का लाभ दो बार नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि पहले प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता के अनुसार कम से कम एक बार योजना का लाभ न दिया जाए।

ट. उक्त स्थायी निधि एसपीवी के साथ **तीन साल की अवधि** के लिए उपलब्ध होगी, जिसके विस्तार पर परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा इसके निष्पादन के आधार पर विचार किया जा सकता है।

ठ. यदि किसी कारण से, बैंक गारंटी/सुरक्षा से राशि की वसूली नहीं होती है, तो एसपीवी/संघ को भारत सरकार को समाप्ति की तारीख से तीन साल तक की अवधि हेतु साधारण ब्याज (10%) के साथ राशि वापस करनी होगी।

ड. एसपीवी परियोजना की मंजूरी के लिए वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को डीपीआर के साथ **अनुबंध-VI** में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा। वस्त्र आयुक्त का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्ताव की जांच करेगा और आवेदन की तारीख के 30 दिनों के भीतर सिफारिश के साथ इसे अग्रेषित करेगा।

ढ. स्थायी निधि के लिए उक्त प्रस्ताव को वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा आगे जांचा जाएगा और इसे वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्ति की तारीख के 60 दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष रखा जाएगा।

7. कार्यान्वयन एजेंसी

वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बुनाई/बुने हुए वस्त्र निर्यात संवर्धन परिपद, बुनाई/बुने हुए वस्त्र क्षेत्र एसोसिएशन/फेडरेशन/संगठन, राज्य सरकारों आदि के सहयोग से इस योजना को लागू किया जाएगा/निगरानी की जाएगी।

8. परियोजना अनुमोदन समिति

इस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी परियोजनाओं को परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :

वस्त्र आयुक्त	- अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (पीएल)	- सदस्य
आईएफडब्ल्यू के प्रतिनिधि	- सदस्य
वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में पावरलूम विकास प्रकोष्ठ के संयुक्त वस्त्र आयुक्त/निदेशक /उप निदेशक	- सदस्य सचिव

9. निगरानी और समीक्षा

क. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और लाभ के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, वस्त्र आयुक्त एसपीवी से किसी भी दस्तावेज/सूचना की मांग कर सकते हैं, जिसे वह आवश्यक समझे।

ख. निर्दिष्ट समय के भीतर वस्त्र आयुक्त द्वारा मांगी किसी भी जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एसपीवी की विफलता को यार्न बैंक योजना के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और परियोजना के अनुमोदन को रद्द करने या समय से पहले दी गई निधि की तत्काल वसूली के आदेश सहित उपयुक्त समझी गई कोई भी कार्रवाई की जा सकती है।

ग. एसओबी भारत सरकार के अंश जारी करने की तारीख से कम से कम 3 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा।

घ. परियोजना अनुमोदन समिति (पॉवरटेक्स इंडिया के अंतर्गत) का निर्णय/निर्देश अंतिम होगा।

10. शिकायत का निवारण

योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी शिकायतें वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत की जाएंगी जो शिकायत के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनुबंध - I

वचन

मैं/हम, _____ एतद्वारा वचन देते हैं कि

- (i) एसपीवी भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधि के बराबर अपनी स्वयं की निधि की व्यवस्था करेगा।
- (ii) एसपीवी स्थायी निधि की सरकारी हिस्सेदारी के 25% के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने (या) भारत सरकार की हिस्सेदारी के 25 प्रतिशत हेतु बाण्ड जारी करने की तिथि से कम से कम 3 साल की अवधि के लिए वैध वस्त्र आयुक्त के पक्ष में संपत्ति को गिरवी रखने, जमानती बांड, प्रोमिसरी नोट, आदि जैसे किसी वैकल्पिक विकल्प की व्यवस्था करेगा।
- (iii) एसपीवी के सभी सदस्यों की पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत बुनाई तथा बुने हुए वस्त्र क्षेत्र विकास हेतु यार्न बैंक योजना में भाग लेने में रुचि है।
- (iv) पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत बुनाई तथा बुने हुए वस्त्र क्षेत्र विकास हेतु यार्न बैंक योजना के लिए ब्याज मुक्त स्थायी निधि का उपयोग एसपीवी द्वारा एसपीवी के सदस्यों हेतु यार्न की खरीद और आपूर्ति के लिए किया जाएगा।
- (v) एसपीवी ने (पूर्ण पता) में स्थित _____ वर्ग फुट माप वाले क्षेत्र के एक गोदाम की पहचान की है। इसके अलावा, मैं/हम यह वचन देते हैं कि सुरक्षा/संरक्षा कार्य और बीमा अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

वचन के कथन मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं।

दिनांक :

नाम :

स्थान :

पदनाम :

एसपीवी का नाम :

एसपीवी की मुहर :

अनुबंध - II

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्यरत,

निष्ठा भवन, न्यू सी.जी.ओ. ,

मुंबई- 400 020।

पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र विकास के लिए योजनाओं के तहत यार्न बैंक के लिए स्थायी निधि के उपयोग के लिए बैंक गारंटी।

इस बैंक गारंटी की पुष्टि उपलब्ध है।

बैंक गारंटी के इस विलेख को..... बैंक, (अधिमानतः एक राष्ट्रीयकृत बैंक) कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के भीतर एक बैंककारी कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय पर और इसकी एक शाखा..... पर है, द्वारा प्रभारी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में जारी किया गया है।

जबकि पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र विकास के लिए योजनाओं के तहत गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) ने पावरटेक्स इंडिया के तहत यार्न बैंक के लिए स्थायी निधि (समय-समय पर संशोधित) के उपयोग का लाभ (एसपीवी/संघ का नाम और पता) को देने पर सहमति प्रदान की है, जिसे वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, मुंबई द्वारा पत्र क्रमांक _____ के माध्यम से पावरटेक्स इंडिया के तहत यार्न बैंक योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अंतर्गत जारी किया गया था।।

जबकि उपरोक्त उल्लिखित (एसपीवी/संघ का नाम और पता) को बॉन्ड को उस तरह की जमानत और सुरक्षा के साथ निष्पादित करना आवश्यक है, जिसके द्वारा उन्हें वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जा सकें।

जबकि प्रभारी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, _____ ने उक्त (एसपीवी/संघ का नाम और पता) को उक्त योजना के अंतर्गत निबंधन और शर्तों की पूर्ति के लिए बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा है।

और जबकि उपरोक्त वर्णित (एसपीवी / संघ का नाम और पता) ने हमसे (बैंक गारंटी देने वाला बैंक का नाम), प्रभारी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय _____ के माध्यम से कार्य कर रहे, भारत के राष्ट्रपति को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए है, उपर्युक्त बॉन्ड द्वारा देय तथा भुगतानयोग्य राशि के लिए (एसपीवी/संघ का नाम और पता) बैंक गारंटी देने का अनुरोध किया है।

हम, (बैंक गारंटी देने वाले बैंक का नाम और पता) बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति को मांग किए जाने पर भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं और ऐसा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर तथा उपरोक्त बॉन्ड के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य **रूपए** (..... **रूपए मात्र**) की राशि को बिना किसी विलंब या विरोध के, पावरटेक्स के अंतर्गत यार्न बैंक योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति को उक्त (एसपीवी / संघ का नाम और पता) द्वारा किसी भी हानि या क्षति या किसी अन्य कारण से अथवा बॉन्ड के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के या अन्यथा के कारण, राशि के भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम, (बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले बैंक का नाम और पता), बिना शर्त के और अपरिवर्तनीय रूप से वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति को उक्त (एसपीवी/संघ का नाम और पता) द्वारा किसी भी अदालत/अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद इस प्रकार मांग की गई किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

हम, (बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले बैंक का नाम और पता), आगे इस बात पर सहमत हैं कि वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई मांग हमारे द्वारा देय तथा भुगतानयोग्य राशि के संबंध में वर्तमान समझौते के अंतर्गत हमारी पूर्ण तथा अपरिवर्तनीय देयता के रूप में निर्णायक होगी।

हम, (बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले बैंक का नाम और पता), आगे सहमत हैं कि यह गारंटी उस अवधि के दौरान पूरी तरह से लागू रहेगी, जो पावरटेक इंडिया के अंतर्गत यार्न बैंक योजना के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए (एसपीवी / संघ का नाम और पता) उक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत ली जाएगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक उक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत सभी नियम और शर्तों का पूरी तरह से **प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त के कार्यालय** द्वारा निर्वहन नहीं हो जाता, **या प्रभारी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, _____** जब तक यह प्रमाणित नहीं करता है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निबंधन और शर्तें पूरी और ठीक तरह से निष्पादित किया गया हैं और उक्त (एसपीवी/संघ का नाम और पता) द्वारा निष्पादित उक्त बाण्ड का पूरी तरह से निर्वहन कर लिया गया है।

हम, (बैंक गारंटी प्रस्तुत करने वाले बैंक का नाम और पता), आगे इस बात से सहमत हैं कि वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति को हमारी सहमति के बिना और इस बैंक गारंटी के अंतर्गत किसी भी तरीके या दायित्व को प्रभावित किए बिना पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वे पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत यार्न बैंक योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित निबंधन और शर्तों को परिवर्तित कर सके या पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत यार्न बैंक योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निष्पादन के लिए समय बढ़ा सकें या उपरोक्त दिशा-निर्देशों के किसी भी निबंधन और शर्तों को रोक या प्रवर्तन के लिए कह सकें और इस तरह की किसी भिन्नता या रोक के विस्तार या उक्त दिशानिर्देशों के संबंध में वस्त्र आयुक्त के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की ओर से किसी कृत्य को करने या उसमें शामिल होने से इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमें या हमारे दायित्व से कोई राहत नहीं दी जाएगी, जो

जमानती कानून से संबंधित है, लेकिन इसके प्रावधान से, हमें (बैंक गारंटी देने वाले बैंक का नाम और पता) राहत देने प्रभाव होता हों।

हम, (बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने वाले बैंक का नाम और पता) घोषित करते हैं कि यह एक सतत बैंक गारंटी होगी और उक्त (एसपीवी/संघ का नाम और पता) की संरचना में किसी भी परिवर्तन से हमें मुक्त नहीं किया जाएगा। हम आगे घोषणा करते हैं कि वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस बैंक गारंटी को उसके चालन के दौरान निरस्त नहीं करेंगे।

हम, (बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने वाले बैंक का नाम और पता), आगे घोषणा करते हैं कि यह बैंक गारंटी _____ से _____ तक _____ तक मान्य होगी और हम इस बैंक गारंटी को नवीनीकृत करने का कार्य तब तक करेंगे जब तक कि मामले का निपटान न हो जाए और **प्रभारी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय**, _____ द्वारा हमें पूर्णतः मुक्त न किया जाए या जब तक इस बैंक गारंटी के अनुपालन में वस्त्र आयुक्त के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई मांग की जाती है।

ऊपर कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद :

1. बैंक गारंटी के तहत हमारी देयता **रुपए (_____ रूपए मात्र)** से अधिक नहीं होगी।
2. यह बैंक गारंटी _____ तक मान्य होगी।
3. हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटी राशि या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने के लिए केवल और केवल आपके हमें लिखित में दावा या मांग प्रस्तुत करने पर ही उत्तरदायी हैं।

हम आगे घोषणा करते हैं कि यह बैंक गारंटी स्वतः नवीनीकृत हो जाएगी; हम इस बैंक गारंटी को मामले के निपटान प्रभारी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, _____ पूर्णतः निर्वहन तक स्वतः नवीनीकृत करने का वचन देते हैं।

अनुबंध-III

यार्न बैंक योजना के भारत सरकार के हिस्से को निर्मुक्त किए जाने हेतु एसपीवी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ दावे के आवेदन का प्रारूप। (अनुमोदन की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाएं)

सेवा में,

दिनांक :

प्रभारी अधिकारी,

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय,

हम इसके साथ यार्न बैंक योजना के प्रति भारत सरकार के अंश को निर्मुक्त करने हेतु अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। हम आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न कर रहे हैं।

1. अधिदेश फार्म की प्रति के साथ एस्करो खाता विवरण।
2. यार्न भंडारण के लिए वेयरहाउस/गोदाम का प्रमाण।
3. एस्करो खाते में सरकार की हिस्सेदारी के समान राशि को जमा किए जाने को दर्शाने वाला बैंक विवरण।
4. यह दर्शाने वाले दस्तावेज कि वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को एसपीवी के निदेशकों में से एक के रूप में शामिल किया गया है।
5. भारत सरकार के अंश पर 25 प्रतिशत की बैंक गारंटी जो कम से कम **3** साल की अवधि के लिए वैध हो।

6. कोई अन्य विवरण।

अनुरोध है कि आप अपनी अनुशंसा के साथ उपरोक्त दावे को वस्त्र आयुक्त कार्यालय को अग्रेषित करें।

भवदीय,

(एसपीवी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-IV

यार्न बैंक की मासिक प्रगति रिपोर्ट

एसपीवी का नाम :																रिपोर्ट दिनांकित			
माह	प्रारंभिक स्टाक किलोग्राम में		यार्न का मूल्य रूपए में		खरीदे गए यार्न की मात्रा किलोग्राम में		यार्न का मूल्य रूपए में		बेचे गए यार्न की मात्रा किलोग्राम में		यार्न का मूल्य रूपए में		अंतिम स्टाक की मात्रा किलोग्राम में		यार्न का मूल्य रूपए में		टर्नओवर रूपए में	एसपीवी में जोड़े गए सदस्यों की संख्या, यदि कोई हो	एसपीवी में निकाले गए सदस्यों की संख्या, यदि कोई हो
	सी	एस	सी	एस	सी	एस	सी	एस	सी	एस	सी	एस	सी	एस	सी	एस			
अप्रैल, 2019																			
मई, 2019																			
जून, 2019																			
जुलाई, 2019																			
अगस्त, 2019																			
सितम्बर, 2019																			
अक्तूबर, 2019																			
नवम्बर, 2019																			
दिसम्बर, 2019																			
जनवरी, 2020																			
फरवरी, 2020																			
मार्च, 2020																			

रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख को प्रस्तुत की जाएगी।

सी - कपास

एस – सिंथेटिक यार्न

ओआईसी के हस्ताक्षर

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय : _____

अनुबंध-V

यार्न बैंक योजना की मासिक खरीद और बिक्री का व्यौरा

एसपीवी का नाम :

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम :

माह :

क्रम सं.	तिथि	प्रारंभिक स्टॉक (किलोग्राम में)	खरीद (किग्रा में)	कुल (किग्रा में)	डिलीवरी			आपूर्ति यार्न (किलोग्राम में)	अंतिम स्टॉक (किलोग्राम में)	टिप्पणी
					सदस्यता सं.	सदस्य का अंश	बुनाई मशीनों की संख्या			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध-VI

यार्न बैंक योजना हेतु आवेदन

क्रम सं.	विवरण	एसपीवी द्वारा भरा जाए
1.	एसपीवी का नाम	
2.	एसपीवी का पता	
3.	एसपीवी किसके अंतर्गत पंजीकृत है	
4.	पंजीकरण संख्या तथा तिथि	
5.	एसपीवी के सदस्यों की संख्या और अनुबंध-VII में संलग्न प्रारूप में सदस्यों की सूची	
6.	एसपीवी के पास बुनाई मशीनों की संख्या	
7.	क्लस्टर का नाम	
8.	क्लस्टर में बुनाई मशीनों की संख्या (i) साधारण सर्कुलर बुनाई मशीन (ii) उच्च गति सर्कुलर बुनाई मशीन (iii) इलेक्ट्रॉनिक जेककार्ड के साथ या उसके बिना हाई स्पीड मोजे बुनाई और दस्ताने बुनाई मशीनें	

	<p>(iv) प्रति मिनट 11 रेवोल्यूशन की न्यूनतम गति के साथ कम्प्यूटरीकृत फ्लैट बेड बुनाई मशीन</p> <p>(v) वार्प/रशेल बुनाई मशीनें</p> <p>(vi) बुनाई के लिए उच्च गति कम्प्यूटरीकृत वार्पिंग मशीन</p> <p>(vii) कम्प्यूटरीकृत लेबल बनाने की मशीन</p> <p>(viii) कम्प्यूटरीकृत स्ट्रैप (कॉलर/कफ) फ्लैट बेड बुनाई मशीन</p> <p>(ix) अन्य बुनाई मशीनें</p>	
9.	क्लस्टर में बुनाई (सिलाई) मशीनों की संख्या	
10.	विनिर्मित उत्पादों का नाम	
11.	क्लस्टर में उपयोग किए जाने वाले यार्न की विविधता (सूती/सिंथेटिक/मिश्रित)	
12.	प्रति वर्ष आवश्यक यार्न का कुल किलोग्राम	
13.	उक्त यार्न की खरीद के लिए प्रति वर्ष अपेक्षित कुल निधि	
14.	एसपीवी द्वारा अपेक्षित ब्याज मुक्त स्थायी निधि	
15.	एसपीवी द्वारा भारत सरकार से ब्याज मुक्त निधि के लिए निवेदन की गई राशि के बराबर व्यवस्था की गई धनराशि का विवरण	
16.	एसपीवी द्वारा व्यवस्था की गई निधियों और तीन वर्षों हेतु बैंक गारंटी का व्यौरा	
17.	उचित प्रलेखन, सुरक्षा/संरक्षा व्यवस्था और बीमा के साथ यार्न के भंडारण के लिए उपयुक्त गोदाम का विवरण	
18.	संलग्न दस्तावेजों की सूची	

दिनांक :

नाम :

स्थान :

पदनाम :

एसपीवी का नाम :

एसपीवी की मुहर :

केवल कार्यालय उपयोग हेतु :

एसपीवी के प्रस्तावित यार्न बैंक के स्थान पर को दौरा किया और एसपीवी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया। प्रस्ताव अनुमोदन के लिए अनुशंसित है/निम्न कारणों से अनुशंसित नहीं है:

ओआईसी के हस्ताक्षर

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

अनुबंध-VII

एसपीवी का विवरण

एसपीवी का नाम और पता :

एसपीवी और उसके सदस्यों का विवरण

क्रम सं.	सदस्य का नाम /यूनिट	संपर्क विवरण (ई-मेल आईडी / मोबाइल नंबर)	एसपीवी में पदनाम	सदस्य/ यूनिट के स्वामित्व वाली बुनाई मशीन की संख्या	सदस्य /यूनिट द्वारा स्थायी निधि में योगदान द्वारा रुपए में

आवश्यक दस्तावेजों का सार और जांच सूची

पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र के विकास की योजना के अंतर्गत यार्न बैंक योजना

चरण	उद्देश्य	आवश्यकता	अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का चरण
1.	यार्न बैंक के लिए स्थायी निधि की मंजूरी के लिए आवेदन	आवेदन एसपीवी द्वारा वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आरओ को सिफारिश के साथ आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे विद्युतकरघा के पास सेल को अग्रेषित करना होगा।	दिशा निर्देशों के अनुबंध-VI में आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 1. एसपीवी की प्रकृति 2. भारत सरकार की हिस्सेदारी का 25% के लिए बैंक गारंटी 3. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि के बराबर अपनी निधि की व्यवस्था करना 4. यार्न के भंडारण के लिए उपयुक्त	आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दौरान।

			वेयरहाउस की बिक्री/लीज	
2.	यार्न बैंक हेतु स्थायी निधि की स्वीकृति	क्षेत्रीय कार्यालय से आवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पावरलूम विकास प्रकोष्ठ एसपीवी को स्वीकृति संप्रेषित करेगा।	दिशा निर्देशों के अनुबंध-VI में आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 1. एसपीवी की प्रकृति 2. भारत सरकार की हिस्सेदारी का 25% के लिए बैंक गारंटी 3. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि के बराबर अपनी निधि की व्यवस्था करना 4. यार्न के भंडारण के लिए उपयुक्त वेयरहाउस की बिक्री/लीज 5. वेयरहाउस का बीमा।	----
3.	भारत सरकार का अंश जारी करने के लिए दावा	एसपीवी को मंजूरी की तारीख से 60 दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत करना होगा। आरओ को प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर दावे को पीडीसी को अग्रेषित करना होगा।	1. एस्क्रो खाते का विवरण 2. भारत सरकार की हिस्सेदारी का 25% के लिए बैंक गारंटी की प्रक्रिया 3. एस्क्रो खाते में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि के बराबर निधि का प्रमाण	भारत सरकार का अंश जारी किए जाने से पूर्व

पीएफएमएस के साथ एजेंसी बनाने के लिए एस्क्रो खाते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

(नोट : सभी फील्ड अनिवार्य हैं)

क्रम सं.	विवरण	
1.	एजेंसी का नाम (यूनिट/ईए/ एसपीवी का नाम)	
2.	एसपीवी की पंजीकरण संख्या	
3.	पंजीकरण की तिथि (डीडी/एमएम/ वाईवाईवाईवाई)	
4.	पंजीकरण प्राधिकारी	
5.	पंजीकरण का राज्य	
6.	टिन संख्या	
7.	टैन संख्या	
8.	पैन संख्या	

9.	यूनिट का पता	
10.	शहर	
11.	जिला	
12.	राज्य	
13.	पिन कोड	
14.	संपर्क व्यक्ति और संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर	
15.	यूनिट/ईए/एसपीवी का एस्करो खाता संख्या	
16.	यूनिट/ईए/एसपीवी की ई-मेल आईडी	
17.	बैंक का नाम	
18.	शाखा का नाम और पिन कोड सहित पता	
19.	बैंक का शहर कोड	
20.	बैंक का एमआईसीआर कोड	
21.	बैंक का आईएफएससी कोड	
22.	बैंक का शाखा कोड	

हस्ताक्षर के साथ बैंक की मोहर

एसपीवी के हस्ताक्षर के साथ मोहर

VI. सामान्य सुविधा केंद्र

निटिंग और निटवियर वस्त्र क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) योजना

निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याएँ प्रचलित तकनीक के निम्न स्तर की हैं, और साथ में निटिंग और निटवियर वस्त्र इकाइयों के व्यापक विखंडन, पैमाने की मितव्ययताओं की कमी, निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र में बुनाई पूर्व और पश्च सुविधाओं तथा डिजाइन विकास/परीक्षण सुविधाओं के अभाव के साथ खराब उत्पादकता, आम तौर पर उत्पाद की खराब गुणवत्ता और कम यूनिट वसूली आदि की है।

उद्देश्य :

विभिन्न निटिंग और निटवियर वस्त्र समूहों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने और साथ जुड़े हुए बुनकरों/इकाइयों के समूहों, निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र उद्योग संघों और निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र उद्योग से संबद्ध अन्य संगठनों को समान सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके बुनाई पूर्व और तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं सुहैया करवाना। समान सुविधा केन्द्र में डिजाइन सेंटर/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना सह व्यापार केन्द्र तथा समान कच्चा माल/यार्न/विक्री डिपो, औद्योगिक उपयोग हेतु जल शोधन संयंत्र, कामगारों के लिए डोरमेट्री, समान बुनाई पूर्व सुविधाएं यथा ए-टीयूएफ संगत यार्न प्रसंस्करण और बुनाई पश्च सुविधा, ए-टीयूएफ संगत वस्त्र प्रसंस्करण मशीनें, फोल्डिंग मशीन, काटने की मशीन और सिलाई मशीनों और बुने हुए वस्त्र पश्च सुविधाएं यथा ए-टीयूएफ संगत परिधान प्रसंस्करण मशीनें शामिल है। अन्य मूर्त परिसंपत्तियां भी क्लस्टर में स्थापित की जा सकती हैं, जब तक कि वे क्लस्टर में और उसके आसपास विकेंद्रीकृत निटिंग और निटवियर वस्त्र इकाइयों द्वारा समान उपयोग में लाए जाते हैं।

योजना के प्रचालन की अवधि :

पावरटेक्स इंडिया के अंतर्गत निटिंग और निटवियर वस्त्र क्लस्टरों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र योजना (सीएफसी) 01.7.2019 से 31.03.2020 तक संचालित होगी।

एसपीवी की पात्रता :

प्रस्तावित सामान्य सुविधा केंद्र को स्थापित करने और संचालित करने से पहले कम से कम 11 सदस्यों के साथ एक विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) का गठन करना आवश्यक है। एसपीवी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, पंजीकृत सहकारी समिति, कोई ट्रस्ट, एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी फर्म, राज्य सरकार/राज्य सरकार की एजेंसियां योजना के अंतर्गत सीएफसी की स्थापना के लिए पात्र हैं। एसपीवी के सदस्य हितधारक अर्थात् बुनकर, मास्टर बुनकर, निजी उद्यमी, निटिंग और निटवियर वस्त्र क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियों के सदस्य होने चाहिए।

एसपीवी का संचालन :

एसपीवी में योगदान करने वाले सदस्यों के अलावा, आयोजकों को प्रस्तावित सुविधा के अधिकाधिक 'उपयोगकर्ताओं' से लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त करनी होगी ताकि इसके लाभों को और बढ़ाया जा सके।

भविष्य में पृथक निटिंग और निटवियर वस्त्र उद्यमियों सहित सदस्यता बढ़ाने के लिए अंतर्निहित गुंजाइश के साथ एसपीवी की एक जनतांत्रिक संरचना होनी चाहिए।

एसपीवी को बुनकरों के साथ बातचीत करनी होगी और संबंधित संगठनों जैसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों, बाजार संस्थानों/बाजार विशेषज्ञों, विपणन कर्ताओं, कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी मशीनरी आदि के साथ संपर्क रखना होगा।

एसपीवी सामान्य सुविधा केन्द्र/यार्न डिपो, आधारभूत ढांचे आदि की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ -वार्षिक वार्षिक कार्य योजनाओं को निर्दिष्ट करेगा, जिसमें क्लस्टर की आवश्यकताओं, गतिविधियों और अपेक्षित आउटपुट, परिणामों/डिलिवरेबल्स, परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा और प्रस्ताव को वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में अनुबंध-III में जांच-सूची में सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ अनुबंध I और II में निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्ताव की जांच करेगा और प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश के साथ उसे वस्त्र आयुक्त कार्यालय को अग्रेषित करेगा। वस्त्र आयुक्त का कार्यालय आगे प्रस्ताव की जांच करेगा और वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव की प्राप्ति पर परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) के समक्ष रखेगा।

एसपीवी वस्त्र आयुक्त को आवधिक रूप से भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट और पूर्ण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

परियोजनाओं के पूरा होने के बाद, एसपीवी निटिंग और निटवियर वस्त्र इकाइयों के लिए सामान्य सुविधाओं/बुनियादी ढांचे को चलाने और बनाए रखने के लिए संघ के रूप में जारी रहेगा।

एसपीवी, गैर-एसपीवी सदस्यों से अपने स्वयं के एसपीवी सदस्यों से सामान्य सुविधा केन्द्रों के उपयोग के लिए वसूले जाने वाले प्रभार से 20% से अधिक शुल्क नहीं लेगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा सीएफसी की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

शर्तें :

(i) सीएफसी के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा को सीमित किए बिना एक क्लस्टर में एक से अधिक प्रस्ताव/परियोजनाएं क्लस्टर की आवश्यकता के अनुसार अनुमेय हैं। तथापि, सीएफसी के एसपीवी में कोई भी सामान्य निदेशक नहीं होगा, अर्थात् सीएफसी के एक एसपीवी का निदेशक सीएफसी के किसी अन्य एसपीवी का निदेशक नहीं होगा।

(ii) स्वामित्व वाली भूमि/भवन, 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए एसपीवी के पक्ष में पट्टाबद्ध भूमि/भवन को भारत सरकार से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले एसपीवी द्वारा व्यवस्थित किया जाना एक पूर्व शर्त है।

(iii) एसपीवी बनाने के लिए न्यूनतम 11 सदस्यों की आवश्यकता होती है।

(iv) परियोजना प्रोफाइल में किसी भी परिवर्तन के मामले में, पीएसी की स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

(v) केवल ए-टीयूएफ संगत मशीनरी सीएफसी में स्थापित की जा सकती है।

(vi) पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित सब्सिडी के गैर-उपयोग/गलत उपयोग के मामले में और परियोजना के पूरा होने में देरी में, जारी की गई निधियों को 10% प्रति वर्ष की दर वाले साधारण ब्याज के साथ कार्यकारी एजेंसी से वसूला जाएगा।

(vii) पीएसी का निर्णय अंतिम होगा।

(viii) बहु-स्रोत वित्त-पोषण की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते लाभार्थी परियोजना/उपकरण की लागत के कम से कम 5% योगदान देता है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, परियोजना/उपकरण की पात्र लागत के 95% पर सीमित किया जाएगा।

(ix) लाभार्थी द्वारा सब्सिडी प्राप्त परिसंपत्तियों को लाभार्थियों द्वारा एस्करो खाते से सब्सिडी जारी करने/निकालने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है।

(x) अंतिम एलएलएमसी के दौरान मशीनरी को चालू किए जाने का प्रमाण-पत्र भी चार्टर्ड इंजीनियर से प्राप्त किया जाना चाहिए।

योजना के अंतर्गत पात्र सुविधाएं, मशीनें, उपकरण, उपस्कर आदि

सामान्य सुविधा केन्द्र में डिजाइन सेंटर/स्टूडियो, परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना सह व्यापार केन्द्र तथा समान कच्चा माल/यार्न/विक्री डिपो, औद्योगिक उपयोग हेतु जल शोधन संयंत्र, कामगारों के लिए डोरमेट्री, समान बुनाई पूर्व सुविधाएं यथा ए-टीयूएफ संगत यार्न प्रसंस्करण और बुनाई पश्च सुविधा, ए-टीयूएफ संगत वस्त्र प्रसंस्करण मशीनें, फोल्डिंग मशीन, काटने की मशीन और सिलाई मशीनों और बुने हुए वस्त्र पश्च सुविधाएं यथा ए-टीयूएफ संगत परिधान प्रसंस्करण मशीनें शामिल है। अन्य मूर्त परिसंपत्तियां भी क्लस्टर में स्थापित की जा सकती हैं, जब तक कि वे क्लस्टर में और उसके आसपास विकेन्द्रीकृत निटिंग और निटवियर वस्त्र इकाइयों द्वारा समान उपयोग में लाए जाते हैं।

सब्सिडी की मात्रा :

(i) सामान्य सुविधा केंद्र निटिंग और निटवियर वस्त्र क्लस्टर की विभिन्न ग्रेडिंग के आधार पर सरकार से सहायता के विभिन्न स्तरों के लिए पात्र है, अर्थात् :

ग्रेड - ए - परियोजना लागत के 60% तक की सब्सिडी।

ग्रेड - बी - परियोजना लागत के 70% तक सब्सिडी।

ग्रेड - सी - परियोजना लागत के 80% तक सब्सिडी।

ग्रेड - डी और पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर में क्लस्टर - परियोजना लागत का 90% तक सब्सिडी।

क्लस्टरों की ग्रेडिंग वस्त्र आयुक्त द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जाएगी। निटिंग और निटवियर वस्त्र क्लस्टर की ग्रेडिंग के लिए मापदंड **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

(ii) यार्न डिपो सहित सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए उपलब्ध सहायता 400 लाख रूपए प्रति सीएफसी होगी।

(iii) उपरोक्त सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे :

भवन, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, प्रयोगशाला, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां, प्रचालन-पूर्व/प्रारंभिक व्यय की लागत आदि।

(iv) भवन निर्माण लागत का केवल 25% अधिकतम सब्सिडी के रूप में पात्र होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 80 लाख रूपए है। राज्य में सीपीडब्ल्यूडी की दरों की अनुसूची का उपयोग भवन निर्माण की लागत के अनुमानों को निकालने के लिए किया जाएगा।

(v) प्रस्ताव, जहां भवन पहले से ही अस्तित्व में है, प्रस्तावित सीएफसी के निर्माण की मंजूरी से पहले भवन का निर्माण पूरा हो गया है और पट्टा पंजीकृत है, तो ऐसे प्रस्तावों को सीएफसी के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है बशर्ते भवन एसपीवी के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए या एसपीवी के पक्ष में भवन का पट्टा समझौता कम से कम 10 वर्षों के लिए होना चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में, सब्सिडी केवल योग्य मशीनरी घटक के लिए दी जाएगी और निर्माण घटक के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

(vi) उदाहरण के लिए :

परियोजना लागत	सहायता की गणना करने के लिए अधिकतम पात्र लागत	
मशीनरी, संयंत्र, उपकरण, प्रयोगशाला, अन्य मूर्त परिसंपत्तियां, प्रचालन-पूर्व/ प्राथमिक व्यय, आदि	3.20 करोड़ रूपए	3.20 करोड़ रूपए
भवन का निर्माण	2.00 करोड़ रूपए	0.50 करोड़ रूपए
कुल	5.20 करोड़ रूपए	3.70 करोड़ रूपए

सहायता जारी करना :

एसपीवी किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोलेगा और सीएफसी के लिए सभी भुगतान एस्करो खाते के माध्यम से किए जाएंगे जिसे एसपीवी के एक सदस्य और क्षेत्रीय कार्यालय के एक सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

एसपीवी को वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को वित्तीय सहायता जारी करने के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहिए।

दुरुपयोग के प्रति रक्षोपाय :

- (i) जिस भूमि पर स्थापना के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र प्रस्तावित है, उसमें एसपीवी के पक्ष में उपयोग के लिए स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिए और स्थानीय निकाय, नगरपालिका प्राधिकारी, राज्य प्रशासन और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी के यथालागू अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी होने चाहिए।
- (ii) लाभार्थियों द्वारा चूक से बचने के लिए, योजना के अंतर्गत अनुमोदित सभी मामलों में परिसंपत्तियों पर प्रथम या द्वितीय प्रभार का रेहन रखा जाएगा, जिसमें विफल रहने पर लाभार्थी निधियों को जारी करने से पूर्व प्रारूप (अनुबंध- V) के अनुसार निश्चित जमानती बांड को निष्पादित करेगा।
- (iii) एसपीवी भारत सरकार की अंतिम किस्त के जारी होने की तारीख से कम से कम पांच साल की अवधि के लिए कार्यकरेगा।
- (iv) सब्सिडी के गैर-उपयोग/दुरुपयोग के मामले में और परियोजना को पूरा करने में 18 महीने से अधिक की देरी पर, पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित, जारी की गई निधियों को एसपीवी द्वारा निधि जारी करने से लेकर राशि वापस करने की तिथि तक 10% प्रति वर्ष की दर वाले साधारण ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।
- (v) पहली किस्त जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि का मूल्य एसपीवी को जारी की जाने वाली राशि (पहली किस्त) से अधिक है।
- (vi) सब्सिडी का उपयोग पूर्वगामी पैरा यानी सहायता जारी करने में उल्लिखित एस्करो खाते के माध्यम से किया जाएगा।

कार्यान्वयन :

स्थानीय स्तर की निगरानी समिति (एलएलएमसी) :

प्रत्येक सीएफसी के लिए स्थानीय स्तर की निगरानी समिति बनाई जाएगी; जिसमें वस्त्र युक्त के क्षेत्रीय कार्यालय से एक अधिकारी, एसपीवी का एक प्रतिनिधि अधिमानतः कोई निदेशक और राज्य सरकार का अधिकारी शामिल होगा। पात्र वित्तीय सहायता **अनुबंध-VI** के प्रारूप के अनुसार एलएलएमसी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जारी की जाएगी।

एसपीवी को भारत सरकार की सब्सिडी जारी करने के लिए निम्नलिखित अनुसूची को अपनाया जाएगा :

पहली किस्त : भारत सरकार के कुल अंश के 30% हिस्से को सरकारी वास्तुकार और सनदी लेखाकार द्वारा अनुमोदित निर्माण के लिए एसपीवी द्वारा किए गए आनुपातिक व्यय के बाद स्वीकृति के 90 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसमें सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ **अनुबंध-VII** में निर्धारित प्रारूप में एसपीवी द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर एलएलएमसी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दूसरी किस्त : भारत सरकार के कुल अंश के 30% हिस्से को पहली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने और स्वीकृति के 180 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसमें सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ **अनुबंध-VIII** में निर्धारित प्रारूप में एसपीवी द्वारा दावा प्रस्तुत करने और सरकारी वास्तुकार और सनदी लेखाकार द्वारा अनुमोदित 60 प्रतिशत या अधिक निर्माण पूरा करने के लिए एसपीवी द्वारा किए गए आनुपातिक व्यय के बाद जारी किया जाएगा।

दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर एलएलएमसी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

तीसरी किस्त : भारत सरकार के कुल अंश के 40% हिस्से को भवन/शेड का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा होने तथा एसपीवी द्वारा स्वीकृति के 270 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसमें सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ **अनुबंध-IX** में निर्धारित प्रारूप में दावा प्रस्तुत करने और सरकारी वास्तुकार और सनदी लेखाकार के प्रमाणीकरण के बाद जारी किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर एलएलएमसी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मशीनरी और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता इसकी खरीद, स्थापना, चालू किए जाने, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने और **अनुबंध-X** में निर्धारित प्रारूप में दावे को वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी। दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर एलएलएमसी वस्त्र आयुक्त कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

स्वामित्व/पट्टे के आधार पर पूर्व विद्यमान भवन सुविधाओं के साथ अनुमोदित सीएफसी के मामले में परियोजना के पूरा होने की समय सीमा पीएसी निर्णय के संप्रेषण की तिथि से केवल 01 वर्ष है और परियोजना की सब्सिडी पर कार्रवाई मशीनों की स्थापना और चालू किए जाने तथा एलएलएमसी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर की जाएगी।

अनुबंध-I

1. एसपीवी के द्वारा सीएफसी के लिए वित्तीय सहायता हेतु अपने प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जाने वाली कलस्टर की सूचना व उसका अध्ययन

1. स्थान : (राज्य, शहर/नगर/गांव)
2. एसपीवी/को-ऑपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी, कलस्टर में एसपीवी में प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति का पता, फोन नं., फैक्स, ई-मेल, मोबाइल नं. आदि सहित नाम

क.सं.	सदस्य का नाम	संपर्क विवरण (ई-मेल व मोबाइल)	एसपीवी में सदस्य का पद	सदस्य द्वारा अधिकृत निर्दिष्ट व निटवियर मशीनों की संख्या	सदस्य का अंशदान

3. एसपीवी का बैंक विवरण :
4. उत्पाद का नाम :
5. कलस्टर का स्वरूप :
 - (क) सूक्ष्म व लघु उद्यमों की कुल संख्या
 - (ख) प्रत्येक श्रेणी में उद्यमों की संख्या
 - i. सूक्ष्म
 - ii. लघु
 - iii. महिला के स्वामित्वाधीन
 - iv. आरक्षित जाति के स्वामित्वाधीन

- v. आरक्षित जनजाति के स्वामित्वाधीन
- vi. अल्पसंख्यकों के स्वामित्वाधीन
- (ग) निर्यात सहित कलस्टर की कुल कारोबार
- (घ) पुरुष/महिला कार्मिकों/यूनिट स्वामियों की औसत वार्षिक आय
- (ङ) प्रदूषण के लिए दृष्टिकोण, यदि कोई है तो
- 6. बड़ी कलस्टर समस्याएं: (प्राथमिक दृष्टिकोण एवं या दो पृष्ठ में दें)
- 7. सीएफसी के अधीन प्रस्तावित मुख्य हस्तक्षेप: तकनीकी सुधार/उत्पाद गुणवत्ता/विपणन/निर्यात/गुणवत्ता/डिजाइन आदि।
- 8. प्रतिस्पर्धा की सीमा: भारत या विदेशों में बड़ी घरेलू फर्मों या अन्य समान कलस्टरों के साथ (एक पृष्ठ में दें)
- 9. उस संगठन/समिति की नियुक्ति/नामांकन के विवरण सहित उसका नाम जिसने कलस्टर के अध्ययन का आंकलन/मूल्यांकन/निदान किया है।

2. सीएफसी के लिए वित्तीय सहायता हेतु एसपीवी द्वारा अपने प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए जांच बिन्दु:

- I. कलस्टर में कौन-सी समान सुविधाएं हैं तथा उनके समक्ष चुनौतियां
- II. वर्तमान सीएफसी इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार कर रहा है।
- III. 'सामान्य सुविधाओं' के रूप में क्या प्रस्तावित है? प्रत्येक का 2-3 वाक्यों में लाभ बताइए।
- IV. यदि इनमें से कोई सुविधा पहले ही उपलब्ध है तो उसका विवरण दें।
- V. वर्तमान में ये सुविधाएं कहां से उपलब्ध हो रही हैं। इन सुविधाओं की अनुपस्थिति में यूनिट किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं।
- VI. क्या आवश्यकता पूर्ति हेतु सरकार/गैर-सरकारी संगठन द्वारा कलस्टर या समीप में इस प्रकार की कोई अन्य सुविधा स्थापित की गई है।
- VII. क्या उपरोक्त सुविधा पूर्ण रूप से उपयोग की जा रही है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?
- VIII. कितनी यूनिटों ने यह पुष्टि की है की वे एसपीवी में शामिल होने जा रही हैं? सूची दी जाए।
- IX. क्या एसपीवी गठित की जा चुकी है? क्या एसपीवी में सदस्य अपना अंशदान देने के लिए सहमत है। (अंशदान, समावेशन/प्रमाण-पत्र संस्था के अंतर्नियम आदि के लिए सहमति हेतु औपचारिक पत्र)
- X. एसपीवी की प्रकृति (खुली या बंद) - क्या कलस्टर सदस्यों का पूंजीकरण भविष्य में किसी भी समय खुल जाएगा तथा उसके लिए एसपीवी की पूंजीगत संरचना में प्रावधान कर लिए गए हैं (प्रदत्त पूंजी प्राधिकृत पूंजी का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए)।
- XI. कितनी इकाइयां एसपीवी में शामिल हुए बिना प्रयोक्ता के रूप में सामान्य सुविधाओं को प्राप्त करने की इच्छुक हैं।
- XII. क्या उपयुक्त प्लांट व मशीनरी की पहचान की जा चुकी है। डीपीआर के उद्देश्य से मंगाई गई उनकी विशिष्टताएं और संविदाएं।
- XIII. प्रस्तावित सीएफसी हेतु डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी का नाम
- XIV. यदि ऋण लिया जाता है तो क्या बैंक से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
- XV. क्या राज्य सरकारें सीएफसी में अंशदान कर रही हैं। राज्य सरकारों के अंशदान के लिए पुष्टि की जाए।
- XVI. 'क्रय समिति' सहित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एसपीवी की समितियों का नाम
- XVII. कार्य की रिपोर्टिंग/मानिट्रिंग के लिए प्रबंध सूचना तंत्र (एमआईएस)

- XVIII. क्या प्लांट तथा मशीनरी की क्षमता क्लस्टर में मांग के आधार पर स्थापित की गई है? यह साक्ष्य कि सीएफसी अपनी क्षमता का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा।
- XIX. क्या निम्नलिखित के आधार पर भारत सरकार की सहायता प्राप्त करने हेतु व्यवहार्यता अंतर के वित्त पोषण की गणना की गई है।
(क) सीएफसी के लिए अत्यंत आवश्यक प्लांट व मशीनरी के प्रकार
(ख) प्लांट व मशीनरी की क्षमता तथा सीएफसी से सेवाओं की कुल मांग के आधार पर उनकी संख्या
- XX. क्या 'प्रयोक्ता शुल्क' निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किए गए हैं :
(क) क्या यह उत्पादन की लागत को पूरी करने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाएगा।
(ख) क्या मूल्यहास की गणना उल्लिखित मूल्यों पर की गई है? (प्लांट व मशीनरी के प्रचालन अवधि के दौरान कुल मूल्यहास की एसपीवी, प्लांट व मशीनरी की लागत के समान होनी चाहिए।)
(ग) प्रयोक्ता शुल्क भिन्न-भिन्न होंगे एक एसपीवी के सदस्य हेतु तथा अन्य गैर सदस्यों हेतु। सदस्यों हेतु प्रयोक्ता शुल्क इस प्रकार निर्धारित की जाए कि उनके द्वारा किए गए अंशदान के लिए उपयुक्त भरपाई हो सके।
- XXI. क्या सीएफसी प्रस्ताव प्रस्तावित सीएफसी के लिए अनुमानित लाभ-हानि लेखा तथा अनुमानित तुलन पत्र जैसे मूल टेम्पलेट का प्रयोग करके मूल्यांकन के वित्तीय नियमों जैसे रिटर्न की आंतरिक दर, लाभ-अलाभ की स्थिति का विश्लेषण, ऋण सेवा राशि का अनुपात, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि का अनुपालन करता है। पूर्ण विवरण दिया जाए।

सीएफसी के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव के साथ एसपीवी द्वारा प्रस्तुत दिए जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तत्व

(1) संयंत्र और मशीनरी

(क) प्लांट और मशीनरी की सूची

क्र० सं०	संयंत्र और मशीनरी का विवरण	संख्या	विद्युत आवश्यकता (एचपी/केडब्ल्यू)	एफओआर मूल्य (रु.)	प्रस्तावित पूर्तिकर्ता के नाम	डिलीवरी का कार्यक्रम (माह-वार)
----------	----------------------------	--------	-----------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

नोट : जीएसटी, पैकिंग तथा अग्रेषण शुल्क ट्रांजिट बीमा तथा कीमतों के लिए माल भाड़ा प्रभार।

(ख) एकल शिफ्ट आधार पर प्लांट व मशीनरी की क्षमता।

(ग) उत्पादन की प्रगति

(2) 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर कच्चे माल तथा उपभोज्यों की वार्षिक आवश्यकता

क्र० सं०	कच्चे माल का विवरण	पूर्ण क्षमता में आवश्यक मात्रा	इकाई मूल्य (रु.)	कुल मूल्य (रु.)
----------	--------------------	--------------------------------	------------------	-----------------

(3) पूर्ण क्षमता प्रयोज्यता पर उपयोगिता व सेवाएं

(क) औद्योगिक उद्देश्य के लिए विद्युत

क्र० सं०	मशीनरी के विवरण	केडब्ल्यू	प्रतिमाह काम करने के घंटों की संख्या	केडब्ल्यू/माह	रु./केडब्ल्यू/एच	कुल
----------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---------------	------------------	-----

(ख) घरेलू प्रयोजन हेतु विद्युत आवश्यकता।

(ग) जल।

(घ) गैस/तेल।

(4) संयंत्र की अवस्थिति, सिविल निर्माण, स्थल तथा विवरण

क्र० सं०	विवरण	दर	कुल लागत (लाख रु. में)
(i)	भूमि की लागत		
(ii)	भूमि की विकास लागत तथा उसका विकास, यदि कोई है।		
(iii)	सीएफसी के प्रयोजन हेतु अहाते की दीवार, यदि कोई हो, सहित शैड/भवन के निर्माण की लागत		

- जमीन के दस्तावेजों को संलग्न किया जाए, जिसमें यह दर्शाया जाए कि क्या वह क्रय या लीज आधार पर एसपीवी के नाम पर है।
- जमीन के लिए एनए प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए।
- भवन विन्यास व भवन योजना अनुमोदन संलग्न किया जाए।
-

(5) संगठनात्मक संरचना तथा श्रमशक्ति की आवश्यकता

➤

क्र० सं०	श्रेणी	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिमाह वेतन (रु.)	कुल वेतन (पीएम)

नोट : गौण लाभ हेतु 25 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़त को जोड़ा जाए

(6) परियोजना की लागत

क.सं.	लागत का विवरण	राशि (रु.)
(i)	भूमि व स्थल विकास लागत (कुल क्षेत्र)	
(ii)	सीएफसी के प्रयोजन के लिए भवन/शैड (कुल निर्माण वर्ग.मी.) लागत में विविध निश्चित संपत्ति (फिक्चर, फर्नीचर, दमकल उपकर, प्राथमिक उपचार उपकरण, बैकअप पावर सप्लाई आदि) शामिल होंगी।	
(iii)	प्लांट व मशीनरी (प्लांट व मशीनरी की लागत + 10% इंस्टालेशन, विद्युतीकरण तथा कमिशनिंग)	
(iv)	प्राथमिक व्यय (नैदानिक अध्ययन, डीपीआर विधिक व प्रशासनिक व्यय, टेलीफोन, स्टेशनरी आदि)	
(v)	प्रचालन पूर्व व्यय (स्थापन, यात्रा, ऋण पर ब्याज, निर्माण अवधि के दौरान लगे शुल्क, आरम्भ करने में व्यय आदि)	
(vi)	आकस्मिक व्यय (2% भवन तथा 5% प्लांट व मशीनरी पर) हेतु प्रावधान	

(vii)	कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन राशि	
	कुल	

(7) वित्त के साधन

क.सं.	एजेंसी	राशि (लाख रु.)	परियोजना लागत का %
1.	एसपीवी		
2.	भारत सरकार		
3.	राज्य सरकार यदि कोई है		
4.	बैंक ऋण		
5.	अन्य		

(8) कार्यशील पूंजी तथा मार्जिन राशि की गणना (वर्षवाट वास्तविक क्षमता प्रयोज्यता के आधार पर)

क.सं.	विवरण	महीनों की संख्या	मार्जिन	प्रथम वर्ष (क्षमता उपयोग के अनुसार)	द्वितीय वर्ष (क्षमता उपयोग के अनुसार)	तृतीय वर्ष (क्षमता उपयोग के अनुसार)
1.	कच्चा माल व उपयोगी वस्तुएं					
2.	उपकरण					
3.	कार्य व्यय (श्रमशक्ति का वेतन)					
4.	प्रक्रिया में कार्य (कच्चे माल की लागत)					
5.	वास्तविक पर उपयोगिता व वेतन					
6.	बिल प्राप्य (ब्रिकी मूल्य)					

सीएफसी की वित्तीय व्यवहार्यता के विस्तृत मानक तथा इसके वित्तीय व्यवहार्य होने का संभावित वर्ष (लाख रु. में)

कार्यशील खर्चे **		राजस्व **	
1. वेतन		1. राजस्व स्ट्रीम-1 (वर्णन दें)	
2. उपभोज्य		2. राजस्व स्ट्रीम-2 (वर्णन दें)	
3. गिरावट		3.	
4. अन्य (वर्णन दें)		4.	
5. कुल		5. कुल	

** नोट : कृपया व्यवहार्यता की प्राप्ति तक वर्णवार तथ्य दें।

(9) उत्पादन की लागत (तथ्यों का अनुमान अधिकतम 10 वर्ष की परियोजना प्रचालन अवधि के लिए हो)

- (i) उपभोज्य तथा कच्चा माल
- (ii) उपयोगिता
- (iii) मेहनताना व वेतन
- (iv) मरम्मत व रखरखाव
- (v) बीमा
- (vi) प्रशासनिक व फैक्ट्री उपरिव्यय
- (vii) बिक्री व्यय

(10) लाभप्रदता का अनुमान (परियोजना के जीवनकाल का अनुमान)

- (i) संस्थापित क्षमता
- (ii) कार्य में दिनों की संख्या (एकल शिफ्ट आधार पर)
- (iii) क्षमता उपयोग
- (iv) उत्पादन (एक यूनिट में)
- (v) बिक्री वसूली
- (vi) उत्पादन की लागत
- (vii) सकल लाभ [(v)-(vi)]
- (viii) वित्तीय व्यय
 - (क) बैंक ऋणों पर ब्याज
- (ix) लिखित मूल्य पद्धति पर मूल्यहास (उसी अनुसार अचल संपत्तियों की विविध श्रेणियों के लिए अलग से सारणी संलग्न की जाए)
- (x) बट्टे खाते नहीं डाले गए
- (xi) प्रचालन लाभ [(vii)-{(viii) + (ix) + (x)}]
- (xii) प्रथम सारणी के अनुसार टैक्स
- (xiii) कर पश्चात् लाभ [(xi) - (xii)]
- (xiv) उपलब्ध अधिशेष [(xiii) + (ix)]

(11) नकद प्रवाह विवरण (परियोजना अवधि हेतु अनुमान)

- (क) निधि के स्रोत:
 - (i) मूल्यहास रहित कुल लाभ
 - (ii) सावधि ऋण
 - (iii) सब्सिडी/अनुदान
 - (iv) प्रवर्तक अंशदान
 - (v) बैंक ऋणों में वृद्धि
 - (vi) मूल्यहास
- (ख) निधियों का निपटान:
 - (i) प्राथमिक व कार्य पूर्व खर्च
 - (ii) पूंजीगत व्यय
 - (iii) कार्यशील पूंजी में वृद्धि
 - (iv) आवधिक ऋण पर ब्याज
 - (v) बैंक ऋणों पर ब्याज

(vi) आवधिक ऋणों में गिरावट

(vii) कर

(ग) नकद या बैंक में अथशेष [{(क) – (ख)} का कुल मूल्य]

(घ) शुद्ध अधिशेष/धारा

(ङ) नकद या बैंक में इतिशेष

(12) ऋण सेवा कवरेज अनुपात)परियोजना अवधि के लिए अनुमानित)

(i) सारणी में क.सं. 10 (xiv) के अनुसार उपलब्ध अधिशेष

(ii) आवधिक ऋण पर व्याज

(iii) आवधिक ऋण किस्त

ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) = [उपलब्ध अधिशेष + आवधिक ऋण पर व्याज] / [आवधिक ऋण किस्त + आवधिक ऋण पर व्याज]

(13) तुलन-पत्र व पी/एल खाता (10 वर्षों के लिए अनुमान)

(14) विवरण = निश्चित लागत / अंशदान = बिक्री – विविध लागत)

अनुबंध-II

पावरटैक्स इंडिया के अधीन सामान्य सुविधा केन्द्र की मंजूरी हेतु आवेदन।

क.सं.	विवरण				ब्यौरा		
1.	एसपीवी का नाम व पता, जापन की प्रति तथा संस्था के अंतर्नियम आरओसी/साझेदारी विलेख/सोसायटी पंजीकरण जैसा भी मामला हो।						
	क.सं.	सदस्य का नाम	संपर्क का नाम	संपर्क विवरण (ई-मेल व मोबाइल)	एसपीवी में सदस्यता पद	सदस्य द्वारा अधिकृत निर्दिष्ट निटबियर यूनिटों की संख्या	सदस्य का अंशदान
	एसपीवी का संपर्क मोबाइल नं. तथा ई-मेल आईडी						
	डीपीआर के साथ सीएफसी स्थापित होने हेतु प्रस्तावित कलस्टर का नाम						
	प्रति के साथ समूह के सदस्य की पश्चात का प्रभाव (पैन कार्ड/बैंक पासबुक/आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर कार्ड)						
	जहां सीएफसी स्थापित होनी है वहां एसपीवी का पूरा पता						
	क. प्रस्तावित स्थान (अधिकृत/लीज पर) के लिए भूमि/भवन दस्तावेजों का क्षेत्र। पंजीकृत विलेख प्रति कैसा भी मामला हो। ख. फैक्ट्री भवन का साईज						
	वित्त के साधन :						

क.सं.	संघटक	प्रवर्तन अंशदान	भारत सरकार सब्सिडी	वैक ऋण	
1.	फैक्ट्री निर्माण				
2.	प्लांट व मशीनरी				
3.	अन्य पात्र निवेश				
कुल					

स्थान :

दिनांक :

(एसपीवी के हस्ताक्षर)

.....

कार्यालय प्रयोग हेतु :

दिनांक को प्रस्तावित सीएफसी के स्थल का मुआयना किया गया तथा एसपीवी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तथा प्रस्ताव की मंजूरी हेतु संस्तुति की जाती है। निम्न कारणों से संस्तुति नहीं की जाती है।

कार्यालय प्रभारी के हस्ताक्षर

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय,

अनुबंध-III

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची।

1. एसपीवी के नाम पर जमीन के पंजीकरण की प्रति या कम से कम दस वर्ष की पंजीकृत लीज विलेख की प्रति, जो लागू हो।
2. संबंधित ग्राम पंचायत/जिला नगर योजना प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण डाटा जारी गैर-कृषि भूमि प्रमाण-पत्र।
3. संबंधित ग्राम पंचायत/जिला नगर योजना प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण, जो भी लागू हो, द्वारा अनुमोदित सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण का लेआउट प्लान।

अनुबंध-IV

सीएफसी की स्थानीय स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी (एलएलएमसी) का रिपोर्टिंग प्रारूप।

क.सं.	एलएलएमसी का विवरण	एलएलएमसी की अनुशंसा
1.	सीएफसी का नाम व पता	
2.	एलएलएमसी की तिथि	
3.	बैठक का स्थान	
4.	एलएलएमसी का स्तर	
5.	वर्तमान एलएलएमसी सदस्यों के नाम	

6.	वर्कशेड/मशीनरी की संस्थापना की वर्तमान स्थिति	
7.	निर्मित वर्कशेड का क्षेत्र	
8.	अब तक हुई वित्तीय प्रगति	
9.	चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र	
10.	चार्टर्ड लेखा प्रमाण-पत्र	
11.	अनुमोदित वर्कशेड का कुल क्षेत्र	
12.	भारत सरकार की स्वीकृत सब्सिडी	
13.	भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	
14.	पूर्ण हो चुका वर्तमान क्षेत्र/शेड निर्माण	
15.	पूर्ण हो चुके कार्य का प्रतिशत	
16.	प्रस्तावित मशीनरी का विवरण	
17.	संस्थापित मशीनरी की संख्या	
18.	अनुशंसित पात्र सब्सिडी	
19.	दिनांक व समय सहित फोटोग्राफ	
20.	समग्र टिप्पणी	

एलएलएमसी के हस्ताक्षर

अनुबंध-V

निटिंग व निटवियर कलस्टर की ग्रेडिंग का मानदण्ड

क.सं.	मानदंड	कुल अंक	समिति द्वारा दिए गए अंक
1.	निटिंग व निटवियर मशीनरी की कुल संख्या	10	
2.	तकनीकी स्तर	25	
3.	उत्पाद प्रोफाइल		
	कम मूल्य के फैब्रिक		
	मध्यम स्तरीय		
	अप स्तरीय		
	मूल्य वर्द्धित		
4.	अवसंरचना	10	
	प्रारंभिक स्तर		
	जांच सुविधाएं		
	यार्न डिपो/यार्न की उपलब्धता		
	विद्युत उपलब्ध तथा उसका मूल्य		

	निटिंग पश्च		
	परिवहन, जल, संचार		
5.	बाजार पहुंच	15	
	निर्यात व उसका मूल्य, क्लस्टर के कुल उत्पाद का प्रतिशत		
	घरेलू उसका मूल्य, क्लस्टर के कुल उत्पाद का प्रतिशत		
6.	कुशल श्रमशक्ति उपलब्धता	10	
7.	क्लस्टर में बैंक/वित्तीय संस्थान	5	
8.	निजी उत्पादन/जॉबवर्क उत्पादन	5	
	कुल	100	

दिए गए अंकों के आधार पर ग्रेडिंग

40 तक	—	घ
41 से 60	—	ग
61 से 75	—	ख
75 से अधिक	—	क

अनुबंध-VI

अनुदान जारी किए जाने से पहले निष्पादन हेतु निर्धारित एक सौ रूपए के न्यायिक पेपर पर जमानती बंध पत्र का नमूना

इस विलेख द्वारा सभी लोगों को ज्ञात हो कि हम मैसर्स , कंपनी अधिनियम.....सरकार की सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समिति के तहत निगमित कंपनी औरमें स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय (इसमें इसके पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा जाएगा)रूपए (.....रूपए मात्र) के लिए भारत के राष्ट्रपति (इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा जाएगा) के प्रति पूर्ण और पक्के तौर पर आबद्ध अभिनिर्धारित किया जाता है, जिसे मांग पर और बिना आपत्ति के सरकार को ठीक और सही तौर पर भुगतान किया जाना है। जिसके भुगतान के लिए हम अपने आपको और अपने उत्तराधिकारियों को और इन अभिलेखों द्वारा पक्के तौर पर आबद्ध करते हैं।

वर्ष दो हजार की तारीख केको हस्ताक्षरित।

अतः बाध्यताधारियों के अनुरोध पर वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक के मंजूरी आदेश संख्या (इसमें इसके पश्चात् "मंजूरी पत्र" के रूप में उल्लिखित), जो इन अभिलेखों का अमिल मांग है और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और अनुबंध-I के रूप में चिह्नित है, सरकारमें वर्कशेड के निर्माण और मशीनों के प्रतिष्ठापन के प्रयोगनार्थ बाध्यताधारियों के पक्ष मेंरूपए (.....रूपए) का अनुदान करने पर सहमत है, जिसमें सेरूपए (.....रूपए मात्र) का भुगतान बाध्यताधारियों (जिसकी पावती बाध्यताधारियों द्वारा एतद् द्वारा स्वीकृत और अभिस्वीकृत की जाती है।) को इस शर्त पर किया गया है कि बाध्यताधारी इसमें इसके पश्चात् निहित शर्तों और ढंग से एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे जिस पर बाध्यताधारी ऐसा करने पर सहमत हुए हैं।

अब उक्त लिखित बाध्यता की शर्तें ऐसी हैं कि यदि बाध्यताधारियों द्वारा मंजूरी पत्र में उल्लिखित शर्तों को विधिवत रूप से पूरा किया जाता है और अनुपालन किया जाता है तो उक्त बंध पत्र या बाध्यता शून्य और प्रभावहीन हो जाएगी। लेकिन अन्यथा यह पूर्णतया और सत्यतापूर्ण प्रवृत्त रहेगा। बाध्यताधारी, अनुदान की निबंधन और शर्तों का लक्ष्यगत तारीख तक, यदि उसमें कोई विनिर्दिष्ट की गई हों, का पालन करेंगे।

कि बाध्यताधारी, अनुदानों का अपयोजन नहीं करेंगे और योजना अथवा संबंधित कार्य का निष्पादन किसी अन्य संस्था (संस्थाओं) अथवा संगठन (संगठनों) को नहीं सौंपेंगे।

कि बाध्यताकारी, इस करार में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तों का पालन करेंगे और शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा बंध पत्र मांग किए जाने की स्थिति में बाध्यताकारी और व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से जमानती, अनुदान की पूरी राशि उस पर 10% वार्षिक ब्याज के साथ भारत के राष्ट्रपति को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि अनुदान की कोई मांग उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् अव्ययित रहता है, जिसके अंदर इसे व्यय करना अपेक्षित है और यदि इसे अग्रणीत किए जाने पर सहमति न हुई हो तो सरकार को यह राशि लौटाए जाने की तारीख तक इस पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी।

बाध्यताकारी ऐसे सभी धन संबंधी अथवा अन्य लाभों का मौद्रिक मूल्य सरकार को अभ्यर्पण/भुगतान करने पर सहमत होंगे और वचन देंगे, जिसके काफी हद तक भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय अथवा संबंधित विभाग के प्रशासनाध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए अनुदान से सृजित/अधिग्रहित निर्मित भवन/मशीनरी के अप्राधिकृत उपयोग (यथायोग्य प्रतिफल अथवा यथायोग्य प्रतिफल से कम पर परिसरों को किराए पर देना अथवा परिसरों का उस प्रयोजन को छोड़कर जिस संपत्ति के लिए अनुदान आशयित था, ऐसा किए जाने से प्राप्त अथवा व्युत्पन्न कर सकते हैं अथवा प्राप्त अथवा व्युत्पन्न किया हो। जहां तक सरकार को अभ्यर्पित/भुगतान किए जाने वाले उल्लिखित मौद्रिक मूल्य का संबंध है, परियोजना अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यताकारियों पर बाध्यकारी होगा।

और ये विलेख इसके भी साक्षी हैं कि

i). इस प्रश्न पर सचिव, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय का निर्णय कि क्या मंजूरी पत्र में उल्लिखित निबंधन और शर्तों को भंग अथवा उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं, अंतिम होगा और बाध्यताकारियों पर बाध्यकारी होगा और;

ii). सरकार इन विलेखों पर देय स्टॉप शुल्क वहन करेगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप इन विलेखों को बाध्यताकारी के शासी निकाय द्वारा दिनांक के संकल्प सं. जिसकी एक प्रति इसके साथ अनुबंध-II के रूप में संलग्न है, की ओर से और जमानतियों की ओर से और राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से नीचे की गई तारीख को निम्नानुसार निष्पादित किया गया है :-

.....के लिए

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षरित

(बाध्यताकारी का नाम)

1. गवाह के हस्ताक्षर

2. गवाह के हस्ताक्षर

नाम और पता

नाम और पता

.....

.....

.....

.....

वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा भरा जाना है
(स्वीकृत)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

पदनाम

दिनांक:

अनुबंध-VII

सीएफसी योजना के तहत 30 प्रतिशत सब्सिडी की पहली किस्त जारी किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ एसपीवी के दावे के आवेदन का प्रपत्र (मंजूरी की तारीख से 90 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाता है।)

दिनांक :

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

.....

.....

महोदय,

हम इसके साथ सामान्य सुविधा केन्द्र योजना के लिए भारत सरकार की पहली किस्त जारी किए जाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आगे की आवश्यकता कार्रवाई के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं :-

1. सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण में किए गए व्यय का सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र।
2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार का आनुपातिक व्यय प्रमाण-पत्र।
3. कोई अन्य ब्यौरा।

आपसे अनुरोध है कि एलएलएमसी सत्यापन करें और अपनी अनुशंसा के साथ वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(एसपीवी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-VIII

भवन निर्माण के लिए भारत सरकार की सब्सिडी की 30 प्रतिशत की दूसरी किस्त जारी किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ एसपीवी के दावे के आवेदन का प्रपत्र (मंजूरी की तारीख से 180 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना है।)

दिनांक :

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

.....

.....

महोदय,

हम इसके साथ भवन निर्माण के लिए पावरटेक्स इंडिया की सीएफसी योजना के तहत भारत सरकार की सब्सिडी की 30 प्रतिशत की दूसरी किस्त जारी किए जाने के लिए अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

1. सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण में किए गए व्यय का सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र।
2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार का आनुपातिक व्यय प्रमाण-पत्र।

3. एसपीवी द्वारा संपन्न और मशीनरी की खरीद के लिए सावधि ऋण हेतु बैंक का मंजूरी पत्र।
4. पहली किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी)
5. अन्य कोई ब्यौरा।

आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र आवश्यक एलएलएमसी सत्यापन करें और अपनी अनुशंसा के साथ उसे वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को अग्रेषित करें।

भवदीय,

(एसपीवी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-IX

भवन निर्माण के लिए भारत सरकार की सब्सिडी की 40 प्रतिशत की तीसरी किस्त जारी किए जाने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ एसपीवी के आवेदन का फॉर्मेट (मंजूरी की तारीख से 360 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना है।)

दिनांक :

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

.....

.....

महोदय,

हम इसके साथ पावरटेक्स इंडिया की सीएफसी योजना के तहत भवनों के निर्माण के लिए भारत सरकार की सब्सिडी की तीसरी किस्त जारी किए जाने हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं:-

1. सामान्य सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिए किए गए व्यय का सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र।
2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार का आनुपातिक व्यय और निर्माण कार्य पूरा किए जाने का प्रमाण-पत्र।
3. संयंत्र और मशीनरी हेतु दिए गए आदेश के दस्तावेज और एसपीवी द्वारा मशीनरी के आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम/जारी की गई टोकन राशि।
4. दूसरी किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी)
5. प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों का प्रमाण-पत्र, यथा लागू
6. कोई अन्य ब्यौरा।

आपसे

आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र आवश्यक एलएलएमसी सत्यापन करें और अपनी अनुशंसा के साथ उसे वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को अग्रेषित करें।

भवदीय,

(एसपीवी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-X

सीएफसी योजना के तहत मशीनरी संस्थापित किए जाने के लिए भारत सरकार की सब्सिडी जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ एसपीवी के आवेदन का प्रपत्र (मंजूरी की तारीख से 18 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना है)

दिनांक :

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय

.....

.....

महोदय,

पावरटेक्स इंडिया की सीएफसी योजना के तहत मशीनरी संस्थापित किए जाने के लिए भारत सरकार की सब्सिडी जारी किए जाने हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं:-

1. संयंत्र और मशीनरी पर किए गए व्यय का सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र।
2. एसपीवी संस्थापित करने पर संयंत्र और मशीनरी का बिल।
3. भवन निर्माण के लिए तीसरी किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र।
4. कोई अन्य ब्यौरा।

आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र आवश्यक एलएलएमसी का सत्यापन करें और अपनी अनुशंसा के साथ उसे वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को अग्रेषित करें।

भवदीय,

(एसपीवी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अपेक्षित दस्तावेजों का सारांश और जांच सूची

निटिंग और निटवियर क्षेत्र के तहत सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) योजना

चरण	उद्देश्य	आवश्यकता	अपेक्षित दस्तावेजों की जांच सूची	दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के चरण
1.	सीएफसी की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र	वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में निष्पादन एजेंसी (ईए) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है	निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिशा-निर्देशों के अनुबंध-II में आवेदन पत्र 1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2. एसपीवी का स्वरूप 3. एसपीवी के नाम पर भूमि/ भवन का बिक्री/पट्टा विलेख 4. गैर-कृषि भूमि प्रमाण-पत्र 5. अनुमोदित लेआउट प्लान	आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दौरान
2.	वस्त्र आयुक्त के	अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से	निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ	

	कार्यालय को आवेदन पत्र अग्रेषित करना	30 नि के अंदर आरओ को आवेदन पत्र निटिंग और विद्युतकर विकास सैल को अग्रेषित करना है	दिशा-निर्देशों के अनुबंध-II में आवेदन पत्र 1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2. एसपीवी का स्वरूप 3. एसपीवी के नाम पर भूमि/ भवन का विक्री/पट्टा विलेख 4. गैर-कृषि भूमि प्रमाण-पत्र 5. अनुमोदित लेआउट प्लान	
3.	30% की पहली किस्त जारी किए जाने का दावा	ईए को मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के अंदर दावा करना है। संबंधित आरओ को 30% निर्माण कार्य पूरा होने के बारे में सूचित करें 3. आरओ को एलएलएमसी दौरे की तारीख से 30 दिन के अंदर पीडीसी को एलएलएमसी रिपोर्ट अग्रेषित करनी है।	1. वर्कशेड के निर्माण में हुए व्यय का सीए प्रमाण-पत्र 2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार का आनुपातिक व्यय प्रमाण-पत्र 3. निर्माणाधीन भवन की फोटो	एलएलएमसी दौरे के दौरान
4.	30% की दूसरी किस्त जारी किए जाने का दावा	1. ईए को मंजूरी की तारीख से 180 दिनों के अंदर दावा करना है। 2. संबंधित आरओ को 60% निर्माण कार्य पूरा होने के बारे में सूचित करें। 3. आरओ को एलएलएमसी दौरे की तारीख से 10 दिनों के अंदर पीडीसी को एलएलएमसी रिपोर्ट अग्रेषित करनी है।	1. वर्कशेड के निर्माण में हुए व्यय का सीए प्रमाण-पत्र 2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार का आनुपातिक व्यय प्रमाण-पत्र 3. पहली किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र 4. प्रत्येक लाभार्थी/ईए के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु सावधि ऋण के लिए बैंक का मंजूरी पत्र 5. निर्माणाधीन भवन की फोटो	एलएलएमसी दौरे के दौरान
5.	40% की तीसरी किस्त जारी किए जाने का दावा	1. ईए को मंजूरी की तारीख से 270 दिनों के अंदर दावा करना है। 2. संबंधित आरओ को 100% निर्माण कार्य पूरा होने के बारे में सूचित करें। 3. आरओ को एलएलएमसी दौरे की तारीख से 10 दिनों के अंदर पीडीसी को एलएलएमसी रिपोर्ट अग्रेषित करनी है।	1. वर्कशेड के निर्माण में हुए व्यय का सीए प्रमाण-पत्र। 2. सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तुकार का आनुपातिक व्यय प्रमाण-पत्र। 3. दूसरी किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र 4. एसपीवी द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए दिए गए आदेश के दस्तावेज और जारी किया गया अग्रिम/टोकन राशि। 5. निर्मित भवन की फोटो।	एलएलएमसी दौरे के दौरान
6.	संयंत्र और मशीनरी के लिए सब्सिडी जारी किए जाने हेतु	ईए को मंजूरी की तारीख से 18 माह के अंदर दावा करना है।	1. संयंत्र और मशीनरी पर हुए व्यय का सीए प्रमाण-पत्र।	एलएलएमसी दौरे के दौरान

	दावा	2. संबंधित आरओ को संयंत्र और मशीनरी संस्थापित और चालू किए जाने के बारे में सूचित करें। 3. आरओ को एलएलएमसी दौरे की तारीख से 10 दिनों के अंदर पीडीसी को एलएलएमसी रिपोर्ट अग्रेषित करनी है।	2. संयंत्र और मशीनरी की इंवाइसेज प्रस्तुत करना। 3. तीसरी किस्त का उपयोग प्रमाण-पत्र। 4. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र। 5. संयंत्र और मशीनरी की फोटो।	
--	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

VII. निटिंग और निटवियर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना

1. उद्देश्य

- भारत में क्लॉथिंग उद्योग (निटवियर और बुने हुए) बिखरा है और यह मूल रूप से एसएसआई क्षेत्र है। यह उद्योग कलस्टर केंद्रित दृष्टिकोण पर कार्य करता है, जिससे कच्ची सामग्री, सेवा और ग्राहकों के संदर्भ में स्पष्ट लाभ प्राप्त है। यद्यपि यह क्षेत्र बिखरा हुआ क्षेत्र है, फिर भी प्रत्येक कलस्टर काफी हद तक विविधता और विशिष्टता लिए हुए हैं। **तिरुपुर, लुधियाना और कोलकाता निटिंग और निटवियर के मुख्य केन्द्र रहे हैं।**
- कुल वैश्विक अपैरल व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 3.6% है और इसका छठा स्थान है। भारत परिधान की एक सौ से अधिक उत्पाद श्रेणियों का निर्यात करता है, जिसमें मुख्यतः कॉटन, अर्द्ध-फैशन औसत मूल्य सेगमेंट के कैजुअल वस्त्र शामिल हैं। जिनमें फिर टी-शर्ट, पुरुषों की टी-शर्ट, महिलाओं के ब्लाउज, महिलाओं के परिधान और स्कर्ट आती है। क्लॉथिंग के समग्र निर्यात में मूल्य के संदर्भ में निटेड परिधानों का हिस्सा लगभग 38% है, जबकि मात्रा के संदर्भ में यह 53% है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन दो क्षेत्रों में निटेड क्षेत्र बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और कुछ समय से यह वोवन गारमेंट क्षेत्र को पीछे छोड़ने में सफल रहा है।
- अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए समय पर धनराशि न मिलने के कारण विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयां/उद्यमी अपने उत्पादों में विविधता नहीं ला पा रहे हैं और मशीनों का आधुनिकीकरण नहीं कर पा रहे हैं।
- उपर्युक्त परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों/उद्यमियों को और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा देश में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना काफी आवश्यक है।
- उपर्युक्त के संदर्भ में भारत सरकार ने "निटिंग और निटवियर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ऋण योजना" शुरू करने का निर्णय लिया। जिसका उद्देश्य निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों को लचीले और किफायती ढंग से पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि निवेश की जरूरतों (सावधि ऋण) के लिए उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह योजना देश के सभी निटवियर कलस्टरों में क्रियान्वित की जाएगी। ऋण सुविधा, पीएमएमवाई (मुद्रा) और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत शामिल सभी ऋणदायी एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

2. क्रियान्वयन प्रक्रिया

क.सं.	विवरण	श्रेणी-I (पीएमएमवाई के तहत)	श्रेणी-II (स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत)
1.	पात्रता	पात्र इकाइयां ये हैं : क. निटिंग और निटवियर कार्य करने वाले केवल वे नए व्यक्तिगत/सामूहिक उद्यमी जो एमएसएमई/उद्योग आधार में पंजीकृत हैं। ख. तथापि, सामूहिक उद्यमों को सरकार की ऋण गारंटी सहायता के बगैर और ऋणदायी एजेंसी के प्रचलित मानदण्डों के अनुसार योजना में शामिल	पात्र इकाइयां ये हैं : क. केवल वे नई निटिंग और निटवियर इकाइयां जिन्हें उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया हो, जो अनुसूचित जाति (एससी) अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा महिला उद्यमी हो। जिन्हें एमएसएमई/उद्योग आधार में पंजीकृत किया गया हो।

		<p>किया जाएगा।</p> <p>ग. इकाई ने उन आस्तियों के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त न की हो। जिनके लिए पीएमएमवाई के तहत लाभ प्राप्त कर लिए गए हों।</p>	<p>ख. गैर-व्यक्तिगत इकाइयों के मामले में शेयरधारिता और नियंत्रक स्टैक का कम से कम 50% या तो एससी (अथवा) एसटी (अथवा) महिला उद्यमी के पास हो।</p> <p>ग. इकाई ने उन आस्तियों के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त न की हो। जिनके लिए पीएमएमवाई के तहत लाभ प्राप्त कर लिए गए हों।</p>
2.	सुविधा का प्रकार और ऋणराशि	<p>क. साविध ऋण प्राप्त किया जाना है।</p> <p>ख. अधिकतम 10 लाख रूपए का ऋण</p> <p>ग. योजना के तहत केवल नए ऋण पात्र हैं। उधारकर्ता द्वारा पहले से ही लिए गए ऋण योजना के तहत पात्र नहीं है।</p>	<p>क. मशीनरी की खरीद के लिए साविध ऋण लिया जाना है।</p> <p>ख. ऋण 10 लाख रूपए से अधिक और एक करोड़ रूपए तक का होगा।</p>
3.	उचित अध्यवसाय, वित्तीय बेंचमार्क लेखापरीक्षित वित्तीय दस्तावेजों की आवश्यकता, ऋण सीमा का निर्धारण	ऋणदायी एजेंसी के प्रचलित मानदण्डों के अनुसार	ऋणदायी एजेंसी के प्रचलित मानदण्डों के अनुसार
4.	योजना के तहत वित्तीय सहायता की वापसी अदायगी 1. मार्जिन मनी सब्सिडी	<p>बैंकों के प्रचलित मानकों के अनुसार</p> <p>क. परियोजना के लिए मार्जिन मनी का निर्णय ऋणदायी एजेंसी के मौजूदा मानकों के अनुसार ऋणदायी एजेंसी द्वारा लिया जाएगा। सरकार, उधारकर्ता के लिए एक लाख रूपए की अधिकतम सीमा के साथ मूल लागत का 20 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मार्जिन मनी की शेष राशि उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।</p>	<p>बैंकों के प्रचलित मानकों के अनुसार</p> <p>ख. योजना में 25 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन स्थापित की गई नई मशीनरी की मूल लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।</p> <p>ग. उधारकर्ता को अपने योगदान के रूप में मशीनरी की लागत का 10 प्रतिशत लगभग होगा।</p>
5.	ब्याज आर्थिक सहायता	<p>क. साविध ऋण पर ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>ख. पहले संवितरण की तारीख से पांच वर्ष तक साविध ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि जहां वापसी अदायगी की अवधि पांच वर्ष से अधिक है वहां साविध ऋण भी पात्र हो जाएगा।</p> <p>लाभार्थी द्वारा ब्याज का भुगतान कर दिए जाने के बाद ऋणदायी एजेंसी, वस्त्र आयुक्त को प्रत्येक तिमाही के अंत में भुगतान की जाने वाली ब्याज सब्सिडी की राशि का ब्यौरा भेजेगी, वस्त्र आयुक्त उसे जारी करेंगे।</p>	लागू नहीं
6.	सीमा, प्रतिभूति, ब्याज दर और अन्य प्रभावों की वैधता/नवीकरण	ऋणदायी एजेंसी के प्रचलित मानकों के अनुसार पावरटेक्स मुद्रा ऋण के लिए संपार्श्विक/प्रतिभूति दी जानी अपेक्षित नहीं है।	ऋणदायी एजेंसी के प्रचलित मानकों के अनुसार
7.	ऋण गारंटी की	राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) योजना के तहत माइक्रो इकाइयों के लिए	राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) योजना के तहत स्टैंड-अप इंडिया के लिए

	प्रतिभूति	सीजीटीएमएसई/ऋण गारंटी योजना के तहत अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी हेतु ऋणराशि का 1 प्रतिशत या फीस की वास्तविक राशि, जो भी कम हो, वसूल की जाती है। सामूहिक उद्यमियों के लिए लागू नहीं।	सीजीटीएमएसई/ऋण गारंटी योजना के तहत अधिकतम पांच वर्ष के लिए ऋण गारंटी हेतु ऋण राशि का 1 प्रतिशत अथवा फीस की वास्तविक राशि, जो भी कम हो, वसूल की जाती है।
8.	भारत सरकार की सहायता	<p>क. पहले संवितरण की तारीख से पांच वर्ष तक सावधि ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि जहां वापसी अदायगी की अवधि पांच वर्ष से अधिक है वहां सावधि ऋण भी पात्र हो जाएगा।</p> <p>ख. परियोजना के लिए मार्जिन मनी का निर्णय ऋणदायी एजेंसी के मौजूदा मानकों के अनुसार ऋणदायी एजेंसी द्वारा लिया जाएगा। सरकार, उधारकर्ता के लिए एक लाख रूपए की अधिकतम सीमा के साथ स्थापित की गई मशीनरी की मूल लागत का 20 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।</p> <p>ग. वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे जो फिर ऑनलाइन मोड से आवेदन(नों) को संबंधित बैंकों को अग्रेषित करेगा।</p> <p>घ. पहली बार मार्जिन मनी सन्डि/व्याज आर्थिक सहायता के लिए दावा प्रस्तुत किए जाने से पहले संयुक्त निरीक्षण टीम (जेआईटी) द्वारा अनुबंध-III में यथा निर्धारित फॉर्मेट में दावे के विवरणों को सत्यापित किया जाएगा। इस टीम में बैंक शाखा और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के पीएससी/आरओ के सदस्य होंगे, निरीक्षण का व्यौरा आई पावरटेक्स इंडिया में अपलोड किया जाएगा।</p>	<p>क. योजना में 25 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन स्थापित की गई नई मशीनरी की मूल लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सन्डि के रूप में प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।</p> <p>ख. वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय को आई पावरटेक्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे जो फिर ऑनलाइन मोड के माध्यम से संबंधित बैंकों को आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे।</p> <p>ग. पहली बार मार्जिन मनी सन्डि के लिए दावा प्रस्तुत किए जाने से पहले संयुक्त निरीक्षण टीम (जेआईटी) द्वारा अनुबंध-III में यथा निर्धारित फॉर्मेट में दावे के विवरणों को सत्यापित किया जाएगा, निरीक्षण रिपोर्ट आई पावरटेक्स इंडिया में अपलोड की जाएगी।</p>
9.	भारत सरकार की सन्डि जारी किए जाने का माध्यम	<p>क. मार्जिन मनी सन्डि, संबंधित ऋणदायी एजेंसी के माध्यम से उधारकर्ता के सावधि ऋण खाते में जमा की जाएगी।</p> <p>ख. ऋण गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति, वार्षिक आधार पर ऋणदायी एजेंसी के माध्यम से उधारकर्ता के सावधि खाते में जमा की जाएगी।</p>	<p>क. मार्जिन मनी सन्डि, संबंधित ऋणदायी एजेंसी के माध्यम से उधारकर्ता के सावधि ऋण खाते में जमा की जाएगी।</p> <p>ख. ऋण गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति, वार्षिक आधार पर ऋणदायी एजेंसी के माध्यम से उधारकर्ता के सावधि खाते में जमा की जाएगी।</p>
10.	कार्ड/पासबुक जारी करना	ऋणदायी एजेंसी की अपने मानकों के अनुसार निट और निटवियर इकाईयों को कार्ड/पासबुक जारी करेगी।	ऋणदायी एजेंसी की अपने मानकों के अनुसार निट और निटवियर इकाईयों को कार्ड/पासबुक जारी करेगी।
11.	प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)	आई पावरटेक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि सभी आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सके।	आई पावरटेक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है ताकि सभी आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सके।

योजना का दुरुपयोग रोके जाने के लिए सुरक्षोपाय।

1. ऋणदायी एजेंसियों से यह अपेक्षित है कि वे योजना के तहत ऋण मंजूर करने से पहले उचित सावधानी बरतें।
2. वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ वस्त्र प्रायुक्त के वरिष्ठ अधिकारी, लाभार्थियों का यादृच्छिक सत्यापन करेंगे।

- स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत लिए गए सावधि ऋण के अंतर्गत मशीनरी खरीदने और स्थापित करने के बाद निटिंग और निटवियर इकाईयों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- योजना के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल आई पावरटेक्स के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ऋणदायी एजेंसी द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ऋण मंजूर किए जाने की सूचना दी जाएगी।
- ऋणदायी एजेंसी के सभी निर्णयों और सुझावों की सूचना वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उधारकर्ता इकाईयों को ऑनलाइन दी जाएगी।
- पीएसी का निर्णय अंतिम होगा।

अनुबंध-1**‘प्रधानमंत्री निटिंग एवं निटवियर ऋण योजना’ (पावरटेक्स मुद्रा) के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन पत्र****10,00,000/- रुपए तक ऋण के लिए**

बैंक एवं शाखा का नाम जहां से ऋण की आवश्यकता है

मैं एतद्वारा के लिए रुपए के नगद ऋण/ओवर ड्राफ्ट/आवधिक ऋण के लिए आवेदन करता हूं।

आवेदक का नाम	1. 2.	पिता/पति का नाम	1. 2.
गठन ()	व्यक्तिगत	संयुक्त	प्रोप्राइटर
आवासीय पता	किराये पर/निजी		
व्यवसाय का पता	किराये पर/निजी		
जन्म तिथि	आयु	लिंग : पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर	
शैक्षणिक योग्यता ()	निरीक्षक	10वीं तक	12वीं तक
केवाईसी दस्तावेज ()	वोटर आईडी नम्बर	आधार नम्बर/उद्योग आधार	ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर
पहचान का प्रमाण (निर्दिष्ट करें)			
पते का प्रमाण (निर्दिष्ट करें)			
दूरभाष नम्बर:	मोबाइल नम्बर	ई-मेल:	
व्यवसायिक क्रियाकलाप की लाइन (उद्देश्य)	वर्तमान	अवधि	
	प्रस्तावित		
वार्षिक बिक्री (लाख रुपए)	वर्तमान:	प्रस्तावित:	
अनुभव, यदि कोई हो			

सामाजिक श्रेणी (कृपया निशान लगाये)		सामान्य	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अल्पसंख्यक समुदाय	
यदि अल्पसंख्यक हैं	बौद्ध	मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	जैन	पारसी	अन्य
आवश्यक ऋण की राशि		सीसी/ओडी-रुपए				आवधिक ऋण-रुपए	
मौजूदा खातों का ब्यौरा, यदि कोई हो		किस्म (कृपया टिक करें) (जमा/ऋण)		बैंक का नाम एवं शाखा			
खाता संख्या			यदि ऋण खाता है तो लिए गए ऋण की राशि				रुपए

घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं। मेरे/हमारे पास आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित को छोड़कर यूनिट के लिए उधार लेने का कोई प्रबंध नहीं है। मैंने/हमने किसी बैंक में आवेदन नहीं किया है। मेरे/हमारे ऊपर कोई बकाया/सांविधिक बकाया नहीं है। मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित सभी अन्य सूचना प्रस्तुत करेंगे। यदि आप उचित समझें तो आप यह सूचना किसी एजेंसी को भी दे सकते हैं। आप, आपके प्रतिनिधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा आपके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी यथा उल्लिखित हमारे कारखाने/व्यवसाय परिसरों में किसी भी समय मेरी/हमारी परिसंपत्तियों, लेखा पुस्तिकाओं आदि का निरीक्षण/सत्यापन कर सकते हैं। बैंक के बकाये की वसूली के लिए आप समुचित सुरक्षोपाय/कार्रवाई कर सकते हैं।

दिनांक: _____

स्थान: _____

आवेदक (को) के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए)

पावती पर्ची संख्या..... ऋण आवेदन संख्या.....दिनांक.....

.....द्वारा प्राप्त किया गया

दिनांक: _____

स्थान: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (शाखा की मुहर और हस्ताक्षर)

-----यहां काटे-----

पीएमएमवाई के अंतर्गत रुपए के लिए दिनांक..... के ऋण आवेदन के लिए श्री/श्रीमती..... से ऋण आवेदन के लिए पावती पर्ची संख्या (आवेदक की प्रति) सधन्यवाद प्राप्त किया।

दिनांक:.....

स्थान:.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (शाखा की मुहर और हस्ताक्षर)

जांच सूची: (आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तोबज)

- 1) पहचान प्रमाणपत्र- मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस /पैन कार्ड/आधार कार्ड/उद्योग आधार/पासपोर्ट/सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी आईएम-पावती आदि की स्वयं सत्यापित प्रति।
- 2) आवास का प्रमाण पत्र- हाल का टेलिफोन बिल/बिजली का बिल/संपत्ति कर की रसीद (2 महीने से अधिक पुरानी नहीं)/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/व्यक्ति/प्रोप्राइटर का पासपोर्ट/साझेदार के बैंक की पासबुक अथवा बैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित खाते का नवीनतम विवरण/निवास प्रमाण पत्र/सरकारी प्राधिकारी/स्थानीय पंचायत/नगरपालिका आदि द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- 3) आवेदक का हाल का फोटोग्राफ (2 प्रति) जो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो।
- 4) खरीदे जाने वाली मशीनों/अन्य वस्तुओं का कोटेशन।
- 5) आपूर्तिकर्ता का नाम/मशीन का ब्यौरा/मशीन का मूल्य और/अथवा खरीदी जाने वाली वस्तुएं।
- 6) पहचान प्रमाण पत्र/व्यवसाय उद्यम का पता-संगत लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाण पत्रों/स्वामित्व से संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, पहचान और व्यवसाय इकाई का पता, यदि कोई हो।
- 7) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक आदि जैसी श्रेणी का प्रमाण।

नोट :

- 1) पावरटेक्स मुद्रा ऋण के लिए कोई कोई जमानत/प्रतिभूति नहीं।
- 2) आवेदक को किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

अनुबंध-II

बैंक का नाम:

बैंक का लोगो

'प्रधानमंत्री निट और निटवियर ऋण योजना (स्टैंड अप इंडिया)' के अंतर्गत

(जांच सूची के अनुसार दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए)

क. कार्यालय में प्रयोग के लिए:

उद्यम का नाम	आवेदन क्रम संख्या	शाखा का नाम	श्रेणी
			एससी/एसटी/महिला

ख. व्यवसाय संबंधी सूचना:

आवेदक/उद्यम का नाम											
संगठन	प्रोप्राइटरी	साझेदारी	प्रा.लि.	लि.कंपनी	कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)						
व्यवसाय का पता	राज्य				पिन कोड						
	व्यवसाय का क्षेत्र				किराये पर	स्वामित्वाधीन					
दूरभाष				मोबाइल नम्बर	91						
ई-मेल:											
व्यवसाय का क्रियाकलाप	प्रस्तावित										
आरंभ होने की दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष)											
क्या इकाई पंजीकृत है		हां			नहीं						
यदि पंजीकृत है (कृपया पंजीकरण संख्या और अधिनियम का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत पंजीकृत है)											
उद्योग आधार पंजीकरण संख्या (अनिवार्य नहीं)											
पंजीकृत कार्यालय का पता											
सामाजिक श्रेणी		एससी	एसटी	अल्पसंख्यक							
यदि अल्पसंख्यक हैं	बौद्ध	मुस्लिम	इसाई	सिक्ख	जैन	पारसी					

ग. प्रोप्राइटर/साझेदार/कंपनी के निदेशकों की पृष्ठभूमि की सूचना और उनके पते:

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	लिंग	मोबाइल नम्बर सहित आवासीय पता	शैक्षिक योग्यता	क्रियाकलाप के अनुसार अनुभव (वर्ष)

क्र.सं.	पहचान प्रमाण पत्र	पहचान प्रमाण पत्र संख्या	पता का प्रमाण पत्र	पता का प्रमाण संख्या	पैन कार्ड/डीआईएन नम्बर	बैंक के अधिकारी/निदेशक के साथ संबंध, यदि कोई हो

घ. प्रस्तावित इकाई के संयुक्त साझेदार अथवा निदेशक के संबंधित एसोसिएट के नाम, यदि कोई हो

संबंधित एसोसिएट के नाम	संबंधित एसोसिएट का पता	वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था	संबंधित एसोसिएशन का स्वरूप	संबंधित एसोसिएट में प्रो./साझेदार/निदेशक अथवा निवेशक के रूप में ब्याज की सीमा

ङ मौजूदा बैंकिंग/ऋण सुविधाएं: (रुपए में)

सुविधाओं के प्रकार	बैंकों के नाम और शाखा	उपलब्ध सीमा	दिनांक..... के अनुसार बकाया
बचत खाता		एन.ए	
चालू खाता		एन.ए	
आवधिक ऋण			
यदि इस बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हैं तो यहां उपभोक्ता का पहचान पत्र दिया जाए:			
प्रमाणित किया जाता है कि हमारी इकाई ने विगत में किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से कोई ऋण नहीं लिया है और मैं/हम ऊपर कॉलम सं. ङ में उल्लिखित के अलावा किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया है।			

च. प्रस्तावित ऋण की सुविधाएं (रुपए में)**

सुविधाओं के प्रकार	राशि	उद्देश्य जिसके लिए अपेक्षित है	पेशकश की गई प्रतिभूति	
			प्राथमिक प्रतिभूति (उल्लेख किए जाने के लिए अधिकतम मूल्य सहित विवरण)	क्या जमानती प्रतिभूति की पेशकश की गई है (यदि हां तो कॉलम 1 पर ब्यौरा दें) (हां/नहीं)
नगद ऋण**				
आवधिक ऋण				
एलसी/बीजी				
कुल				

** आवश्यक क्षेत्र

छ. कार्यशील पूंजी के मामले में: आवेदित नगद ऋण की सीमा का आधार: (रुपए में)

नगद ऋण	अनुमानित						
	विक्री	कार्य चक्र महीने में	मालसूची	ऋणी	ऋणदाता	प्रमोटर का अंशदान	सीमा

ज. आवधिक ऋण की आवश्यकता के मामले में मशीनरी/उपकरण के विवरण निम्नानुसार दिए जाएं:

मशीन/उपकरण की किस्म	उद्देश्य जिसके लिए अपेक्षित है	आपूर्तिकर्ता का नाम	मशीन की कुल लागत	प्रमोटर द्वारा किया जा रहा अंशदान (रुपए)	अपेक्षित ऋण (रुपए)
कुल					

आवेदित अधिस्थगन की अवधि के साथ पुनर्भुगतान की अवधि

झ. भावी प्राक्कलन: (रुपए में)

भावी प्राक्कलन (चालू वर्ष के लिए अनुमान और कार्यशील पूंजी की सुविधाओं के लिए प्रदान किए जाने के लिए प्रथम वर्ष के अनुमान। तथापि ऋण के पुनर्भुगतान के प्रस्तावित वर्ष तक प्रदान किए जाने के लिए आवधिक ऋण की सुविधाओं के अनुमान)

	चालू वर्ष (प्राक्कलन)	प्रथम वर्ष (अनुमान)	द्वितीय वर्ष (अनुमान)	तृतीय वर्ष (अनुमान)
निवल विक्री				
निवल लाभ				
पूंजी (कंपनी के मामले में कुल मूल्य)				

ञ. सांविधिक दायित्वों से संबंधित स्थिति:

सांविधिक दायित्व	क्या संकलित किया गया है (हां/नहीं लिखें) यदि लागू नहीं है तो लागू नहीं लिखें	टिप्पणी (संगत दायित्व से संबंधित विवरण दिए जाएं)
1. दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण		
2. एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकरण (अंतिम/अंतिम)		
3. फाइल किया गया नवीनतम विक्री कर रिटर्न		
4. फाइल किया गया नवीनतम आयकर रिटर्न		
5. बकाया कोई अन्य सांविधिक देयता		

ट. घोषणा:

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं। मेरे/हमारे पास आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित को छोड़कर यूनिट के लिए उधार लेने का कोई प्रबंध नहीं है। मेरे/हमारे ऊपर कोई बकाया/सांविधिक बकाया नहीं है। मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित सभी अन्य सूचना प्रस्तुत करेंगे। यदि आप उचित समझें तो आप यह सूचना किसी एजेंसी को भी दे सकते हैं। आप, आपके प्रतिनिधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा आपके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी ऊपर यथा उल्लिखित हमारे कारखाने/व्यवसाय परिसरों में किसी भी समय मेरे/हमारे परिसंपत्तियों, लेखा पुस्तिकाओं आदि का निरीक्षण/सत्यापन कर सकते हैं। बैंक के बकाये की वसूली के लिए आप समुचित सुरक्षा/कार्रवाई कर सकते हैं।

फोटो के लिए स्थान	फोटो के लिए स्थान	फोटो के लिए स्थान
(प्रोप्राइटर/साझेदार/निदेशक के हस्ताक्षर जिनकी फोटो ऊपर चिपकाई गई है)		

दिनांक: _____

स्थान: _____

जांच सूची

1. पहचान पत्र का प्रमाण: प्रोप्राइटर, निदेशक के वर्तमान बैंकों के पार्टनर (यदि कंपनी है) के मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड हस्ताक्षर की पहचान।
2. आवास का प्रमाण: हाल का टेलिफोन बिल, बिजली का बिल, संपत्ति कर की रसीद/पासपोर्ट/प्रोप्राइटर का मतदाता पहचान पत्र, निदेशक के पार्टनर (यदि कंपनी है)।
3. व्यवसाय के पते का प्रमाण।
4. आवेदक को किसी बैंक/एफ.आई. में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
5. कंपनी के संस्था ज्ञापन और अंतर्नियम/पार्टनर के पार्टनरशिप का विलेख।
6. नवीनतम आयकर रिटर्न सहित प्रोमोटर और गारंटर की परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण।
7. किराया करार (यदि व्यवसाय का परिसर किराये पर है) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति यदि लागू हो।
8. एसएसआई/एमएसएमई का पंजीकरण, यदि लागू हो।
9. कार्यशील पूंजी की सीमा के मामले में आगामी दो वर्ष के लिए अनुमानित तुलन पत्र और आवधिक ऋण के मामले में ऋण की अवधि।
10. प्राथमिक और जमानती प्रतिभूतियों के रूप में पेशकश की जा रही सभी संपत्तियों के लीज डीड/हकदारी डीड की फोटो कॉपी।
11. आवेदक एससी/एसटी श्रेणी का है, यह प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज, यदि लागू हो।
12. कंपनी की अधिकांश शेयरधारिता एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो एससी/एसटी/महिला श्रेणी की है, को स्थापित करने के लिए आरओसी के लिए शामिल किए जाने का प्रमाण पत्र।

25 लाख रुपए से अधिक के खुलासे वाले मामलों के लिए

1. इकाई की प्रोफाइल (प्रोमोटरों के नाम, कंपनी में अन्य निदेशक, सभी कार्यालयों और संयंत्रों के लिए जा रहे पतों के क्रियाकलाप, शेयरधारिता की पद्धति आदि शामिल है)
2. एसोसिएट/ग्रुप कंपनियों के पिछले 3 वर्षों के तुलन पत्र (यदि कोई हो)।
3. अधिग्रहित की जाने वाली मशीन के ब्यौरे वाली परियोजनाएं रिपोर्ट (यदि आवधिक वित्त पोषण की आवश्यकता है तो प्रस्तावित परियोजना), किससे अधिग्रहित किया जाना है, मूल्य, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, मशीनों की क्षमता जैसे वित्तीय ब्यौरे, अनुमानित उपयोग की क्षमता, उत्पाद की बिक्री, अनुमानित लाभ और हानि तथा ऋण की अवधि का तुलन पत्र, श्रमिकों के ब्यौरे, किराये पर लिए जाने वाले कर्मचारी, ऐसे वित्तीय ब्यौरों के अनुमान लगाने का आधार।

4. निर्माण की प्रक्रिया, यदि लागू हो, कंपनी ने कार्यपालकों का मुख्य प्रोफाइल, कोई गठबंधन, उपयोग की गई कच्ची सामग्री और उनके आपूर्तिकर्ताओं का ब्यौरा, क्रेताओं का ब्यौरा, प्रमुख प्रतिस्पर्धियों का ब्यौरा और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कंपनी की क्षमता और कमजोरियां आदि।

(यह जांच सूची केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है तथा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है)।

अनुबंध-III

‘प्रधानमंत्री निट और निटवियर ऋण योजना’ (पावरटेक्स मुद्रा) के अंतर्गत दावों के सत्यापन का प्रपत्र

1	कारखाने का नाम और पता	
	तालुका/तहसील/मंडल:	
	जिला:	
	राज्य:	
	पिन कोड:	
	दूरभाष नं./मोबाइल नं.	
	फैक्स नं.	
	ई-मेल आईडी	
	पैन नं.	
2	आधार नं.	
3	दूरभाष/मोबाइल नं. सहित संपर्क व्यक्ति का नाम	
4	पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी सहित आईएम की पावती संख्या/उद्योग आधार नम्बर एवं तारीख	
5	करघों की संख्या	
6	संगठन (व्यक्तिगत/प्रोप्राइटरशिप/सामूहिक प्रा.लि.)	
7	प्रोप्राइटर/पार्टनर/निदेशक के नाम	
8	आवेदक का लिंग (पुरुष/महिला)	
9	आवेदक की श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/अल्पसंख्यक आदि) अल्पसंख्यक के मामले में कृपया ब्यौरा दें।	
10	परियोजना की कुल लागत	
11	ऋण की राशि क. आवधिक ऋण	

12	वितरित की गई ऋण की राशि क. आवधिक ऋण	
13	मौजूदा मशीनें क. मशीन का नाम ख. मात्रा	
14	योजना के अंतर्गत स्थापित नई मशीनें (यदि कोई हो) क. मशीन का नाम ख. मात्रा	
15	दावा की गई मशीनों का प्राथमिक मूल्य	
16	बैंक का नाम और पता (पिन कोड, आईएफएस कोड एवं ई-मेल आईडी सहित शाखा का पूर्ण विवरण)	
17	आवधिक ऋण का खाता संख्या:	
18	क्या परियोजना दिशानिर्देशों के अनुरूप है	
19	क्या जेआईटी निम्न को रिलीज करने की सिफारिश करती है	
	क. मार्जिन मनी सब्सिडी	
	ख. व्याज आर्थिक सहायता	
20	यदि हां, तो पात्रता	
	क. मार्जिन मनी सब्सिडी	
	ख. व्याज आर्थिक सहायता	
21	टिप्पणी, यदि कोई हो	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दावे को पावर टेक्स इंडिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री निट और निटवियर ऋण योजना (पावर टेक्स मुद्रा) के दिशानिर्देशों के अनुसार हर दृष्टि से व्यवस्थित पाया गया है। इसलिए मार्जिन मनी सब्सिडी जारी किए जाने की सिफारिश की जाती है।

मुहर सहित संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य के हस्ताक्षर (ऋणदाता एजेंसी की शाखा का प्रतिनिधि)

मुहर सहित संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य के हस्ताक्षर
(विद्युतकरघा सेवा केंद्र/वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि)

अनुबंध-IV

‘प्रधानमंत्री निट और निटवियर ऋण योजना’ (स्टैंड अप इंडिया) के अंतर्गत दावों के सत्यापन का प्रपत्र

1	कारखाने का नाम और पता तालुका/तहसील/मंडल:	
----------	-------------------------------------------------	--

	जिला: राज्य: पिन कोड:	
	दूरभाष नं./मोबाइल नं.	
	फैक्स नं.	
	ई-मेल आईडी	
	पैन नं.	
2	आधार नं.	
3	दूरभाष/मोबाइल नं. सहित संपर्क व्यक्ति का नाम	
4	पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी सहित आईएम की पावती संख्या/उद्योग आधार नम्बर एवं तारीख	
5	करघों की संख्या	
6	संगठन (व्यक्तिगत/प्रोप्राइटरशिप/साझेदार प्रा.लि.)	
7	प्रोप्राइटर/पार्टनर/निदेशक के नाम	
8	आवेदक का लिंग (पुरुष/महिला)	
9	आवेदक की श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/अल्पसंख्यक आदि) अल्पसंख्यक के मामले में कृपया ब्यौरा दें।	
10	बैंक का नाम और पता (पिन कोड, आईएफएस कोड एवं ई-मेल आईडी सहित शाखा का पूर्ण विवरण)	
11	मशीन की कुल लागत क. प्रोमोटर का अंशदान ख. वितरित आवधिक ऋण	
12	योजना के अंतर्गत स्थापित नई मशीनें (यदि कोई हो) क. मशीन का नाम ख. मात्रा	
13	दावा की गई मशीनों का प्राथमिक मूल्य	
14	आवधिक ऋण का खाता संख्या:	
15	क्या परियोजना दिशानिर्देशों के अनुरूप है	
16	क्या जेआईटी सब्सिडी रिलीज करने की सिफारिश करती है	
17	यदि हां, तो मार्जिन मनी सब्सिडी की राशि	
18	टिप्पणी	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दावे को पावर टेक्स इंडिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री निट और निटवियर ऋण योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हर दृष्टि से व्यवस्थित पाया गया है। इसलिए मार्जिन मनी सब्सिडी जारी किए जाने की सिफारिश की जाती है।

मुहर सहित संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य के हस्ताक्षर
(ऋणदाता एजेंसी की शाखा का प्रतिनिधि)

मुहर सहित संयुक्त निरीक्षण दल के सदस्य के हस्ताक्षर
(विद्युतकरघा सेवा केंद्र/वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि)

VIII. निटिंग और निटवियर क्षेत्र की योजनाओं के लिए सूचना सुविधा, सूचना प्रौद्योगिकी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार हेतु दिशानिर्देश

2.0 उद्देश्य

- क) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई (ओटीएक्ससी) द्वारा संचालित किए जा रहे निटिंग और निटवियर क्षेत्र की योजनाओं, कार्यक्रमों का मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित व्यापक प्रचार करना।
- ख) प्रचार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना।
- ग) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों के तौर-तरीकों और लाभों के बारे में सूचना का प्रसार।
- घ) निटिंग और निटवियर क्षेत्र के बारे में जागरूकता का संवर्धन और विकास पद्धति को बढ़ावा देना।
- ङ) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाई को प्रोत्साहित करना।
- च) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- छ) कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित, व्यापक प्रचार करना।

2.0 योजना प्रचालन की अवधि

योजना के प्रचालन की अवधि 01.07.2019 से 31.03.2020 तक होगी।

(क) सूचना सुविधा सेवाओं और आईटी के संघटक

(क) सूचना सुविधा सेवाएं

- **हेल्प लाइन:-** टोल फ्री कॉल की व्यवस्था करके निटिंग और निटवियर क्षेत्र को आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन/सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित टोल फ्री हेल्प लाइन स्थापित की जाएगी।
- **केएससी में निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों के लिए पंजीकरण सुविधा:** निटिंग सेवा केंद्रों (केएससी) में निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों को पंजीकृत करने की एक प्रणाली होगी जिससे कि केएससी, सरकारी योजनाओं के संबंध में सूचना का प्रसार करने के लिए इन इकाइयों तक पहुंच सके। इस परस्पर संपर्क से इकाइयां, केएससी में उपलब्ध सुविधाओं को समझ सकेंगी ताकि उनका लाभ उठा सकें।
- **एसएमएस एलर्ट:** निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों को निटिंग और निटवियर से संबंधित विषयों पर नए घटनाक्रमों/पहलों के बारे में एसएमएस एलर्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी।
- **बैंक सहायता:** निटिंग और निटवियर क्लस्टरों में केएससी के माध्यम से अग्रणी बैंक और प्रमुख बैंकों की सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि बैंकों से ऋण सुविधा और मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।
- **उद्यमी प्रकोष्ठ:** प्रत्येक निटिंग और निटवियर सेवा केंद्र में एक उद्यमी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में सूचना का प्रसार हो सके।
- **डिजाइन और तकनीकी उन्नति:** केएससी, निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों के लिए उपयुक्त रूप से तैयार की गई डिजाइनिंग सुविधाएं और वांछित तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगी।
- **अन्य कोई सूचना सुविधा सेवाएं-**

(ख) आईटी भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में ऑनलाइन-पोर्टल/मोबाइल एप्लीकेशन का विकास

- भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और पात्र लाभार्थी, लाभ के प्रकार, योजना के विवरणों आदि सहित उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में एक सरल और सिंगल प्वाइंट पहुंच उपलब्ध करने में ऑनलाइन-पोर्टल का विकास अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मोबाइल एप्स, एक अधिक तीव्रतर विकल्प उपलब्ध कराता है, क्योंकि यह आरंभ होने में केवल एक सेकंड का समय लेता है क्योंकि अधिकांश सूचना स्वयं एप्लीकेशन में स्टोर होती हैं जिससे इसमें ऑफ लाइन काम संभव हो पाता है। इससे सूचना से जुड़ने की सुविधा प्रदान करके अंतिम प्रयोक्ताओं के साथ निष्ठा कायम होने में सहायता मिलती है। मोबाइल एप्लीकेशन का लाभ यह है कि अंतिम प्रयोक्ताओं के साथ बेरोकटोक जुड़ाव और संपर्क रखा जा सकता है जिससे यह भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं तक पहुंच बनाने के लिए एक बहुमूल्य साधन बन जाता है जिसके परिणामस्वरूप सूचना अनुरोधों और फील कॉलों द्वारा स्टाफ के कार्यभार में कमी आती है।

1.0 जागरूकता और बाजार विकास कार्यक्रम

- (i) **सेमिनार/कार्यशालाएं:** निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों के लाभ के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, प्रौद्योगिकी, सेवाओं, उत्पादों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, निटिंग और निटवियर सेवा केंद्रों तथा अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों, टीआरए आदि द्वारा कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- (ii) **क्रेता-विक्रेता बैठकें:** योजना के अधीन प्रदर्शनियां/मेले और क्रेता-विक्रेता बैठक जैसी बाजार विकास की गतिविधियों से निटिंग और निटवियर क्षेत्र की इकाइयों को उनके उत्पादों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन करने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।
इस योजना के अधीन प्रदर्शनियों के आयोजन, अवसंरचना सहायता, स्टाल किराया, स्टाल फर्निशिंग, बिजली प्रभारों, प्रचार, बैंक अप सेवाओं और प्रशासनिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- (iii) **रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम:**
भारत में विदेशों से संभावित क्रेताओं और आयातकों को आमंत्रित करके निर्यात संवर्धन परिषदों/निटिंग और निटवियर उद्योग संघों के सहयोग से रिवर्स बायर सेलर मीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों में प्रमुख भारतीय कंपनियां आंगतुक विदेशी क्रेताओं के समक्ष निटेड फैब्रिक और निटवियर परिधानों की अद्यतन रेंज का प्रदर्शन करती हैं जिससे भागीदार सदस्य अपने निर्यात व्यापार का विकास/विस्तार कर सकें। इस प्रकार आंगतुक क्रेताओं के पास एक ही छत के नीचे अग्रणी वस्त्र कंपनियों के अद्यतन उत्पादों को देखने, भागीदार कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करने और लाभकारी कारोबारी सौदे करने का अद्वितीय अवसर होता है।
- (iv) **निटेड और निटवियर उत्पादों के विपणन के लिए ई-प्लेटफार्म:**
ई-कामर्स के माध्यम से निटेड और निटवियर उत्पादों के विपणन का संवर्धन करना वस्त्र मंत्रालय की प्राथमिकताओं में से एक है। पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी तरीके से निटेड और निटवियर उत्पादों की ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय के अधीन वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, निटेड और निटवियर उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में भागीदारों के लिए अच्छे ट्रेक रिकॉर्ड वाले किसी इच्छुक ई-कामर्स प्लेटफार्म की सेवाओं का लाभ प्राप्त करेगा।
- (v) **निटिंग और निटवियर कलस्टरों के उद्यमियों के लिए अनुभव दौरा:**
बेहतर प्रौद्योगिकी, उत्पाद आदि को समझने के उद्देश्य से निटिंग और निटवियर कलस्टरों के उद्यमियों के लिए अनुभव दौरों का आयोजन किया जाता है। प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर से निटिंग और निटवियर कलस्टर के उद्यमियों को अद्यतन प्रौद्योगिकी/विनिर्माण वाले विकसित कलस्टर के संपर्क में रहने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादों के विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
भारत सरकार द्वारा प्रत्येक उद्यमी को आकस्मिक खर्चों के लिए 5000/- रुपए और आने-जाने के लिए स्लीपर श्रेणी के रेल किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- (vi) **विशेष आवश्यकताओं पर अध्ययन, सर्वेक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन:**
विश्लेषणात्मक अध्ययनों और सर्वेक्षणों के निष्कर्ष निटिंग और निटवियर उद्योग को उनकी कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा साथ ही सतत रोजगार सृजन का विस्तार करने के उद्देश्य से चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने में निटिंग और निटवियर उद्योग की सहायता करने और उसे समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा स्वयं अथवा सरकारी निजी भागीदारी पद्धति में उपयुक्त कार्यनीतियों और पहल के उपायों को तैयार करने में सहायता करते हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष इन योजनाओं में परिवर्तनों का सुझाव देंगे जिससे वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।

योजनाओं की मॉनीटरिंग/मूल्यांकन से (i) इनके कार्य निष्पादन (ii) संसाधन कैसे खर्च किए गए हैं (iii) योजनाओं की निरंतरता संबंधी विश्वसनीयता के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त योजनाओं का मूल्यांकन (i) कार्यान्वित परियोजनाओं की खूबियों और कमजोरियों (ii) बाधाएं/कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं (iii) सफलता और असफलता और (iv) अच्छी पद्धति जैसे समस्याकारक मुद्दों का समाधान करने में सहायता करता है।

(vii) कोई अन्य जागरूकता और बाजार विकास कार्यक्रम:

उदाहरणार्थ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग्स, सचल प्रचार वैन, अधिकतम जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न आईसीटी मोड अपनाना।

5.0 इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रचार:

किसी भी मीडिया का मुख्य उद्देश्य जनता तक सूचना पहुंचाना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मीडिया का अधिक उन्नत स्वरूप है, इंटरनेट, टेलीविजन आदि हो सकता है और इसमें विभिन्न चैनलों, साइट आदि के माध्यम से अधिक तेजी से पहुंचा जा सकता है। प्रिंट मीडिया में विशेषतः समाचार पत्र, लेख और जर्नल्स आदि शामिल होते हैं जिन्हें प्रयोक्ता किसी भी समय और कहीं भी पढ़ सकते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, विभिन्न निटिंग और निटवियर क्षेत्र की योजनाओं के प्रचार और जागरूकता सृजन में सहायता करने में स्टेक होल्डरों/निटिंग और निटवियर उद्यमियों की आवश्यकताओं को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन साधनों द्वारा पूरा किया जा सकता है।

6.0 कार्यान्वयन एजेंसी

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों/निटिंग और निटवियर सेवा केंद्रों (केएससी) के साथ-साथ निर्यात संवर्धन परिषदों और निटिंग और निटवियर संघों के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन करेगा।

7.0 योजना की प्रगति की मॉनीटरिंग

वस्त्र आयुक्त समय-समय पर इस योजना की प्रगति को मॉनीटर करेंगे।

MINISTRY OF TEXTILES

RESOLUTION

New Delhi, the 1st July, 2019

Subject: Comprehensive Scheme Guidelines for Development of Knitting & Knitwear Sector under PowerTex India w.e.f. 01.07.2019 to 31.03.2020.

No.1/6/2018-PL.—Knitting and Knitwear sector is one of the highest employment generator and it has a significant contribution in the export of textiles. Further, the knitting & knitwear units are mostly MSME units located in major clusters like Ludhiana, Tirupur, Kolkata, Surat, Bengaluru etc. Though, the Knitting & knitwear units are covered for benefits under Amended Technology Upgradation Fund Scheme (A-TUFS) towards installation of new machines of benchmarked technology level, there are no schemes focusing on the infrastructure development, access to credit, common facilities required in the cluster, raw material price fluctuation etc. for Knitting and Knitwear industry/sector. Therefore, Ministry of Textiles had decided to intervene/facilitate/assist the Knitting and Knit wear industry/sector and called the meeting at Ministry of Textiles, New Delhi on 05.06.2017 with the stake holders of the knitting and knit wear industry/sector. Based on the suggestions/inputs from the Industry and the Ministry of Textiles Senior Officers. The Scheme i.e. Comprehensive Scheme for Development of Knitting&Knitwear Sector under PowerTex India was approved &will be in operation with effect from 01.07.2019 to 31.03.2020.

I.COMPONENTS AND OBJECTIVES:

S.No.	COMPONENTS	OBJECTIVES
1.	Creation of New Service centers on PPP model by Industry/ Associations in the Knitting and Knitwear clusters.	The prime objective of the Scheme is to provide adequate facilities for testing, training, sample development, consultancy, trouble shooting, facilitation services in the knitting and knitwear clusters by way of creation of new service centers in the clusters on PPP model with participation from industry/association.
2.	Modernization and Upgradation of existing PSCs/institutions run by TRAs/ EPCs Associations in Knitting and Knitwear clusters.	To equip the existing Powerloom Service Centres/institutions run by the Textile Research Associations (TRAs) (or) Export Promotion Councils (EPCs) (or) any other Textile Industry Association with requisite machineries for training/testing purposes required for knitting & knitwear industry.
3.	Group Workshed Scheme for Knitting and Knitwear units.	The prime objective of the scheme is to facilitate the establishment of Group Worksheds for modern knitting machines and/or knitwear in an existing (or) new cluster, which will provide required scale of economy for business operations and improved working condition in terms of more space, work environment, improve the work efficiency to enhance their competitiveness in the global market.
4.	Yarn Bank Scheme for Knitting & Knitwear units.	To provide interest free corpus fund to Special Purpose Vehicle (SPV) / Consortium of knitting units to enable them to purchase the yarn at wholesale rate and give the yarn at reasonable price to the small Knitting unit thereby avoiding middle man/ local supplier's brokerage charge on sales of yarn.
5.	Common Facility Centre (CFC) Scheme for Knitting and knitwear units.	To establish Common Facility Centres (CFC) in various knitting & knitwear clusters for providing common facilities like processing, dyeing, printing, design development, testing facilities, ETP etc. to the knitting & knitwear units.
6.	Pradhan Mantri Credit Scheme for Knitting and Knitwear units (Stand-up India scheme)	To provide adequate and timely financial assistance to the knitting & knitwear units to meet their credit requirements, for investment needs (Term Loan), for new entrepreneurs belonging to SC/ST & Women category.
7.	Facilitation, IT, Awareness, Studies, Surveys, Market Development and Publicity for Knitting and Knitwear Units	Facilitation services to Knitting and Knitwear Units like Help line, Registration services, SMS Alert, Bank services etc. Online Portal for Knitting and Knitwear Schemes To create awareness about schemes, disseminate the information about technology, products for the benefits of Knitting and Knitwear Units. To provide a platform for Knitting and Knitwear Units to market their products at cluster level, regional level, national and international level. Publicity of Knitting and Knitwear schemes in Electronic and Print Media.

All the above schemes will be implemented by Textile Commissioner through their Office, the Regional Office, the PSC and any other Organisation/Agency.

The detailed guidelines for each of the above components are as under:-

IV. Creation of New Service Centres in Knitting and Knitwear clusters.**1) Objective**

Govt. of India will provide financial assistance for setting up of new Knitting and Knitwear Service Centres for providing testing, training, sample development, consultancy, trouble shooting, facilitation services in the Knitting and Knitwear clusters.

2) Setting-up of Knitting Service Centre (KSCs)

- a) The proposed KSCs would be set-up in Public Private Partnership (PPP) model.
- b) The Knitting and Knitwear industry / Stakeholders will form an association to be called as the Knitting and Knitwear Service Centre Association, to operate the Service Centres. The Knitting and Knitwear industry/associations would provide land and building for setting-up of new Knitting Service Centre (KSCs) and would be managed by them.
- c) In case of testing of samples, First-in-First-out (FIFO) rules will be strictly followed and the same should be technology driven. In case of urgent test reports for samples for export clearance, additional "express charges" may be levied.
- d) The recurring expenditure for running of the KSCs would be borne by the Stakeholders/ Industry associations.
- e) They would be free to decide on the user charges for availing various facilities in the Service Centre. However, the user charges decided by the association would be subject to any direction from the Textile Commissioner/Ministry of Textiles, Govt. of India in the said regard so that the facilities are made available even to the smaller and financially weaker units.

3) Financial Assistance

- a) Financial assistance up to **Rs.200 lakh per Center** will be provided towards purchase of testing equipments and machineries required for training for the KSCs. An indicative list of testing equipments and machineries for training is given at **Annexure-A1**. However, the testing equipments and machineries required for training can be decided by the stakeholders of the clusters as per their requirement within the overall cap of Rs.200 lakh. Any additional equipment required for KSCs would be purchased by the stakeholders at their own cost.

4) Monitoring of KSCs

- a) The KSC set-up by the association would be subject to supervision and inspection/audit by the Textile Commissioner.
- b) The Office of the Textile Commissioner will supervise and monitor the functioning of the Knitting & Knitwear centre.

5) Safeguard against mis-utilisation

- a) In case of non-utilization/mis-utilisation of Financial Assistance and delay in completion of setting-up of KSCs within stipulated period, as approved by PAC/ Textile Commissioner/ Ministry of Textiles, Govt. of India, funds released shall be recovered from the Implementing Agency (IA) with simple interest @10% per annum from the date of release to date of refund of the amount.
- b) Project Approval Committee (under PowerTex India) decisions/directions is final.

6) Redressal of Grievance

All grievances related to implementation of the scheme shall be submitted to the Textile Commissioner who will take necessary action to resolve the grievance.

NIHAR RANJAN DASH, Jt. Secy.

Annexure-A1**ESTIMATED LIST OF MACHINES & EQUIPMENTS AND ITS COST FOR SETTING UP KNITWEAR SERVICE CENTRE****A. TESTING LABORATORY :****(iii) Physical testing**

Sl. No.	Name of machine	Number	Estimated Rate (Rs.)	Total amount (Rs.)
1.	Automatic Wrap reel	1 No.	35,000/-	35,000/-
2.	Electronic Analytical Balance	1 No.	1,25,000/-	1,25,000/-
3.	Electronic Lea Strength Tester	1 No.	2,00,000/-	2,00,000/-

4.	Electronic Twist Tester	1 No.	1,00,000/-	1,00,000/-
5.	Single Yarn Strength Tester (Electronic Type)	1 No.	42,00,000/-	42,00,000/-
6.	Laundry o meter with Grey Scales	1 No.	35,000/-	35,000/-
7.	Crockmeter with Grey Scale	1 No.	25,000/-	25,000/-
8.	Perspirometer	1 No.	20,000/-	20,000/-
9.	Air Conditioner (1.5 Ton)	1 No.	35,000/-	35,000/-
10.	Projection Microscope	1 No.	3,00,000/-	3,00,000/-
11.	Yarn Evenness Tester UT-5	1 No.	80,00,000/-	80,00,000/-
Total				Rs. 1,30,75,000

(iv) Fabric & Chemical testing Machines & Equipments

Sl. No.	Name of machine	Number	Estimated Rate (Rs.)
1.	Beasley Balance	1	10,000/-
2.	Fabric Strength tester	1	3,50,000/-
3.	Fabric sample cutting machine	1	25,000/-
4.	UV Cabinet	1	30,000/-
5.	Crease recovery tester	1	10,000/-
6.	Tumble Dryer	1	80,000/-
7.	Wet & Dry fastness testing machines	1	40,000/-
8.	Computerised colour Matching Unit	1	2,50,000/-
9.	Abrasion tester	1	5,00,000/-
Total			Rs. 12,95,000/-

B. Development of Training Facilities on Knitwear Manufacturing

The List of Machineries required and their approximate costing:

	Machine Type	Quantity	Approx. cost
1.	Single Needle lock stitch with clutch motor	25	6,87,500/-
2.	Double needle lock stitch	1	70,000/-
3.	Button hole	1	2,50,000/-
4.	Button stitch	1	85,000/-
5.	Over lock	1	85,000/-
6.	Feed of the Arm machine	1	1,70,000/-
7.	Lock stitch with computer control	1	70,000/-
8.	Pattern cutting table (2'6"×6'×6')	1	35,000/-
9.	Cutting machine (Straight Knife)	1	80,000/-
10.	Cutting machine (Round Knife)	1	70,000/-
11.	Attachment and tool kit	1	60,000/-

12.	Pressing table & iron	1	13,000/-
13.	Fusing machine	1	30,000/-
14.	IT infrastructure (Hardware and software systems)	Computers, Printers & LAN connections	3,50,000/-
15.	Furniture etc.	-	1,50,000/-
16.	Garment Software (CAD)	4	4,00,000/-
Total			26,05,500/-

C. DEVELOPMENT OF FABRIC EMBROIDERY & KNITTING TRAINING FACILITIES

	Machine Type	Quantity	Estimated Rate (Rs.)	Approx. cost
1.	Computerized Embroidery Machine (multi headed) with sequence	1	15,00,000/-	15,00,000/-
2.	IT infrastructure (Hardware and CAD system)	6 computers, printers & CAD software	3,00,000/-	3,00,000/-
3.	Single Jersey Knitting M/C	1	50,000/-	50,000/-
4.	Single Jersey Knitting M/C with Auto stripper	1	80,000/-	80,000/-
5.	Rib Machine	1	50,000/-	50,000/-
6.	Collar/ Cuff Machine	1	50,000/-	50,000/-
7.	Furniture etc.	-	-	1,00,000/-
Total				21,30,000/-

E. Others

Sl. No.	Name of machine	Number	Rate (Rs.)	Total amount (Rs.)
1.	Library- Cum –meeting room	--	--	50,000/-
2.	LCD Projector with screen	01	1,00,000/-	1,00,000/-
3.	DG Set 15 KVA	1 No.	2,00,000/-	2,00,000/-
4.	Furniture & Fixtures	--	--	1,00,000/-
5.	Fax	1 No.	30,000/-	30,000/-
6.	UPS	1 No.	3,00,000/-	3,00,000/-
Total				7,80,000

The list is not exhaustive, it is illustrative only. Any other machines/ equipments will be decided as per requirement for the cluster.

III. Modernisation and Up-gradation of existing Powerloom Service Centers run by TRAs/ EPCs etc.

1) Objective

Govt. of India will provide financial assistance towards incurring expenditure to the existing Powerloom Service Centres/institutions run by the Textile Research Associations (TRAs) (or) EPCs (or) any other Textile Industry Associations towards the purchase of machineries/equipments for training/testing for the development of Knitting and Knitwear Industry.

2) Financial Assistance

- Financial assistance up to **Rs.20 lakh per Centre** will be provided by the Textile Commissioner towards strengthening/ modernization of the such Centers/institutions.
- Based on the experience of new Knitting Service Centres (KSCs) which will operate on a PPP model, the possibility of converting the existing Powerloom Service Centres (PSCs) into Powerloom cum Knitting Service Centres (KSCs) which are operated on a PPP model will be explored.

3) Safeguard against mis-utilisation

- In case of non-utilization/mis-utilisation of Financial Assistance and delay in completion of setting-up of KSCs within stipulated period, as approved by PAC/ Textile Commissioner/ Ministry of Textiles, Govt. of India, funds released shall be recovered from the Implementing Agency (IA) with simple interest @10% per annum from the date of release to date of refund of the amount.
- Project Approval Committee (under PowerTex India) decisions/directions is final.

4) Redressal of Grievance

All grievances related to implementation of the scheme shall be submitted to the Textile Commissioner, who will take necessary action to resolve the grievance.

IV. Group Workshed Scheme

1.0 Objectives

The prime objective of the scheme is to establish Group worksheds for installation of modern knitting and knitwear machines in an existing or new clusters, which will provide required scale of economies for business operations and to organize knitting and knitwear units in a cluster and to provide improved working condition in terms of more space, work environment, improve the work efficiency to enhance their competitiveness in the global market.

2.0 Period of Operation

The Group Workshed Scheme shall remain in operation for the period from **01.07.2019 to 31.03.2020**.

3.0 Scope of the Scheme

The construction of worksheds under the scheme include the space required for installation of modern Knitting and knitwear sector machines, Air Compressor, Fabric Checking machines & Common facilities such as sample display room and construction of Dormitory for the workers.

3.1 Eligible area for Knitting units

S.No.	Eligible Machineries	Max. Eligible Area per Machine
KNITTING MACHINERIES		
1.	Socks knitting machine & flat collar knitting	250 sq.ft
2.	Circular knitting machine	600 sq.ft
3.	Auto stripper (open width type)	1200 sq.ft
4.	High speed knitting machine with Jacquard	1200 sq.ft

The above area includes requirement for working of a knitting machine, raw material storage for knitting, grey fabric storage, stores and spare parts storage, grey fabric checking / folding and packing, and administration/utilities/workers amenities etc. However, beneficiaries can have area of bigger size with their own contribution.

3.2 Eligible area for Knitwear units

S.No.	Eligible Machineries	Eligible Area per Machine
KNITWEAR MACHINERIES		
1.	Stitching Machine	100 sq.ft

The above area includes requirement for working of a knitwear stitching machine, fabric storage, fabric cutting section, garment checking and packing section, stores and administration/utilities/workers amenities etc. However, beneficiaries can have area of bigger size with their own contribution.

3.3 Additional subsidy for construction of Dormitory for workers which includes adequate hygienic toilet and bath room (kitchen with store room and dining hall may also be included as optional) for accommodation of minimum 1.25 persons per knitting and knitwear stitching machine will be provided @ 125 sq.ft per person.

3.4 The beneficiaries who have availed benefit under Scheme would not be eligible for any infrastructure benefits under any other scheme of Ministry of Textiles viz. Scheme for Integrated Textile Park (SITP). However, benefit from State Govt. scheme as applicable may be availed.

4.0 Eligible Criteria

- 4.1 Eligible beneficiary would include Knitting and knitwear sector unit (or) Entrepreneurs associated with Knitting and knitwear sector & allied industry, Registered co-operative societies (or) any new entrepreneur(s) individually (or) in-group.
- 4.2 Group will consist of at least 4 entrepreneur(s) having separate legal entity. At least **24 nos. of knitting machine of all types (or) 8 nos. of Auto stripper (open width type) knitting machine (or) 4 nos. of High Speed Knitting machines with Jacquard** are to be installed in the Workshed. Each beneficiary should install at least 4 nos. of knitting machine (or) 2 nos. of Auto stripper (open width type)knitting machine (or) 1no of High Speed Knitting machine with Jacquard.
- 4.3 Group will consist of at least 4 entrepreneur(s) having separate legal entity. At least **200 nos. of stitching machine of all types** are to be installed in the Workshed. Each beneficiary should install at least **50 nos. of stitching machine.**
- 4.4 In case of combination of knitting and knitwear stitching machines in GroupWorkshed, pro-rata number of machines will be allowed.
- 4.5 Group applications will be entertained. However, where sufficient beneficiaries are available, the subsidy will be restricted to one representative of a family only in the group.Family means Husband,Wife,dependent children & dependent parents.
- 4.6 “Knitting and knitwear sector unit” would include Knitting machines and knitwear stitching machine, Air Compressor, Fabric Checking/cutting machines & Common facilities such as sample display room and construction of Dormitory.
- 4.7 **Only A-TUFS compatible machines would be allowed to install** in the projects sanctioned under the Scheme. However, prior approval of TUFS subsidy need not be a pre-condition.
- 4.8 The scheme does not envisage more than 300 Knitting machines and 2500 knitwear stitching machines under one project.

5.0 Purchase of land & Clearance

- 5.1 An Executing Agency (referred as EA) shall be formed for setting up of project under this scheme. However, the EA cannot be considered as beneficiary for Govt. of India subsidy.
- 5.2 EA may include the State Govt. (or) its agency (or) a Registered Co-operative Society (or) a Company set-up under Companies Act, 1956 as amended (or) a firm set-up under the Limited Liability Partnership Act, 2008 as amended, by a group of knitting and knitwear sector units (**minimum of Four beneficiaries**) (or) by the local knitting and knitwear sector and allied industry association.
- 5.3 The EA must be in possession of required land by owned/ leased before submission of project proposal. If land is taken on lease basis by the EA, it should have **minimum lease period of 10 years** and the EA shall submit **registered lease deed** along with the project proposal.
- 5.4 The proposed land must be **non-agriculture industrial land** and should have necessary approach road.
- 5.5 The EA should have **Layout and Building plan duly approved by Govt. Authority.**

6.0 Operational Guidelines:

- 6.1 There would be an Executing Agency (referred as EA) for setting up of project under this scheme which may include the State Govt. or its agency, a registered Cooperative Society or a Company set up under Companies Act 1956, as amended/ **a firm set-up under the Limited Liability Partnership Act, 2008as amended**, by a group of knitting & knitwear owners (minimum of four beneficiaries) or by the local knitting & knitwear association.
- 6.2 The EA shall submit an application as per format given at **Annexure-I** alongwith a Detailed Project Report (DPR) and documents enlisted in the enclosed checklist at **Annexure-II**, for the purpose of availing of subsidy under the scheme indicating the salient features and submit the same to the Powerloom Development Cell (PDC) at the Office of the Textile Commissioner, Mumbai, through its Regional Office of the Textile Commissioner with an advanced copy to PDC. The concerned Regional Office of the Textile Commissioner will forward the proposal with their recommendation or otherwise to the Office of the Textile Commissioner within 30 days of the receipt of the application. The DPR should, interalia, contain the following details:
- Executive summary of the Project
 - Nature of the EA: whether the Govt. Agency or Co-operative society or a company set up by the group of knitting & knitwear units/local knitting & knitwear associations.
 - Details of the land-location, nature of ownership (owned/leased) and the cost.
 - Details of beneficiaries, along with the Worksheds and knitting & knitwear machineries proposed to be installed by each beneficiary.
 - Component-wise cost of Project
 - Project funding patterns, indicating the shares of the EA, Central Govt. and others, and loans
 - Schedule of construction indicating month-wise plan with PERT/CPM.
 - Layout of the Project Area indicating location of sheds, infrastructure such as road/water supply/electricity/drainage and other common facilities.
- 6.3 The schedule of rates of CPWD as in that state shall be used, as the basis, for arriving at the cost estimates of construction of building under the scheme.
- 6.4 The beneficiary (ies) should give a written undertaking as **per the format (Annexure-III) prescribed by the Textile Commissioner.**
- 6.5 The knitting & knitwear units availing of subsidy should at least function for a minimum lock-in period of 3 (three) years under the same ownership from the date of disbursement of last instalment of subsidy.

7.0 Project Approval Committee (PAC)

All projects under the scheme will be submitted to Project Approval Committee constituting of following members for its approval, where,

- i) GOI share /assistance is more than Rs. 2.00 crore.

Chairman	- Secretary (Textiles)
Member	- AS & FA
Member	- Joint Secretary (PL)
Member	- Representative from Niti Ayog
Member Secretary	- Textile Commissioner

- ii) GOI share /assistance is less than Rs. 2.00 crore

Chairman	- Textile Commissioner
Member	- Joint Secretary (PL)
Member	- Representative from IFW
Member Secretary	-Additional-Textile Commissioner/Director

The Project Approval Committee may meet monthly but at least once in every quarter to review / assess the progress of the projects under the scheme. The PAC may examine the proposal submitted by the Concerned Regional Office of the Textile commissioner within 90 days.

- 7.1 The EAs will open an ESCROW account with any schedule bank and all payments for GWS will be made through ESCROW account which will be jointly operated by one member of EA and one member from the concerned Regional Office of Textile Commissioner. After opening of ESCROW account, the EA shall submit the account details as per the format prescribed by Office of Textile Commissioner to Powerloom Development Cell.
- 7.2 After receipt of communication of approval of the project by PAC & opening of escrow account, the beneficiary would take up the construction. Initial 30% advance will be given only if the land is mortgaged to Govt. of India as first charge or 2nd charge. If the land is not mortgaged, initial 30% of the total GOI share will be released on incurring proportionate expenditure.
- 7.3 The EA should submit the claim for release of subsidy to the Textile Commissioner.
- 7.4 For any change/modification in project profile, the approval of PAC is to be obtained.

8.0 Local Level Monitoring Committee (LLMC):

Local Monitoring Committee will be formed for each centre which will include an officer from the concerned Regional Office of the Textile Commissioner & local District Industries Centres, a representative of local knitting & knitwear associations and/or respective FI/banks. The eligible subsidy will be released only after getting the physical verification report of LLMC **as per the format (Annexure-IV) prescribed by the Textile Commissioner.**

9.0 Financial Assistance & Funding Pattern

9.1 Under this scheme, subsidy for construction would be as under:-

General Category: 40% of the unit cost of construction of Group workshed, Dormitory/workers' accommodation subject to a maximum of Rs.400/- per Sq.ft

SC Category: 75% of the unit cost of construction of Group workshed, Dormintory/workers' accommodation subject to a maximum of Rs.750/- per Sq.ft

ST Category: 90% of the unit cost of construction of Group workshed, Dormintory/workers' accommodation subject to a maximum of Rs.900/- per Sq.ft

9.2 The maximum permissible subsidy per beneficiary shall be restricted to Rs.22.00 lakh

9.3 The lowest rate of subsidy should be adopted in case of the Group consisting of mixed category.

10.0 Release of Subsidies:

The following schedule will be adopted for release of GOI share to the beneficiaries:

- 10.1 30% of the total GOI share will be released in advance, after approval of the project by the PAC and after submission of the claim by the EA within 90 days of the date of sanction of the project by the PAC in the prescribed Format at **Annexure-V** along with documents enlisted provided the land is mortgaged to GOI on 1st charge / 2nd charge. Otherwise the first instalment of 30% of Govt. of India subsidy will be released after the proportionate expenditure is incurred by the EA for construction which is approved by a Govt. Architect. The LLMC report will be submitted by the concerned Regional Office of the Textile Commissioner to the Office of the Textile Commissioner within 30 days from the date of submission of the claim.
- 10.2 Second instalment of 30% of the total GOI share will be released after furnishing of the Utilization Certificate (UC) of 1st instalment and the proportionate expenditure approved by a govt. approved architect and submission of claim within 180 days of the date of sanction in the prescribed Format at Annexure-VI alongwith documents enlisted therein. The LLMC report will be submitted by the concerned Regional Office of the Textile Commissioner to the Office of the Textile Commissioner within 30 days from the date of submission of the claim.
- 10.3 Third instalment of 20% of the total GOI share will be released after successful completion of Group Workshed along with the copy of proportionate expenditure incurred by the EA for construction which is approved by a Govt. Architect and submission of claim within 270 days of the date of sanction in the prescribed Format at **Annexure-VII** alongwith documents enlisted therein. The LLMC report will be submitted by the concerned Regional Office of the Textile Commissioner to the Office of the Textile Commissioner within 30 days from the date of submission of the claim.

- 10.4 Balance 20% of Govt. of India subsidy will be released after submission of claim by the EA within 2 years from the date of sanction in the prescribed Format at Annexure-VIII along with documents enlisted therein. The LLMC report regarding successful installation and satisfactory working of the machineries as approved by PAC will be submitted by the concerned Regional Office of the Textile Commissioner to the Office of the Textile Commissioner within 30 days from the date of submission of the claim.
- 10.5 If the land is not mortgaged, then no advance will be given, but pro rata reimbursement of subsidy will be done in the ratio of 30:30:20:20.

11.0 **Monitoring and Review:**

- 11.1 With a view to monitoring the implementation of the scheme and ensuring proper usage of the benefit, the Textile Commissioner shall call for any documents/information from the beneficiary as may be deemed necessary and cause inspection of the unit(s) as and when required.
- 11.2 Failure on the part of an Eligible Unit to submit any of the information / documents as called for by the Textile Commissioner within the specified time shall amount to breach of the provisions of the Group Workshed Scheme entailing suitable action as deemed fit including action to cancel the approval of the project, or premature recall of and immediate recovery of the incentives drawn / availed.

12.0 **Safeguard against Mis-utilisation:**

- 12.1 The land on which Group Workshed is proposed for establishment must have clear title for use in favour of EAs and also must have all NOC from local bodies, Municipal Authority, State Administrative and State Pollution Control Board as applicable.
- 12.2 The EA shall function at-least for a period of three years from date of release of fourth and final instalment.
- 12.3 In order to avoid default by the beneficiaries, the mortgage of assets on 1st or 2nd charge would be taken in all cases approved under the scheme failing which the beneficiary shall execute surety bond **as per the format (Annexure-IX)** before release of funds.
- 12.4 In case of non utilization/mis-utilisation of subsidy and delay beyond 18 months in completion of the project, as approved by PAC, funds released shall be recovered from the Executive Agency with simple interest @10% per annum from the date of release to date of refund of the amount.
- 12.5 Before releasing the 1st instalment it will be ensured that the cost of land is more than the amount (1st instalment) being released to the EA.
- 12.6 Utilization of Govt. subsidy will be made through an Escrow account indicated in para 7.1 of the scheme.
- 12.7 Project Approval Committee (under PowerTex India) decisions/directions is final.

13.0 **Time Limit for completion of Project:**

- 13.1 The project as approved by the PAC shall be completed in all respect within 2 years from the date of communication of approval.
- 13.2 The PAC may extend the time limit for one more year beyond 2 years period, based on the request of EA with sufficient reason/cause for non-completion of the project, failing which penalty @ 10% will be imposed and the same will be adjusted from the balance subsidy to be released.

14. **Redressal of Grievance**

All grievances related to implementation of the scheme shall be submitted to the Textile Commissioner, who will take necessary action to resolve the grievance.

Annexure-1

APPLICATION FOR GRANT OF SUBSIDY UNDER GROUP WORKSHED SCHEME FOR KNITTING AND KNITWEAR SECTOR

(A) General Details

1.	Name of Executing Agency	
	Address of Registered/Administrative Office	
	Location of Workshed	

	Phone No.	
	Fax	
	Website	
	Email	
2.	Nature of Executing Agency (State Govt. or its agency / Registered Co-operative Society / Private Limited Company / Public Limited Company / LLP/ Knitwear Association)	
3.	Registration No. & Date (Copy enclosed)	

(B) Details of Project costs & Financing

Sr. No	Items	Financing (Rs. lakh)				
		Own contribution	Central Govt's. subsidy	State Govt's. subsidy	Loan from Financial Institutions	Total
1.	Land					
2.	Worksheds					
3.	Infrastructure					
	a) Internal roads					
	b) Electricity supply					
	c) Water supply					
	d) Drainage					
	e) Others					
4.	Knitting machines					
5.	Knitwear machines					
6.	Dormitory					
	TOTAL					

(C) Project Details

1.	<u>Land</u> Total area in sq.ft Nature of Ownership:	Owned / Leased
2.	<u>Worksheds</u>	
	a) Total No. of sheds for Knitting machines	
	b) Total No. of sheds for Knitwear machines	
	Total number of Sheds (a) + (b)	
	c) Total area in sq.ft for sheds of Knitting machines	
	d) Total area in sq.ft for sheds of Knitwear machines	

	e) Total area in sq.ft. for Dormitory	
	Total area in sq.ft (c) + (d) +(e)	
	f) Proposed Cost of construction per sq. ft (in Rs)	
3.	<u>Infrastructure</u>	
	a) Electricity supply (Load in M.W)	
	b) Water supply (Quantity in K.L.)	
	c) Drainage (Length in mtrs)	
	d) Others	
4.	<u>Knitting and knitwear sector Machines Proposed</u>	
	a) Socks knitting & flat collar knitting machines	
	b) Circular knitting machines	
	a) No. of Auto stripper (open width type)	
	e) High speed knitting machines with Jacquard	
5.	a) Product Profile	
	b) Production per day (Kgs/ mtrs as applicable)	
	b) Total Production per annum (Kgs/ mtrs as applicable)	
	c) No. of Stitching & other allied machines proposed to be purchased (Knitwear sector)	(Also enclose the list of machinery.)
	d) Production per day	No. of Pieces
	e) Total Production per annum	No. of Pieces
	f) Export in terms of value & percentage	
	g) Total Turnover per annum	Lakh
	h) Cost of production per annum	Lakh
	i) Net profitability	Lakh
	j) Employment in nos.	

(D) Details of Beneficiaries

Sr. No.	Name of the Beneficiary (Unit)	Gender	Religion	Social Category	Area of proposed workshed in sq.ft.	Machines proposed		Approx. cost of the machines to be purchased (Rs.lakh)
						Qty.	Type	
	TOTAL							

Note:

- If more than one beneficiary is sharing one shed, write their names consecutively and indicate one shed jointly against them.
- Please indicate Gender of Beneficiary -- M - Male, F - Female.
- Please indicate Religion of Beneficiary -- H - Hindu, M - Muslim, S - Sikh, J - Jain, C - Christain, O - Other.

d. Please indicate Social Category of Beneficiary--SC/ST/OBC/General.

(E) Details of expected annual contribution by the beneficiaries towards maintenance & repayment of loans

Sr. No.	Component	Amount (in Rs.)				
1.	Details of costs of maintenance/year					
	a) Worksheds					
	b) Infrastructure <ul style="list-style-type: none"> ➤ Supply of power ➤ Supply of water ➤ Maintenance of roads & drainages 					
	c) Watch & ward					
	d) Total Costs					
	e) Total area of worksheds					
	f) Maintenance Cost/Sq.ft. of workshed area per year					
2.	<u>Loan Repayment</u>	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
	* a) Total loan borrowed					
	b) Annual Repayment with interest					
	c) Annual payment to be done by beneficiary per sq.ft. of workshed area year-wise.					

(F) Details of expected annual contribution by the beneficiaries towards maintenance & repayment of loans

Sr. No.	Component	Amount (in Rs.)				
1.	Details of costs of maintenance/year					
	g) Worksheds					
	h) Infrastructure <ul style="list-style-type: none"> ➤ Supply of power ➤ Supply of water ➤ Maintenance of roads & drainages 					
	i) Watch & ward					
	j) Total Costs					
	k) Total area of worksheds					
	l) Maintenance Cost/Sq.ft. of workshed area per year					
2.	<u>Loan Repayment</u>	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5

	* a) Total loan borrowed b) Annual Repayment with interest c) Annual payment to be done by beneficiary per sq.ft. of workshed area year-wise.					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

* This is the loan amount borrowed by the EA for construction of worksheds and development of common facilities/infrastructure etc., if any.

For office use only :

Visited the site of Group Workshed of the EA i.e. M/s.....on and verified the documents submitted by the applicant and the proposal is recommended for sanction/ not recommended for reasons as under:

Signature of OIC

Regional Office of the Textile Commissioner,

Annexure-2

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We, the undersigned Directors of M/s....., (EA), a Company Registered under Company's Act 1956/LLP Act 2008, hereby undertake that the work shed Building Measuring an area of Sq. ft, situated at, constructed under Group Workshed Scheme (GWS) under Schemes for Knitting and Knitwear Sector Development (A Comprehensive Scheme For Development of Powerloom and Knitting & Knitwear Sector) launched by Govt. of India, Ministry of Textiles, shall be used only to install Technology Up gradation Fund Scheme (TUFS) compatible Machinery and shall not be utilized for any other purpose. Further, it is also declared that the said Company will function for a period of three years from the date of release of subsidy under GWS and availed by the company and the undersigned beneficiaries.

S.NO.	Name of the beneficiary	Designation	Signature
1		Managing Director	
2		Director	
3		Director	
4		Director	

The above resolution is passed by the company during the meeting held on -----and all the Directors of the company is aware of the same for the implementation of the said project under the Group Work shed Scheme.

Date :

Name :

Place :

Designation:

Name of the EA:

Seal of EA:

Annexure-3

Format for furnishing ESCROW account details for Agency creation with PFMS

(Note: All fields are mandatory)

S.No	Particulars	
1.	Agency Name (Name of Unit/EA/SPV)	
2.	Registration No. of EA/SPV	

3.	Date of Registration (DD/MM/YYYY)	
4.	Registration Authority	
5.	State of Registration	
6.	TIN Number	
7.	TAN Number	
8.	PAN Number	
9.	Address of Unit	
10.	City	
11.	District	
12.	State	
13.	Pin code	
14.	Contact Person & Mobile No. of Contact Person	
15.	ECSROW Account No. of Unit/EA/SPV	
16.	E-mail ID of the Unit/EA/SPV	
17.	Bank Name	
18.	Name of Branch and Address with pin code	
19.	City code of the bank	
20.	MICR Code of the bank	
21.	IFSC code of the bank	
22.	Branch Code of the bank	

Bank Stamp with Signature**Stamp with Signature of Unit/EA/SPV****Annexure-4****Reporting format of Local Level Monitoring Committee (LLMC) of the Group Workshed**

Sr No.	Details of LLMC Report	Recommendation of LLMC
1	Name and address of the Group work shed	
2	Date of LLMC	
3	Venue of the Meeting	
4	Stage of LLMC	
5	Names of LLMC Members present	
6	Present status of work Shed	
7	Area of work shed constructed	

8	Financial progress made so far	
9	Govt. approved Architect/ Chartered Engineer's Certificate	
10	Chartered Accountant Certificate	
11	Total area of the work shed approved	
12	Govt. of India Subsidy sanctioned	
13	Govt of India subsidy released	
14	Present area/construction of work shed completed	
15	Percentage of work completed	
16	Details of machinery proposed	
17	No. of machinery installed	
18	Eligible subsidy recommended	
19	Photographs with all members of LLMC and indicating the date & time	
20	Over all Remarks	

Signature of LLMC Members

Annexure-5

Format of application by the EA alongwith documents to be submitted for the release of first instalment of 30% GOI subsidy. (To be submitted within 90 days of the date of sanction)

To

Date-

The Officer Incharge,

Regional Office of the Textile Commissioner

Sir,

We herewith submit our claim for the release of first instalment of Govt. of India subsidy under the Group Workshed Scheme of PowerTex India. We are enclosing the following documents further necessary action.

1. Mortgage deed of the land to the Govt. of India on Ist charge/2nd charge in case of advance release of GOI share.
2. Chartered Accountant Certificate of expenditures incurred towards construction of Worksheds.
3. Certificate of proportionate expenditure by a Govt. approved architect.
4. Any other details.

You are requested to conduct necessary LLMC verification at the earliest.

Yours faithfully,
(Authorised signatory of EA)

Annexure-6

Format of application of claim by the EA alongwith documents to be submitted for the release of second instalment of 30% GOI subsidy. (To be submitted within 180 days of the date of sanction)

To _____ Date-

The Officer Incharge,
Regional Office of the Textile Commissioner

Sir,

We herewith submit our claim for the release of second instalment of Govt. of India subsidy under the Group Workshed Scheme of PowerTex India. We are enclosing the following documents further necessary action.

1. Chartered Accountant Certificate of expenditures incurred towards construction of Worksheds.
2. Certificate of proportionate expenditure by a Govt. approved architect.
3. Sanction letters of the bank for the Term Loan for purchasing plant and machineries for each beneficiaries /Executing agency for tie-up for funds for purchase of machineries.
4. Utilisation Certificate (UC) of Ist instalment.
5. Any other details.

You are requested to conduct necessary LLMC verification at the earliest.

Yours faithfully,
(Authorised signatory of EA)

Annexure-7

Format of application of claim by the EA alongwith documents to be submitted for the release of third instalment of 20% GOI subsidy. (To be submitted within 270 days of the date of sanction)

To _____ Date-

The Officer Incharge,
Regional Office of the Textile Commissioner

Sir,

We herewith submit our claim for the release of third instalment of Govt. of India subsidy under the Group Workshed Scheme of PowerTex India. We are enclosing the following documents further necessary action.

1. Chartered Accountant Certificate of expenditures incurred towards construction of Worksheds.

2. Certificate of proportionate expenditure and construction completion certificate by a Govt. approved architect.
3. Documents of placement of order for plant and machineries and advance / token money released to the machinery supplier by each beneficiaries / Executing agency.
4. Utilisation certificate (UC) of 2nd instalment.
5. Any other details.

You are requested to conduct necessary LLMC verification at the earliest.

Yours faithfully,
(Authorised signatory of EA)

Annexure-8

Format of application of claim by the EA alongwith documents to be submitted for the release of last instalment of 20% GOI subsidy. (To be submitted within 2 years of the date of sanction)

To

Date-

The Officer Incharge,

Regional Office of the Textile Commissioner

Sir,

We herewith submit our claim for the release of last instalment of Govt. of India subsidy under the Group Workshed Scheme of PowerTex India. We are enclosing the following documents further necessary action.

1. Chartered Accountant Certificate of expenditures on incurred on plant and machineries.
2. Invoices of plant and machineries towards installation of machineries by each beneficiary / EA.
3. Utilisation Certificate (UC) of 3rd instalment.
4. Any other details.

You are requested to conduct necessary LLMC verification at the earliest.

Yours faithfully,
(Authorised signatory of EA)

Annexure-9

Specimen of Surety Bond One Hundred Rupees Judicial Paper

BOND PRESCRIBED TO BE EXECUTED BEFORE GRANT IS RELEASED

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, M/s _____, a company incorporated under the LLP Act/Companies Act/Co-op. Society registered under Co-op Society Act of Govt. of _____ and having its registered office at _____ (hereinafter called the "Obligors") are held fully and firmly bounded to the President of India (hereinafter called the "Government") for the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment we firmly bind ourselves and our successors and assigns by these presents.

Signed on the _____ day of _____ in the year Two Thousand _____.

WHEREAS on the Obligors' request, the Government as per Sanction Order No. _____ Dated _____ of Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") which forms an integral part of these presents, and a copy whereof is annexed hereto and marked as Annexure-I, agreed to make in favour of the Obligors a grant of Rs. _____ (Rupees _____) for the purpose of construction of workshed and installation of specified machines at _____ out of which the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) have been paid to the Obligors (the receipt of which the Obligors do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligors executing a bond in the terms and manner contained hereinafter which the Obligors have agreed to do.

NOW the conditions of the above written obligation is such that if the Obligors duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, the above written Bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise, it shall remain in full force and virtue. The Obligors will abide by the terms & conditions of the grant by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligors shall not divert the grants and entrust execution of the Scheme or work concerned to another institution(s) or organization(s).

THAT the Obligors shall abide by any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the bond, the Obligors and the sureties individually and jointly will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the grant with interest of 10% per annum thereon. If a part of the grant is left unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, interest @10% per annum shall be charged upto the date of its refund to the Government, unless it is agreed to be carried over.

The Obligors agree and undertake to surrender/pay the Government the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive / have received or derived through / upon unauthorized use of (such as letting out the premises on adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that for which the grant was intended of the property) building created/acquired constructed largely from out of the Grant sanctioned by Government of India, Ministry of Textiles or the Administrative Head of the Department concerned. As regards the monetary value aforementioned to be surrendered/paid to the Government, the decision of the Project Approval Committee will be final and binding on the Obligors.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT

i) the decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Textiles on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obligors and;

ii) the Government shall bear the stamp duty payable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on behalf of the Obligors the day herein above written in pursuance of the Resolution No. _____ Dated _____ passed by the governing body of the Obligor, a copy whereof is annexed hereto as Annexure-II and on behalf of the sureties and by _____ for and on behalf of the president on the date appearing below:-

FOR

Signature of the AUTHORISED SIGNATORY

Signed for and on behalf of

(Name of the Obligor)

1. Signature of witness 2. Signature of witness

Name & Address Name & Address

TO BE FILLED UP BY THE OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

(ACCEPTED)

For and on behalf of the President of India

Designation _____

Date: _____

SUMMARY AND CHECKLIST OF DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED PROJECT PROPOSAL UNDER GROUP WORKSHED SCHEME.

Stages	Objective	Requirement	Checklist of documents required	Stage of submission of documents
1.	Sanction for construction of work shed.	Application to be submitted by the Executing Agency (EA) at concerned Regional office of the Textile Commissioner.	Application in Annexure- 1 of the guidelines along with 1. Executive summary of the project. 2. Nature of EA 3. Sale /lease deed of land in the name of EA. 4. Non-agricultural land certificate. 5. Approved layout plan.	For taking Sanction for construction of work shed.
2.	Forwarding application to office of the Textile Commissioner	Forwarding application by Regional office with recommendation to office of the Textile Commissioner for sanction within 30 days of receipt of application.	1. Executive summary of the project. 2. Nature of EA 3. Sale /lease deed of land in the name of EA. 4. Non-agricultural land certificate. 5. Approved layout plan. 6. Photos of the site.	----
3..	Claiming for release of first installment of 30 %.	1. EA has to claim within 90 days from the date of sanction. 2. Inform concern RO about 30 % completion of construction. 3. RO has to forward LLMC report to PDC within 10 days from the date of LLMC visit.	1. Mortgage deed of the land to GOI in case of advance release of subsidy. 2. CA certificate of expenditure incurred for construction of workshed. 3. Certificate of proportionate expenditure by Govt. approved architect. 4. Photos of the construction.	During LLMC visit.
4.	Claiming for release of second installment of 30 %.	1. EA has to claim within 180 days from the date of sanction. 2. Inform concern RO about 60 % completion of construction. 3. RO has to forward LLMC report to PDC within 10 days from the date of LLMC visit.	1. CA certificate of expenditure incurred for construction of workshed. 2. Certificate of proportionate expenditure by Govt. approved architect. 3. Utilization certificate of first installment. 4. Photos of the building construction. 5. Sanction letter of bank for the Term loan for purchasing plant &	During LLMC visit

Stages	Objective	Requirement	Checklist of documents required	Stage of submission of documents
			machineries for each beneficiary/EA	
5.	Claiming for release of third installment of 20 %.	1.EA has to claim within 270 days from the date of sanction. 2.Inform concern RO about 100 % completion of construction. 3.RO has to forward LLMC report to PDC within 10 days from the date of LLMC visit.	1.CA certificate of expenditure incurred for construction of workshed. 2.Certificate of proportionate expenditure by Govt.approved architect. 3.Photos of the building 4.Utilization certificate of second installment. 5. Documents of placement of order for plant & machinery by each beneficiary/EA & advance/token money released.	During LLMC visit
6	Claiming for release of fourth installment of 20 %.	1. EA has to claim within 2 years from the date of sanction. 2. Inform concern RO about installation & commissioning of plant & machinery. 3. RO has to forward LLMC report to PDC within 10 days from the date of LLMC visit.	1. CA certificate of expenditure incurred on plant & Machineries. 2.Submission of Invoices of Plant & Machineries 3. Utilization certificate of third installment. 4. C.E. Certificate for installation & commissioning of machineries.	During LLMC visit

V. Yarn Bank Scheme

1.0 Background

Small units in the Knitting and knitwear sector may have no capacity to purchase yarn in bulk from the open market due to high rate. They depend on local supplier of yarn for their day to day consumption. The local supplier sells the yarn at high rate and takes advantage of fluctuation in price. Due to this the small knitting and knitwear units are not able to get yarn at reasonable price and unable to plan his production. Therefore, it is necessary to set up yarn bank to assure the availability of yarn at reasonable rate, to the Knitting and knitwear sector units. Such Yarn Bank will help the small knitting and knitwear sector units to tide over the fluctuation in yarn prices.

Normal working capital cycle for Knitting and knitwear industry includes yarn procurement, work-in-process, folding at grey stage and sale of grey knitted fabrics and cash/creditors etc., taking approximately 2- 2 ^{1/2} months for completion of the cycle. Therefore, in a year, the SPV is expected to rotate the corpus funds including their contribution at least **4 - 5 times**.

1.1 Objectives

To enable small Knitting and knitwear units to purchase the yarn at wholesale rate and in large quantities by avoiding middle man/local supplier's charges by way of providing interest free corpus fund to Special Purpose Vehicle (SPV)/consortium of Knitting and knitwear sector units.

2. Period of Operation

As a component under A Comprehensive Scheme for Development of Powerloom and Knitting & Knitwear Sector, the Yarn Bank Scheme shall remain in operation for the period i.e. 01.07.2019 to 31.03.2020.

3. Financial assistance

Government shall provide interest free corpus fund maximum upto **Rs.200 lakh** per yarn bank to SPV/Consortium.

4. Eligible Criteria

- a. The Special Purpose Vehicles (SPV) would be constituted in the form of a registered Co-op. Society, a trust or in the form of a company registered under Companies Act, 1956 and a firm established under Limited Liability Partnership Act, 2008.
- b. Minimum 11 members are required to form SPV.
- c. The Members of SPV should be Knitting and knitwear sector and its allied industry unit, Co-operative Societies, Private Entrepreneurs and NGO's working for Knitting and Knitwear sector.

5. Pre-requisite

- a. The Special Purpose Vehicles (SPV) shall be registered as mentioned at 4 (a) above before applying for setting up of Yarn Bank.
- b. The SPV shall give undertaking
 - i. for arrangement of their own fund equal to the fund provided by the Government.
 - ii. for submission of the bank guarantee for 25% of Government share of the corpus fund (or) an alternate option like Mortgage of Property, Surety Bond, Promissory Note, etc. for 25% of the GOI Share in favour of Textile Commissioner valid for at least 3 years period.
 - iii. that all members of SPV are interested to participate in the Yarn Bank.
 - iv. that the corpus fund for yarn bank will be utilized by the SPV for purchasing and supply of the yarn to the members of SPV and Knitting and knitwear sector units in and around the cluster.
 - v. that they will arrange a suitable Warehouse for storage of yarn, safety / security arrangements and insurance.

The specimen format prescribed for the above purpose is at **Annexure-I**.

6. Term and Conditions for Implementation

The terms and conditions for providing corpus fund to SPV are as under:-

- a. Government shall provide interest free corpus fund maximum **Rs.200 Lakh** per yarn bank to SPV/Consortium.
- b. The SPV shall arrange their own fund equal to the fund sanctioned by the PAC within 60 days of the date of sanction.
- c. The said corpus fund provided by the Govt. shall be released to SPV against the bank guarantee for 25% of Government share of the corpus fund in favour of Textile Commissioner valid for at least 3 years period (or) an alternate option like Mortgage of Property, Surety Bond, Promissory Note, etc. for 25% of the GOI Share in favour of Textile Commissioner valid for at least 3 years period. Format of bank guarantee prescribed for this purpose is at **Annexure-II**
- d. The SPV will identify/provide a suitable Warehouse for storage of yarn with proper documentation, safety / security arrangements and insurance.
- e. GOI share of corpus will be deposited in the ESCROW account which will be jointly operated by one member of SPV and one member from the concerned Regional Office of Textile Commissioner. The Govt. of India share shall be deposited in the Escrow Account immediately after deposit of share of SPV and furnishing of prescribed Bank Guarantee. After opening of ESCROW account, the SPV shall submit their claim for Govt. Of India share of the corpus fund within 60 days of the date of sanction, in the prescribed format at **Annexure-III** along with the documents enlisted therein to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner who will in turn will forward to the Powerloom Development Cell of the Office of the Textile Commissioner within 10 days of the receipt of claim.
- f. The said corpus fund for yarn bank will be utilized by the SPV for purchasing and supply of the yarn and maintaining its stock required by the knitting and knitwear sector units in and around the cluster.
- g. The SPV should rotate the corpus fund including their contribution at least 4 – 5 times in a year.
- h. After implementation of the project SPV shall have to furnish monthly performance report to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner with a copy to the Office of the Textile Commissioner, Mumbai, in prescribed format at **Annexure-IV**.
- i. The SPV should maintain records properly with entry of each purchase and delivery of yarn, showing the details of members i.e. the membership numbers whom yarn is sold by the yarn bank in the enclosed performa at **Annexure-V**.

- j. The SPV should ensure that if the demand of the yarn is more than the availability, then the yarn supply should go to every member separately, and no members should be given the scheme benefit twice before each member is given the scheme benefit at least once as per their requirement.
- k. The said corpus fund will be available with SPV for **three years period**, extension of which may be considered by Project Approval Committee (PAC) on the basis of its performance.
- l. In case, due to any reason, amount is not recovered from the bank guarantee / security, then the SPV / consortium shall have to refund the amount with simple interest (10%) w.e.f. the date of expiry of three years to Govt. of India.
- m. The SPV will submit an application in prescribed format at **Annexure-VI** along with DPR to the Textile Commissioner through concerned Regional Office of Textile Commissioner for sanction of the project. The concerned Regional office of the Textile Commissioner will examine the proposal and forward the same along with recommendation within 30 days of the date of application.
- n. The said proposal for corpus fund will be further scrutinized by the Office of the Textile Commissioner and will be placed before Project Approval Committee (PAC) for approval within 60 days of the date of receipt from the concerned Regional Office of the Textile Commissioner.

7. Implementing Agency

The scheme will be implemented/ monitored by the Office of the Textile Commissioner through Regional Offices, in association with Knitting and Knitwear Export promotion councils, Knitting and knitwear sector Associations/Federations/Organizations, State Governments etc.

8. Project Approval Committee

All projects submitted under the scheme will be approved by the Project Approval Committee (PAC) constituted as under:-

Textile Commissioner	- Chairman
Joint Secretary (PL)	- Member
Representative from IFW	- Member
Joint Textile Commissioner/ Director/Deputy Director of Powerloom Development Cell in the Office of the Textile Commissioner	- Member Secretary

9. Monitoring and Review

- a. With a view to monitor the implementation of the scheme and ensuring proper usage of the benefit, the Textile Commissioner shall call for any documents/information from the SPV as may be deemed necessary.
- b. Failure on the part of SPV to submit any of the information / documents as called for by the Textile Commissioner within the specified time shall amount to breach of the provisions of the Yarn Bank Scheme and action as deemed fit including action to cancel the approval of the project, or premature recall of an immediate recovery of the corpus fund availed.
- c. The SPV shall function at least for a period of 3 years from the date of last release of the GOI share.
- d. Project Approval Committee (under PowerTex India) decisions/directions is final.

10. Redressal of Grievance

All grievances related to implementation of the scheme shall be submitted to the Textile Commissioner who will take necessary action to resolve the grievance.

Annexure-I

UNDERTAKING

I/We, _____ hereby undertake that

- (i) The SPV will arrange of their own fund equal to the fund provide by the Govt. of India.
- (ii) The SPV will arrange Bank Guarantee for 25% of Government Share of the Corpus Fund (or) an alternate option like mortgage of property, surety bond, Promissory Note etc. for 25% of Government Share in favour of Textile Commissioner valid for at least 3 year period from the date of issue of the bond.
- (iii) All Members of SPV interested to participate in the Yarn Bank Scheme under Scheme for Knitting and Knitwear Sector Development under PowerTex India.

- (iv) The interest free corpus fund for Yarn Bank under Scheme for Knitting and Knitwear Sector Development under PowerTex India will be utilized by the SPV for purchasing and supply of the yarn to the members of the SPV.
- (v) The SPV have identified a warehouse of area measuring _____ sq.ft located at (Full Address). Further, I/We undertake that the Safety/Security and Insurance will be done after the approval of the proposal.

Content of the undertaking are true and correct to the best of my/our knowledge.

Date:

Name:

Place:

Designation:

Name of the SPV:

Seal of SPV:

Annexure-II

To,

The President of India,

Acting Through the Textile Commissioner,

Nishtha Bhavan, New C.G.O. Building,

Mumbai- 400 020.

Bank Guarantee for utilization of Corpus for Yarn Bank under Schemes for Knitting and Knitwear Sector Development under PowerTex India.

Confirmation of this Bank Guarantee is available.

THIS DEED OF BANK GUARANTEE is executed by the..... Bank, (preferably a Nationalised Bank) a Banking Company within the meaning of the Companies Act, 1956 having its Registered Office at..... and one of its Branches at in favour of **the President of India acting through the Officer-in-charge, Regional Office of the Textile Commissioner, _____.**

WHEREAS the Project Approval Committee (PAC) constituted under the Schemes for Knitting and Knitwear Sector Development under PowerTex India has agreed to grant to (name and address of the SPV / Consortium) the benefit of utilisation of Corpus for Yarn Bank under PowerTex India (as amended from time to time) which was approved by the Ministry of Textiles, Government of India and issued by the Office of the Textile Commissioner, Mumbai vide letter No. _____ under the terms and conditions mentioned in the Guidelines of Yarn Bank Scheme under PowerTex India.

WHEREAS as the above said (name and address of the SPV / Consortium) is required to execute the Bond with such Surety and Security as may be specified by the Office of the Textile Commissioner, Mumbai binding themselves to fulfil the terms and conditions under the said Scheme.

WHEREAS The Officer-in-charge, Regional Office of the Textile Commissioner, _____ has called upon the above said (name and address of the SPV / Consortium) to furnish Security in the form of a Bank Guarantee for the fulfilment of the terms and conditions under the said Scheme.

AND WHEREAS the above said (name and address of the SPV / Consortium) has / have requested us (name of the Bank furnishing the Bank Guarantee) to furnish Bank Guarantee to the President of India acting through the Officer-in-charge, Regional Office of the Textile Commissioner, _____ for the amount due and payable under the above said Bond executed by (name and address of the SPV / Consortium).

WE, (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee) do hereby unconditionally and irrevocably agree to pay to the President of India acting through Textile Commissioner on demand forthwith as and when such demand is made by an Officer authorized in that behalf without any demur or protest the amount due and payable under the above said Bond namely Rs. **(Rupees _____ Only)**

by way of Loss or damage caused or suffered or on any other count by the President of India acting through the Textile Commissioner, by reason of non fulfilment of the terms and conditions laid down in the Guidelines of Yarn Bank Scheme under PowerTex India or by reason or any breach of any of the terms and conditions of the above said Bond or otherwise by the said (name and address of the SPV / Consortium) .

WE, (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee), unconditionally and unequivocally agree to pay the President of India acting through the Textile Commissioner, any money so demanded notwithstanding any dispute raised by the said (name and address of the SPV / Consortium) before any Court / Tribunal or any other Authority.

WE, (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee), further agree that the demand made by the President of India acting through the Textile Commissioner shall be conclusive as regards the amount due and payable by us under present agreement as our absolute and unequivocal liability.

WE, (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee), further agree that this Guarantee shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the implementation of the Guidelines of Yarn Bank Scheme under PowerTex India by the said (name and address of the SPV / Consortium) under the said Guidelines and it shall continue to be in force till all the said terms and conditions under the said Guidelines are fully discharged to **the Officer-in-charge, Regional Office of the Textile Commissioner, _____ or till Officer-in-charge, Regional Office of the Textile Commissioner, _____** Certifies that the terms and conditions under the said guidelines are fully and properly carried out and the said bond executed by the said (name and address of the SPV / Consortium) fully discharged.

We, (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee), further agree that the President of India acting through the Textile Commissioner shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner or obligation under this Bank Guarantee to vary any of the terms and conditions laid down in the Guidelines of Yarn Bank Scheme under PowerTex India or extend the time for performance under the said Guidelines of Yarn Bank Scheme under PowerTex India or to forebear or enforce any to the terms and conditions of the above said Guidelines and we shall not be relieved or our liability under this Bank Guarantee by reason of any such variation or extension of forbearance or indulgence or any act of commission on the part of the President of India acting through the Textile Commissioner which under the law relating to sureties, but for its provision, have the effect of so relieving us (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee).

WE, (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee), declare that this shall be a continuing Bank Guarantee and shall not be discharged by any change in the constitution of the said (name and address of the SPV / Consortium). We further declare that we will not revoke this Bank Guarantee during its currency without prior written consent of the President of India acting through the Textile Commissioner.

WE, (name and address of the Bank furnishing the Bank Guarantee), further declare that this Bank Guarantee will be valid up to _____ **from _____ to _____** and we undertake to renew this Bank Guarantee on our own till the matter is settled and fully discharged by **the Officer-in-charge, Regional Office of the Textile Commissioner, _____** or till any demand is raised pursuant to this Bank Guarantee by the President of India acting through the Textile Commissioner.

Notwithstanding anything contained herein above.

1. Our liability under the Bank Guarantee shall not exceed **Rs. _____ (Rupees _____ Only).**
2. This Bank Guarantee shall be valid up to _____ .
3. We are liable to pay the guarantee amount or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if you serve upon us a written claim or demand.
4. We further declare that this Bank Guarantee will be renewed automatically; we undertake to renew this Bank Guarantee on our own till the matter is settled and fully discharged by the Officer-in-charge, Regional Office of the Textile Commissioner, _____.

ANNEXURE-III

Format of application of claim by the SPV alongwith documents to be submitted for the release of Govt. of India share of Yarn Bank Scheme. (To be submitted within 60 days from the date of sanction)

To

Date-

The Officer Incharge,

Regional Office of the Textile Commissioner

Sir,

We herewith submit our claim for the release of Govt. of India share towards Yarn Bank Scheme. We are enclosing the following documents for further necessary action.

1. Escrow account details with the copy of the mandate form.
2. Proof of warehouse/godown for yarn storage.
3. Bank statement showing the deposit of equal amount of Govt. share in the Escrow account.
4. Document showing that the Officer in charge of the concerned Regional Office of the Textile Commissioner inducted as one of the Directors of the SPV.
5. 25% Bank Guarantee on GoI share valid at least for a period of 3 years.
6. Any other details.

You are requested to forward the above claim to the Office of the Textile Commissioner along with your recommendation.

Yours faithfully,

(Authorised signatory of SPV)

Annexure-IV																			
Monthly Progress Report of Yarn Bank																			
Name of SPV:																Report dated			
Month	Opening stock of yarn in Kgs		Value of Yarn in Rs.		Qty of yarn purchased in Kgs		Value of Yarn in Rs.		Qty of yarn sold in Kgs		Value of Yarn in Rs.		Closing stock of yarn in Kgs		Value of Yarn in Rs.		Turnover in Rs.	No. of Members added in SPV, if any	No. of Members discarded in SPV, if any
	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S			
April, 2019																			
May, 2019																			
June, 2019																			
July, 2019																			
August, 2019																			
Sept., 2019																			
Oct., 2019																			
Nov., 2019																			
Dec., 2019																			
Jan., 2020																			
Feb., 2020																			
March, 2020																			

Report shall be furnished on 5th of every month

C-cotton

S- Synthetic Yarn

Signature of OIC

Regional Office of the Textile Commissioner:_____

Annexure-V**Details of Monthly Purchase & Sales of Yarn Bank Scheme**

Name of SPV:

Name of R.O.:

Month:

Sr. NO.	Date	Opening stock (in Kgs.)	Purchase (in Kgs.)	Total (in Kgs.)	Delivery			Yarn supplied (in Kgs.)	Closing Stock (in Kgs.)	Remark
					Membership No.	Share of the Member	No. of Knitting M/c.			

ANNEXURE-VI**APPLICATION FOR YARN BANK SCHEME**

Sl. No.	PARTICULARS	To Filled up by SPV
1.	Name of the SPV	
2.	Address of SPV	
3.	SPV registered under	
4.	Registration No. and Date	
5.	No. of Members of SPV & the list of Members in the enclosed format at Annexure-VII	
6.	No. of Knitting Machines with SPV	
7.	Name of the Cluster	
8.	No. of Knitting machines in the Cluster (i) Ordinary Circular Knitting Machine (ii) High speed Circular Knitting Machine (iii) High Speed socks knitting and gloves knitting machines with or without	

	electronic jacquard (iv) Computerized flat bed knitting machine with minimum speed of 11 revolutions per minute (v) Warp/Raschel Knitting Machines (vi) High speed computerized warping machine for Knitting (vii) Computerized label making machine (viii) Computerized strap (Collar/Cuff) flat bed knitting machine (ix) Others Knitting Machines	
9.	No. of knitwear (stitching) machines in the Cluster	
10.	Name of Products Manufactured	
11.	Variety of yarn used in the Cluster (Cotton/Synthetic/Blended)	
12.	Total Kgs. of yarn required per annum	
13.	Total fund required per annum to purchase the said yarn	
14.	Interest free corpus fund required by SPV	
15.	Details of funds arranged by SPV equal to the amount of fund requested for interest free corpus fund from Govt of India	
16.	Details of funds arranged by SPV & Bank Guarantee for three years	
17.	Details of suitable warehouse for storage of yarn with proper documentation, safety/ security arrangements and insurance	
18.	List of documents enclosed	

Date :**Name :****Place :****Designation:****Name of the SPV:****Seal of SPV:****For office use only :**

Visited the location of proposed yarn bank of SPV on and verified the documents submitted by the SPV. The proposal is recommended for sanction/ not recommended for reasons as under:

Signature of OIC

Regional Office of the Textile Commissioner.....

ANNEXURE-VII**Details of SPV**

Name and Address of the SPV:

Details of SPV and its Members

Sl. No.	Name of the Member/Unit	Contact details (E-mail Id./Mobile No.)	Designation in the SPV	Number of Knitting Machines owned by the Member/ Unit	Contribution by the Member/Unit to the corpus fund in Rs.

SUMMARY AND CHECKLIST OF DOCUMENTS REQUIRED

Yarn Bank Scheme under Scheme of Knitting & Knitwear Sector Development under PowerTex India

Stages	Objective	Requirement	Checklist of documents required	Stage of submission of documents
1.	Application for Sanction of corpus for yarn bank	Application to be submitted by the SPV at concerned Regional office of the Textile Commissioner. RO has to forward application to Powerloom Development Cell within 30 days from the date of receipt with recommendation.	Application in Annexure- VI of the guidelines along with 1. Nature of SPV. 2. Bank guarantee for 25% of GOI share. 3. Arranging own fund equal to the fund provided by GOI. 4. Sale/lease deed of suitable warehouse for storage of yarn.	During submission of application.
2.	Sanction of corpus for yarn bank	Powerloom Development Cell to convey the sanction to SPV within 60 days from the receipt of application from Regional office.	Application in Annexure- VI of the guidelines along with 1. Nature of SPV. 2. Bank guarantee for 25% of GOI share. 3. Arranging own fund equal to the fund provided by GOI. 4. Sale/lease deed of suitable warehouse for storage of yarn. 5. Insurance for warehouse.	----
3.	Claim for releasing of GOI share	SPV has to submit the claim within 60 days from the date of sanction. RO has to forward the claim to PDC within 10 days from the date of receipt.	1. ESCROW account details. 2. Copy of the Bank guarantee for 25% of GOI share. 3. Proof of fund equal to the fund provided by GOI in ESCROW account.	Before release of GOI share.

Format for furnishing ESCROW account details for Agency creation with PFMS*(Note: All fields are mandatory)*

S.No	Particulars	
1.	Agency Name (Name of Unit/EA/SPV)	
2.	Registration No. of SPV	
3.	Date of Registration (DD/MM/YYYY)	
4.	Registration Authority	
5.	State of Registration	
6.	TIN Number	
7.	TAN Number	
8.	PAN Number	
9.	Address of Unit	
10.	City	
11.	District	
12.	State	
13.	Pin code	
14.	Contact Person & Mobile No. of Contact Person	
15.	ECSROW Account No. of Unit/EA/SPV	
16.	E-mail ID of the Unit/EA/SPV	
17.	Bank Name	
18.	Name of Branch and Address with pin code	
19.	City code of the bank	
20.	MICR Code of the bank	
21.	IFSC code of the bank	
22.	Branch Code of the bank	

Bank Stamp with Signature**Stamp with Signature of /SPV****VI. Common Facility Centre****COMMON FACILITY CENTRE SCHEME (CFC) FOR KNITTING & KNITWEAR CLUSTER**

The most critical problems being faced in the Knitting & Knitwear sector are the low level of technology prevalent therein, coupled with widespread fragmentation of knitting & knitwear units, lack of economies of scale, lack of pre & post knitting facilities and design development/testing facilities in Knitting & Knitwear clusters in order to overcome poor productivity, generally poor product quality and low unit realization etc.

Objective:

To establish Common Facility Centres (CFC) in various Knitting & Knitwear clusters and provide pre & post knitting and other infrastructure facilities to group of knitters/units joined together, Knitting & Knitwear sector industry associations and other organizations allied with Knitting & Knitwear sector industry by way of providing financial assistance for the setting up of Common Facility Centres (CFC). The Common Facility Centre will house

design centre / studio, testing facilities, training centre, information cum trade centre and common raw material / yarn / sales depot, water treatment plant for industrial use, dormitory for workers, common pre-knitting facilities viz. A-TUF Compatible Yarn processing and post knitting facilities viz. A-TUF Compatible fabric Processing machines, Folding machine, cutting machine & stitching machines and post knit wear facilities viz. A-TUF compatible garment processing machines. There can also be other tangible assets that could be set up in clusters, as long as they are put to common use by decentralized Knitting & Knitwear units in and around the cluster.

Period of Operation of Scheme:

Common Facility Centre Scheme (CFC) for Knitting & Knitwear Clusters under PowerTex India will be in operation from 01.7.2019 to 31.03.2020.

Eligibility of SPV:

It is necessary to form a Special Purpose Vehicle (SPV) with at least 11 members prior to setting up and running the proposed Common Facilities Centre. The SPV registered under Companies Act, 1956, registered Co-operative societies, a trust, Limited Liabilities Partnership (LLP) firm registered under LLP Act, 2008, State Government/State Government Agencies are eligible for establishment CFC under the Scheme. The members of the SPV should be the stake holders i.e. weavers, master weavers, private entrepreneurs, NGO's working for Knitting & Knitwear sector, Co-operative societies.

Operation of SPV:

In addition to the contributing members of the SPV, the organizers should obtain written commitments from as many 'users' of the proposed facility so that its benefits can be further enlarged.

The SPV should have a democratic constitution with an inbuilt scope for increasing the membership including individual Knitting & Knitwear entrepreneurs in future.

The SPV will be required to interact with the weavers and tie up with the connected organizations like banks/ financial institutions, market institutions / market experts, marketers, legal experts, Government machineries etc.

The SPV will prepare project report for setting up of the Common Facilities Centre / yarn depot, infrastructure etc. specifying inter-alia annual action plans, clearly indicating the requirement of the cluster, activities and expected outputs, outcomes / deliverables time limit for completion of the projects and submit the proposal in the prescribed formats **Annexure I & II** along with documents enlisted in the checklist at **Annexure-III** to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner. Regional Office of the Textile Commissioner will examine the proposal and forward the same to the Office of the Textile Commissioner along with their recommendation within 30 days of the receipt of the proposal. The Office of the Textile Commissioner will further scrutinize the proposal and place the same before the Project Approval Committee (PAC) on the receipt of the proposal from the concerned Regional Office of the Textile Commissioner.

The SPV will also submit physical and financial progress report periodically and also, completion report to the Textile Commissioner.

After completion of the projects, the SPV will continue as consortium for the Knitting & Knitwear units to run and maintain the common facilities/infrastructure.

The SPV shall not charge the non SPV members more than 20% of the charges they charge to their own SPV members towards the usage of Common Facility Centres, since the Govt. of India subsidy is provided for the establishment of CFC.

Conditions:

- (i) More than one proposals/ projects in a single cluster are allowed as per the requirement of the cluster without restricting the maximum subsidy limit per CFC. However, the SPVs of CFCs shall not have any common Director i.e., Director of one SPV of a CFC shall not be a Director of any other SPV of CFC.
- (ii) Owned Land/Building, Leased land/Building registered in favor of SPV for minimum period of 10 Years is to be arranged by SPV before submitting the proposal for financial assistance from Govt. of India is prerequisite.
- (iii) A minimum of 11 members are required to form an SPV
- (iv) In case of any change in project profile, the approval of PAC is to be obtained.
- (v) Only A-TUF compatible machineries are eligible to install in the CFC.
- (vi) In case of non utilization/mis-utilisation of subsidy and delay in completion of the project, as approved by PAC, funds released shall be recovered from the Executive Agency with simple interest @10% per annum.
- (vii) PAC decision will be the final.

- (viii) Multi source funding should be allowed provided the beneficiary contributes at least 5 % of the cost of project/equipment being subsidized by both the central and state government will be capped at 95 % of the eligible cost of the project/equipment.
- (ix) Subsidized assets are retained by the beneficiary for a period of at least 5 years from the date of release/withdrawal of subsidy from Escrow account.
- (x) Certificate of Commissioning of machineries should also be obtained from the Chartered Engineer during the final LLMC.

Eligible facilities, Machines, Equipments, Instruments etc under the Scheme:

Common Facility Centre will house design centre / studio, testing facilities, training centre, information cum trade centre and common raw material / yarn / sales depot, water treatment plant for industrial use, dormitory for workers/ worker's residential place, common pre-knitting facilities viz. A-TUF Compatible Yarn processing and post knitting facilities viz. A-TUF Compatible fabric Processing machines, Folding machine, cutting machine & stitching machines and post knit wear facilities viz. A-TUF compatible garment processing machines. There can also be other tangible assets that could be set up in clusters, as long as they are put to common use by decentralized Knitting & Knitwear units in and around the cluster.

Quantum of Subsidy:

(i) The Common Facility Centre is entitled to the different levels of assistance from the Government on the basis of different grading of Knitting & Knitwear clusters i.e.,:

- Grade - A - subsidy upto 60% of project cost.
- Grade - B - subsidy upto 70% of project cost.
- Grade - C - subsidy upto 80% of project cost.
- Grade - D & clusters in NER/J&K - subsidy upto 90% of project cost.

The grading of the clusters will be done by a Committee constituted by the Textile Commissioner. The criteria for grading the Knitting & Knitwear Cluster is indicated at **Annexure-IV**.

(ii) Assistance available for setting up of Common Facilities Centre including Yarn depot will be Rs. 400 lakh per CFC.

(iii) The project cost for providing the above assistance will include the following:

The cost of building, the cost of Plant and machinery, equipment, laboratory, other tangible assets, pre-operative/preliminary expenses etc.

(iv) Only 25% of the construction cost of the building will be eligible as subsidy subject to the maximum limit of Rs.80 lakhs. The schedule of rates of CPWD as in the state shall be used as the basis for arriving at the cost estimates of construction of building.

(v) Proposals, where Building is already in existence, construction of the building is completed prior to sanction of the proposed CFC and registered lease building, then such proposals are allowed under CFC provided the building should be registered in the name of the SPV or the lease agreement of the building in favour of the SPV should be at least for 10 years. However, in such cases, subsidy shall be allowed only for the eligible machinery component and no subsidy will be given for the construction component.

(vi) For Example:

Project cost		Maximum eligible cost for calculating the assistance
Machinery, plant, equipment, laboratory, other tangible assets, pre-operative/preliminary expenses, etc.	Rs.3.20 crore	Rs. 3.20 core
Construction of Building	Rs.2.00 crore	Rs. 0.50 crore
Total	Rs.5.20 crore	Rs 3.70 core

Release of Assistance:

The SPV will open an escrow account with any schedule bank and all payments for CFC will be made through escrow account which will be jointly operated by one member of SPV and one member from Regional Office.

The SPV should submit the claim for release of financial assistance to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner.

Safeguard against Mis-utilisation:

- (i) The land on which Common Facility Centre is proposed for establishment must have clear title for use in favour of SPV and also must have all NOC from local bodies, Municipal Authority, State Administrative and State Pollution Control Board as applicable.
- (ii) In order to avoid default by the beneficiaries, the mortgage of assets on 1st or 2nd charge would be taken in all cases approved under the scheme failing which the beneficiary shall execute surety bond as per the format (**Annexure-V**) before release of funds.
- (iii) The SPV shall function at least for a period of five years from the date of release of last installment of GOI subsidy.
- (iv) In case of non utilization/mis-utilisation of subsidy and delay beyond 18 months in completion of the project, as approved by PAC, funds released shall be recovered from the SPV with simple interest @10% per annum from the date of release to date of refunding back the amount.
- (v) Before releasing the 1st installment it will be ensured that the cost of land is more than the amount (1st installment) being released to the SPV.
- (vi) Utilization of Govt. subsidy will be made through the Escrow account indicated in the foregoing para i.e release of assistance.

Implementation:**Local Level Monitoring Committee (LLMC):**

Local Level Monitoring Committee will be formed for each CFC; which will include an officer from the Regional Office of the Textile Commissioner, a representative of the SPV preferably Director and State Govt officer. The eligible financial assistance will be released only after getting the physical verification report of LLMC as per format at **Annexure-VI**.

The following schedule will be adopted for release of GOI subsidy to the SPV:

1st instalment: 30% of the total GOI share will be released, after submission of the claim by the SPV in the prescribed format at **Annexure-VII** along with documents enlisted therein to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner within 90 days of the sanction after the proportionate expenditure incurred by the SPV for construction which is approved by a Govt. Architect and Chartered Accountant. The LLMC will submit the report to the Office of the Textile Commissioner within 30 days of the submission of claim.

2nd instalment: 30% of the total GOI share after getting the utilization Certificate of 1st instalment and after submission of claim by the SPV in the prescribed format at **Annexure-VIII** along with documents enlisted therein to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner within 180 days from the date of sanction and the proportionate expenditure by the SPV, on completion of 60 % or above construction which will be duly approved by the Govt. Architect and Chartered Accountant.

The LLMC will submit the report to the Office of the Textile Commissioner within 30 days of the submission of claim.

3rd instalment: 40% of the total GOI share will be released after the successful completion of the construction of the building/shed and after submission of claim in prescribed format **Annexure-IX** along with documents enlisted therein to the concerned Regional Office of the Textile Commissioner within 270 days from the date of sanction and certification by Govt. Architect and Chartered Accountant. The LLMC will submit the report to the Office of the Textile Commissioner within 30 days of the submission of claim.

Financial Assistance for the machinery & equipments will be released after its purchase, installation, commissioning, commencement of Commercial Production and after submission of claim in the prescribed format at **Annexure-X** along with documents enlisted therein to the Regional Office of the Textile Commissioner. The LLMC will submit the report to the Office of the Textile Commissioner within 30 days of the submission of claim.

In case of CFC approved with pre existing building facilities on ownership/lease basis the time limit for the completion of the project is only 01 year from the date of communication of the PAC decision and the subsidy towards the project will be processed on installation & commissioning of machines & submission of LLMC report.

Annexure-I**1. Information about cluster & its Study to be submitted by SPV with their proposal for financial assistance for CFC****Summary Details of the Proposed Cluster**

1. Location: (State, city/town/village)

2. The SPV/Co-op. Societies/Trust/Company, name of the contact person authorised in SPV in the cluster along with address, telephone no., fax, e-mail address, mobile no., etc.:

S.No	Name of the member	Contact details (Email & Mobile)	Designation of the member in the SPV	No. of Knitting & Knitwear machines owned by the member	Contribution of the member

3. Bank's details of SPV

4. Name of Products

5. Nature of the Cluster:

(a) Total No. of micro and small enterprises

(b) No. of enterprises of each category

(i) micro,

(ii) small,

(iii) women-owned,

(iv) owned by SC,

(v) owned by ST,

(vi) owned by minorities

(c) Total turnover of the cluster including exports

(d) Average yearly income of men/ women of workers/ unit owner

(e) pollution angle, if any

6. Major Cluster Problems: [Preliminary perception – Give in one or two page]

7. Key Intervention expected under Proposed CFC: Technology Improvement / Product Quality / Marketing / Export / Quality/ Design, etc.

8. Extent of Competition: With large domestic firms or other similar clusters in India or abroad [Give in one page]

9. Name of organisation/Committee which have assessed/evaluated/conducted/diagnosed the study of cluster with details of its appointment/nomination.

2. Check list for Common Facility Centre to be submitted by SPV with their proposal for financial assistance for CFC

I. What are the similar facilities in the cluster and the challenges faced by them.

II. How is the present CFC addressing these challenges.

III. What is (or are) proposed as “Common Facilities”? Give benefits of each in 2-3 sentences.

IV. These facilities already available if any, in cluster? Give its details.

V. From where these facilities are being availed at present? In absence of these facilities what problems are the units facing?

VI. Is there any other such facility established by Govt. /NGO in the Cluster or nearby to cater the need?

- VII. Is the above facility being fully utilised? If no, what are the reasons?
- VIII. How many units have confirmed that they are going to join the SPV? List may be given.
- IX. Has SPV been constituted? Whether the members of the SPV have agreed to give their contribution. (formal letter of agreeing for contribution, certificate of incorporation, articles of association etc.).
- X. Nature of SPV (open or close ended) - Whether enrolment of cluster members will open at any time in future and to that extent provision has been made in the capital structure of SPV (paid up capital should not be more than 30% of the authorized capital).
- XI. How many other units wish to avail the common facility as “users”, without joining SPV?
- XII. Has the suitable plant and machinery been identified, their specification and quotation invited for the purpose of DPR?
- XIII. Name of the Agency who has prepared the DPR for the proposed CFC?
- XIV. Whether “in-principle” approval from the bank has been obtained, in case loan is being availed of.
- XV. Whether the State Govt. has been contributing in CFC, the confirmation of State Government for their contribution may be given.
- XVI. Name of committees of SPV for implementing the project, including the 'purchase committee'.
- XVII. Management Information System (MIS) for reporting/monitoring progress of work.
- XVIII. Has the capacity of plant and machinery been established on the basis of demand in the cluster? Evidence that CFC will be utilized at least 60% of their capacity.
- XIX. Whether viability-gap funding has been worked out for availing GoI assistance on the basis of following:
- Types of plant and machinery absolutely needed for the CFC.
 - The capacity of plant and machinery and their number on the basis of total demand of the services from the CFC.
- XX. Whether the “user charge” has been determined on the basis of the following:
- Will it generate sufficient revenue to meet all its cost of production?
 - Has Depreciation been calculated on written down value?
[NPV of the total depreciations during the usable life of plant and machinery should be equal to cost of plant and machinery]
 - There will be differential user charges: one for members of SPV and other for non-members. The user charges for the members may be fixed in a manner that they are suitably compensated towards the contribution made by them.
- XXI. Whether the CFC proposal comply with financial norms of appraisal, i.e. internal rate of return, break-even point analysis, debt service coverage ratio, sensitivity analysis, etc, using basic templates, such as projected profit & loss account, and projected balance sheet for the proposed CFC. Full details may be given.

Elements of Detailed Project Report to be submitted by SPV with their proposal for financial assistance for CFC

(1) Plant and Machinery

(a) List of Plant and Machinery

Sr. No.	Particulars of plant and machinery	No.	Power requirement (HP/KW)	F.O.R. Price (Rs)	Name of proposed suppliers	Delivery Schedule (month-wise)
---------	------------------------------------	-----	---------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------

Note: Add GST, packing and forwarding charges, transit insurance, and freight charges to costs.

(b) Capacity of plant and machinery on single shift basis

(c) Production pattern

(2) Annual requirement of raw materials and consumables at 100 % capacity utilisation

Sr. No.	Particulars of raw material	Quantity required at full capacity	Unit price (Rs.)	Total value (Rs.)
---------	-----------------------------	------------------------------------	------------------	-------------------

(3) Utilities and services at full capacity utilization

(a) Power for industrial purpose

Sr. No.	Particulars of the machinery	KW	No. of working hrs. per month	KW/month	Rs./KWH	Total
---------	------------------------------	----	-------------------------------	----------	---------	-------

(b) Power requirement for domestic purpose

(c) Water

(d) Gas/Oil

(4) Plant location, site and details of civil construction

Sr. No.	Particulars	Rate	Total Cost (Rs. in lakh)
(i)	Cost of land		
(ii)	Development cost of land & its development, if any		
(iii)	Cost of construction of shed/building including compound wall if any for the purpose of CFC		

- Land documents may be enclosed indicating that it is in the name of SPV whether on purchase or lease basis.
- The copy of NA Certificate for land may be enclosed.
- Building lay-out & Building Plan approval may be enclosed.

(5) Organizational set up and man power requirement

Sr. No.	Category	No. of persons	Salary per month (Rs)	Total salary (PM)
---------	----------	----------------	-----------------------	-------------------

Note: Add 25% towards fringe benefits and 5% annual increment

(6) Project cost

Sr. No.	Particulars of cost	Amount (Rs.)
(i)	Land & site development cost (Total area)	
(ii)	Building/shed for the purpose of CFC (Total sq.ft. of construction). The cost will be inclusive of Misc. fixed assets (fixture, furniture, firefighting equipment, first aid equipment, backup power supply, etc.)	
(iii)	Plant and machinery (cost of plant and machinery + 10% installation, electrification and commissioning)	
(iv)	Preliminary expenses (diagnostic study, DPR, legal & administrative expenses, telephone, stationery, etc.)	
(v)	Pre-operative expenses (establishment, travel, interest on borrowings, committed charges during construction period, start up expenses, etc.)	
(vi)	Provision for contingencies (2% building and 5% on plant and machinery)	
(vii)	Margin money for working capital	
Total		

(7) Means of finance

Sr. No.	Agency	Amount(Rs. lakh)	% of the project cost
1.	SPV		
2.	GOI		
3.	State Govt. if any		
4.	Bank Borrowings		
5.	Others		

(8) Working capital and margin money calculation (on the basis of actual capacity utilisation year wise)

Sr. No.	Particulars	No. of months	Margin	1st year (as per capacity utilisation)	2nd Year (as per capacity utilisation)	3rd year (as per capacity utilisation)
1.	Raw material and consumables					
2.	Utilities					
	Working expenses (salary of manpower)					
4.	Works in process (cost of raw material, utility and salary on actuals)					
5.	Stock of finished goods (cost of raw material, utility, salary, factory overheads on actuals)					
6.	Bills receivables (Sales value)					

Broad parameters of financial viability of CFC and likely year of its becoming financially viable (Rs. in lakh)

Working expenses**		Revenues**	
1. Salaries		1. Revenue stream 1 (specify)	
2. Consumables		2. Revenue stream 2 (specify)	
3. Depreciation		3.	
4. Others (specify)		4.	
5. Total		5. Total	

**** Note:** Please give year-wise projections, till attainment of viability.

(9) Cost of production (projection could be for a maximum of 10 years of project life)

- (i) Raw materials and consumables
- (ii) Utilities
- (iii) Wages and salary
- (iv) Repairs and maintenance

- (v) Insurance
- (vi) Administrative and factory overheads
- (vii) Selling expenses

(10) Estimation of profitability (projection for the project life)

- (i) Installed capacity
- (ii) Number of working days (single shift basis)
- (iii) Capacity utilization
- (iv) Production (in single unit)
- (v) Sales realization
- (vi) Cost of production
- (vii) Gross profit [(v)-(vi)]
- (viii) Financial expenses
 - (a) Interest on bank borrowing
- (ix) Depreciation on written down value method (as per separate schedule to be attached for different categories of fixed assets)
- (xi) Preparatory expenses not written off
- (xi) Operating profit [(vii) – {(viii) + (ix) + (x)}]
- (xii) Tax vide separate schedule
- (xiii) Profit after tax [(xi) – (xii)]
- (xiv) Available surplus [(xiii) + (ix)]

(11) Cash flow statement (projection for the project life)

(A) Sources of fund:

- (a) Gross profit less depreciation
- (b) Term loan
- (c) Subsidy/Grant
- (d) Promoter's contribution
- (e) Increase in bank borrowings
- (f) Depreciation

(B) Disposal of funds:

- (a) Preliminary & pre-operative expenses
- (b) Capital expenditure
- (c) Increase in working capital
- (d) Interest on term loan
- (e) Interest on bank borrowings
- (f) Decrease in term loan
- (g) Taxes

(C) Opening balance of cash in hand or at bank [sum total of {(A)-(B)}]

(D) Net surplus/Deficit

(E) Closing balance of cash in hand or at bank

(12) Debt Service coverage ratio (projection for the project life)

- (i) Available surplus as per the table at Sr. No. 10(xiv)

(ii) Interest on term loan

(iii) Term loan instalment

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = [Available surplus + interest on term loan]/[Term Loan instalment + interest on term loan]

(13) Balance sheet & P/L account (projection for 10 years)

(14) Break even point = Fixed cost / Contribution (= Sales-Variable cost)

Annexure-II

Application for sanction of Common Facilities Centre under PowerTex India

S.NO.	Particulars	Details																														
	Name & address of the SPV, its constitution along with copy of the Memorandum and Articles of Association, ROC/Partnership deed/Society Registration as the case may be.																															
	<table border="1"> <tr> <th>S.No.</th><th>Name of the member</th><th>Contact details (Email & Mobile)</th><th>Designation of the member in the SPV</th><th>No. of Knitting & Knitwearunits owned by the member</th><th>Contribution of the member</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	S.No.	Name of the member	Contact details (Email & Mobile)	Designation of the member in the SPV	No. of Knitting & Knitwearunits owned by the member	Contribution of the member																									
S.No.	Name of the member	Contact details (Email & Mobile)	Designation of the member in the SPV	No. of Knitting & Knitwearunits owned by the member	Contribution of the member																											
	Contact Mobile no of SPV & E mail ID																															
	Name of the cluster where CFC is proposed to be set up alongwith DPR																															
	Proof of Identity of the members of the group alongwith copy (PAN Card/ Bank Pass Book/ Aadhar Card/ Ration card/ Voter Card)																															
	Full address of the SPV where the CFC will be set up																															
	a. Area of land/Building documents for the proposed location (own/ leased). Registered land deed copy as the case may be b. Size of the Factory building																															
	a. Area of land documents for the proposed location (own/ leased). Registered land deed copy as the case may be b. Size of the Factory building																															
	Means of finance:																															
	<table border="1"> <tr> <th>S.no.</th><th>Components</th><th>Promoter contribution</th><th>GOI subsidy</th><th>Bank loan</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Factory Building</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Plant & Machinery</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Other eligible investment</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	S.no.	Components	Promoter contribution	GOI subsidy	Bank loan	Total	1	Factory Building					2	Plant & Machinery					3	Other eligible investment					TOTAL						
S.no.	Components	Promoter contribution	GOI subsidy	Bank loan	Total																											
1	Factory Building																															
2	Plant & Machinery																															
3	Other eligible investment																															
TOTAL																																

Place :

Date :

(Signature of SPV)

.....

For office use only :

Visited the location of proposed CFC on and verified the documents submitted by the SPV and the proposal is recommended for sanction/ not recommended for reasons as under:

Signature of OIC

Regional Office of the Textile Commissioner,

Annexure-III**Checklist of documents to be submitted along with detailed project report (DPR)**

1. Copy of the registration of land in the name of SPV or copy of the registered lease deed of the land not less than 10 years, as applicable.
2. Non-agriculture land certificate issued by the concerned Gram Panchayat/District Town Planning Authority or any other competent authority, as applicable.
3. Layout Plan for construction of Common Facility Centre duly approved the concerned Gram Panchayat/District Town Planning Authority or any other competent authority, as applicable.

Annexure-IV

Reporting format of Local Level Monitoring Committee(LLMC) of the CFC

S. No.	Details of LLMC Report	Recommendation of LLMC
1	Name and address of the CFC	
2	Date of LLMC	
3	Venue of the Meeting	
4	Stage of LLMC	
5	Names of LLMC Members present	
6	Present status of work Shed / installation of Machinery	
7	Area of work shed constructed	
8	Financial progress made so far	
9	Chartered Engineer's Certificate	
10	Chartered Accountant Certificate	
11	Total area of the work shed approved	
12	Govt. of India Subsidy sanctioned	
13	Govt of India subsidy released	
14	Present area/construction of work shed completed	
15	Percentage of work completed	
16	Details of machinery proposed	
17	No. of machinery installed	
18	Eligible subsidy recommended	

19	Photographs with date & Time	
20	Over all Remarks	

Signature of LLMC Members

Annexure-V

Criteria of grading the Knitting & Knitwear cluster

Sr. No.	Criteria	Total Mark	Mark allotted by Committee
1.	Total number of knitting & knitwear machines	10	
2.	Technology level	25	
3.	Product Profile	20	
	Low value fabrics		
	Medium value		
	High value fabric		
	Value added		
4.	Infrastructure	10	
	Preparatory level		
	Testing facilities		
	Mill stores availability		
	Yarn depot / Availability of yarn		
	Power availability and its price		
	Post-Knitting		
	Transportation, water, communication		
5.	Market Access	15	
	Export and its value, percentage of total product of cluster		
	Domestic and its value, percentage of total product of cluster		
6.	Skilled Manpower Availability	10	
7.	No. of banks / financial institutions in the cluster	5	
8.	Own production/ Jobwork production	5	
	Total	100	

Grading on the basis of marks allotted

Upto 40 -	D
41 to 60 -	C
61 to 75 -	B
Above 75 -	A

Annexure-VI**Specimen of Surety Bond One Hundred Rupees Judicial Paper****BOND PRESCRIBED TO BE EXECUTED BEFORE GRANT IS RELEASED**

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, M/s _____, a company incorporated under the Companies Act/Co-op. Society registered under Co-op Society Act of Govt. of _____ and having its registered office at _____ (hereinafter called the "Obligors") are held fully and firmly bounded to the President of India (hereinafter called the "Government") for the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) well and truly to be paid to the Government on demand and without a demur for which payment we firmly bind ourselves and our successors and assigns by these presents.

Signed on the _____ day of _____ in the year Two Thousand _____.

WHEREAS on the Obligors' request, the Government as per Sanction Order No. _____ Dated _____ of Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles (hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") which forms an integral part of these presents, and a copy whereof is annexed hereto and marked as Annexure-I, agreed to make in favour of the Obligors a grant of Rs. _____ (Rupees _____) for the purpose of construction of workshed and installation of specified machines at _____ out of which the sum of Rs. _____ (Rupees _____ only) have been paid to the Obligors (the receipt of which the Obligors do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligors executing a bond in the terms and manner contained hereinafter which the Obligors have agreed to do.

NOW the conditions of the above written obligation is such that if the Obligors duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, the above written Bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise, it shall remain in full force and virtue. The Obligors will abide by the terms & conditions of the grant by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligors shall not divert the grants and entrust execution of the Scheme or work concerned to another institution(s) or organization(s).

THAT the Obligors shall abide by any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the bond, the Obligors and the sureties individually and jointly will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the grant with interest of 10% per annum thereon. If a part of the grant is left unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, interest @10% per annum shall be charged upto the date of its refund to the Government, unless it is agreed to be carried over.

The Obligors agree and undertake to surrender/pay the Government the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive / have received or derived through / upon unauthorized use of (such as letting out the premises on adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that for which the grant was intended of the property) building/machineries created/acquired constructed largely from out of the Grant sanctioned by Government of India, Ministry of Textiles or the Administrative Head of the Department concerned. As regards the monetary value aforementioned to be surrendered/paid to the Government, the decision of the Project Approval Committee will be final and binding on the Obligors.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT

i) the decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of Textiles on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obligors and;

ii) the Government shall bear the stamp duty payable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on behalf of the Obligors the day herein above written in pursuance of the Resolution No. _____ Dated _____ passed by the governing body of the Obligor, a copy whereof is annexed hereto as Annexure-II and on behalf of the sureties and by _____ for and on behalf of the president on the date appearing below:-

FOR

Signature of the AUTHORISED SIGNATORY

Signed for and on behalf of

(Name of the Obligor)

1. Signature of witness 2. Signature of witness

Name & Address Name & Address

TO BE FILLED UP BY THE OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

(ACCEPTED)

For and on behalf of the President of India

Designation _____

Date: _____

Annexure-VII

Format of application of claim by the SPV alongwith documents to be submitted for the release of first instalment of 30% subsidy under CFC Scheme. (To be submitted within 90 days from the date of sanction)

To

Date-

The Officer In-charge,

Regional Office of the Textile Commissioner

Sir,

We herewith submit our claim for the release of first instalment of Govt. of India subsidy towards Common Facility Centre Scheme. We are enclosing the following documents for further necessary action.

1. Chartered Accountant Certificate of expenditures incurred towards construction of Common Facility Centre.
2. Certificate of proportionate expenditure by a Govt. approved architect.
3. Any other details.

You are requested to carryout LLMC verification and forward the report to the Office of the Textile Commissioner along with your recommendation.

Yours faithfully,

(Authorised signatory of SPV)

Annexure-VIII

Format of application by the SPV along with documents to be submitted for the release of second instalment of 30% GOI subsidy towards construction of building. (To be submitted within 180 days of the date of sanction)

To

Date-

The Officer In-charge,

Regional Office of the Textile Commissioner,

Sir,

We herewith submit our claim for the release of second instalment 30% of Govt. of India subsidy under the CFC Scheme of PowerTex India towards construction of building. We are enclosing the following documents further necessary action.

1. Chartered Accountant Certificate of expenditures incurred towards construction of Common Facility Centre.
2. Certificate of proportionate expenditure by a Govt. approved architect.
3. Sanction letters of the bank for the Term Loan for purchasing plant and machineries by the SPV.
4. Utilisation Certificate (UC) of 1st instalment.
5. Any other details.

You are requested to conduct necessary LLMC verification and forward the same to the Office of the Textile Commissioner along with your recommendation at the earliest.

Yours faithfully,
(Authorised signatory of SPV)

Annexure-IX

Format of application by the SPV along with documents to be submitted for the release of third instalment of 40% GOI subsidy towards construction of building. (To be submitted within 360 days of the date of sanction)

To
The Officer In-charge,
Regional Office of the Textile Commissioner,

Date-

Sir,

We herewith submit our claim for the release of third instalment of Govt. of India subsidy towards construction of buildings under the CFC Scheme of PowerTex India. We are enclosing the following documents further necessary action.

1. Chartered Accountant Certificate of expenditures incurred towards construction of Common Facility Centre.
2. Certificate of proportionate expenditure and construction completion certificate by a Govt. approved architect.
3. Documents of placement of order for plant and machineries and advance/token money released to the machinery supplier by SPV.
4. Utilisation Certificate (UC) of 2nd instalment.
5. Certificate from pollution control authorities as applicable.
6. Any other details.

You are requested to conduct necessary LLMC verification and forward the same to the Office of the Textile Commissioner along with your recommendation at the earliest.

Yours faithfully,
(Authorised signatory of SPV)

Annexure-X

Format of application by the SPV along with documents to be submitted for the release of GOI subsidy towards installation of machineries under CFC Scheme. (To be submitted within 18 months from the date of sanction)

To
The Officer In-charge,
Regional Office of the Textile Commissioner,

Date-

Sir,

We herewith submit our claim for the release of Govt. of India subsidy towards installation of machineries under the CFC Scheme of PowerTex India. We are enclosing the following documents further necessary action.

1. Chartered Accountant Certificate of expenditures on incurred on plant and machineries.
2. Invoices of plant and machineries towards installation of machineries by SPV.
3. Utilisation Certificate (UC) of 3rd instalment towards building.
4. Any other details.

You are requested to conduct necessary LLMC verification and forward the same to the Office of the Textile Commissioner along with your recommendation at the earliest

Yours faithfully,

(Authorised signatory of SPV)

SUMMARY AND CHECKLIST OF DOCUMENTS REQUIRED

Common Facility Centre(CFC) Scheme under Knitting & Knitwear Sector.

Stages	Objective	Requirement	Checklist of documents required	Stage of submission of documents
1.	Application for Sanction of CFC.	Application to be submitted by the Executing Agency (EA) at concerned Regional office of the Textile Commissioner	Application in Annexure- II of the guidelines along with 1.Detailed Project Report 2.Nature of SPV 3.Sale /lease deed of land/building in the name of SPV. 4.Non-agricultural land certificate. 5.Approved layout plan.	During submission of application.
2.	Forwarding application to office of the Textile Commissioner	RO has to forward application to Knitting&Powerloom Development Cell within 30 days from the date of receipt with recommendation.	Application in Annexure- II of the guidelines along with 1.Detailed Project Report 2.Nature of SPV 3.Sale /lease deed of land/building in the name of SPV. 4.Non-agricultural land certificate. 5.Approved layout plan. 6.Photos of the site.	-----
3.	Claiming for release of first installment of 30 %.	EA has to claim within 90 days from the date of sanction. Inform concern RO about 30 % completion of construction. 3. RO has to forward LLMC report to PDC within 30 days from the date of LLMC visit.	1.CA certificate of expenditure incurred for construction of workshed. 2.Certificate of proportionate expenditure by Govt.approved architect. 3.Photos of building under construction.	During LLMC visit.

Stages	Objective	Requirement	Checklist of documents required	Stage of submission of documents
4.	Claiming for release of second installment of 30 %.	1.EA has to claim within 180 days from the date of sanction. 2.Inform concern RO about 60 % completion of construction. 3. RO has to forward LLMC report to PDC within 10 days from the date of LLMC visit.	1.CA certificate of expenditure incurred for construction of workshed. 2.Certificate of proportionate expenditure by Govt.approved architect. 3.Utilization certificate of first installment. 4.Sanction letter of bank for the Term loan for purchasing plant & machineries for each beneficiary/EA 5.Photos of building under construction.	During LLMC visit
5.	Claiming for release of third installment of 40 %.	1.EA has to claim within 270 days from the date of sanction. 2.Inform concern RO about 100 % completion of construction. 3. RO has to forward LLMC report to PDC within 10 days from the date of LLMC visit.	1.CA certificate of expenditure incurred for construction of workshed. 2.Certificate of proportionate expenditure & construction completion certificate by Govt.approved architect. 3.Utilization certificate of second installment. 4. Documents of placement of order for plant & machinery by SPV & advance/token money released. 5.Photos of constructed building.	During LLMC visit
6.	Claiming for release of subsidy for plant & machinery.	1.EA has to claim within 18 months from the date of sanction. 2.Inform concern RO about installation & commissioning of plant & machinery. 3. RO has to forward LLMC report to PDC within 10 days from the date of LLMC visit.	1.CA certificate of expenditure incurred on plant & Machineries. 2. Submission of Invoices of Plant & Machineries. 3. Utilization certificate of third installment. 4.Pollution control certificate. 5.Photos of Plant& machinery	During LLMC visit

VII.Pradhan Mantri Credit Scheme for Knitting and knitwear sector

1) Objective

- i) The clothing (Knitwear & woven) industry in India is fragmented and predominantly in the SSI sector. This industry operates in a cluster centric approach which has a clear-cut advantage in terms of raw material, services and customers. Though fragmented, each cluster is quite diversified and unique. **Tirupur, Ludhiana and Kolkata being the major centres for Knitting and knitwear.**
- ii) India's share in the total global apparel trade is about 3.6% and is ranked sixth. India exports more than one hundred garment product categories, mainly falling in cotton, semi fashion middle price segment of casual wear with the main product categories being T-shirts, men's shirts, ladies blouses, ladies dresses and skirts. Member states of the EU, USA, Canada, UAE, Japan, Switzerland and Australia are the major markets for India's clothing exports. The share of knitted garments in value terms is about 38 percent in overall export of clothing, while in quantum terms it is 53 percent. There is no doubt that the knitted sector is emerging as the faster growing sector of the two and over a period, has succeeded in overtaking woven garment sector.

- ii) Due to non-availability of timely funding for their day to day activities, most of the knitting and knitwear sector units/ entrepreneurs in the decentralized sector are not able to go for product diversification and machine modernization.
- iii) Considering the above scenario, the knitting and knitwear sector units/ entrepreneurs in the decentralized sector need more financial support. Further, to encourage SC/ST and women entrepreneurs in the Country, timely financial support is quite necessary.
- iv) In view of above, GOI decided to launch a “Pradhan Mantri Credit Scheme for Knitting and knitwear sector, which aims at providing adequate and timely financial assistance to the knitting and knitwear sector units to meet their credit requirements, for investment needs (Term Loan), in a flexible and cost effective manner. The scheme will be implemented in all knitwear clusters in the Country. Credit facility should have been availed through all lending agencies covered under PMMY(MUDRA) and Stand-up India Scheme.

2) Implementation Procedure

Sr. No	Particulars	Category – I (under PMMY)	Category – II (under Stand-up India Scheme)
1	Eligibility	<p>The eligible units are;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Only New individual / group enterprises involved in Knitting and knit wear activity who are registered with MSME /Udyog Aadhar b. However Group Enterprises will be covered under the scheme without support of credit guarantee by the government and as per the prevailing norms of the Lending Agency. c. Units should not have availed subsidy under Amended Technology Upgradation Fund Scheme for the assets seeking benefits under PMMY. 	<p>The eligible units are;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Only new knitting and knitwear unit established by a person who belongs to a Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) or a woman entrepreneur who are registered with MSME / Udyog Aadhar b. In case of non-individual units at least 51 % of the share holding and controlling stake should be held by either an SC (or) ST (or) women entrepreneur. c. Units should not have availed subsidy under Amended Technology Upgradation Fund Scheme for the assets seeking benefits under Stand-up India Scheme.
2	Type of Facility & Loan Amount	<ol style="list-style-type: none"> a. The Term loan has to be availed. b. Maximum Loan up to Rs.10 lakh. c. Only new loans are eligible under the scheme. The loans already availed by a borrower are not eligible under the scheme. 	<ol style="list-style-type: none"> a. The Term loan has to be availed for purchasing of Machinery. b. The loan shall be above Rs.10 lakh and up to Rs.1 crore.
3	Due-diligence, Financial benchmark, Requirement of audited financial documents, Fixation of Credit Limit	As per the prevailing norms of lending agency.	As per the prevailing norms of lending agency.
4	Repayment	As per the prevailing norms of Banks.	As per the prevailing norms of Banks.
5	Financial assistance under the scheme i. Margin Money Subsidy	<ol style="list-style-type: none"> a. Margin money for the project will be decided by the lending agency as per their existing norms. Govt. will provide financial assistance on margin money @ 20% of basic cost with a ceiling of Rs.1 lakh for a borrower. Remaining amount of margin money will be borne by the 	<ol style="list-style-type: none"> a. The Scheme envisages 25% of the Basic cost of new machinery installed will be provided as Margin Money subsidy subject to the ceiling of Rs. 25 lakh. b. The borrower shall be required to bring in 10% of the cost of

Sr. No	Particulars	Category – I (under PMMY)	Category – II (under Stand-up India Scheme)
		borrower.	machinery as his/her own contribution.
	ii. Interest Subvention	<p>(a) Interest Subvention will be given on Term Loan.</p> <p>(b) Interest Subvention @ 6% per year on term loan will be provided upto 5 years from the date of first disbursement so that term loan where repayment period is more than 5 years will be also eligible.</p> <p>After payment of interest by the beneficiary, the lending agency will send the details of interest subsidy to be paid on the end of every quarter to Textile Commissioner. TxC will release the same.</p>	Not Applicable
6	Validity/Renewal of Limit, Security, Rate of Interest & other charges	<p>As per the prevailing norms of lending agency.</p> <p>No collateral/security is required to be given for PowerTex MUDRA Loan.</p>	As per the prevailing norms of lending agency.
7	Reimbursement of Credit Guarantee	<p>1% of the loan amount or the actual amount of fees whichever is less charged for the credit guarantee for a maximum of five years under CGTMSE/ Credit Guarantee Scheme for Micro Units under National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) scheme.</p> <p>Not applicable for Group Enterprises.</p>	1% of the loan amount or the actual amount of fees charged for the credit guarantee for a maximum of five years under CGTMSE/ Credit Guarantee Scheme for Stand-Up India under National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) scheme, whichever is less.
8	GOI Support	<p>a. Interest Subvention @ 6% per year for term loan will be provided upto 5 years from the date of first disbursement so that term loan where repayment period is more than 5 years will be also eligible.</p> <p>b. Margin money for the project will be decided by the lending agency as per their existing norms. Govt. will provide financial assistance on margin money @ 20% of basic cost of new machinery installed with a ceiling of Rs.1 lakh for a borrower. Remaining amount of margin money will be borne by the borrower.</p> <p>c. Submission of applications will be done online to the Office of the Textile Commissioner which in turn will forward the application(s) to the Banks concerned, through online mode.</p>	<p>a. The Scheme envisages 25% of the Basic cost of new machinery installed will be provided as Margin Money subsidy subject to the ceiling of Rs. 25 lakh.</p> <p>The borrower shall be required to bring in 10% of the cost of machinery as his/her own contribution.</p> <p>b. Submission of applications will be done online through iPowerTex portal to the Regional Office of the Textile Commissioner which in turn will forward the application(s) to the Banks concerned through online mode.</p> <p>c. Before submission of the claim for Margin Money Subsidy for the first time, particulars of the claim details</p>

Sr. No	Particulars	Category – I (under PMMY)	Category – II (under Stand-up India Scheme)
		d. Before submission of the claim for Margin Money Subsidy/Interest Subvention for the first time, particulars of the claim details shall be verified by a Joint Inspection Team (JIT) comprising of members from the Branch of the Bank and PSC/ROs of the Office of the Textile Commissioner in the prescribed format as at Annexure-III; the inspection details will be uploaded to iPowerTex India.	shall be verified by the Joint Inspection Team (JIT) comprising members of the Branch of the Bank and PSC/ROs of the Office of the Textile Commissioner in the prescribed format Annexure-IV. The inspection report will be uploaded to iPowerTex India.
9	Mode of release of GOI's subsidy	a. The Margin Money Subsidy will be credited in the term loan account of the borrower through respective Lending Agency. b. Reimbursement of Credit Guarantee fee will be credited to the Term loan a/c of the borrowers through Lending Agency on an annual basis. c. Interest subvention will be credited to the Term loan a/c of the borrowers through Lending Agency on an annual basis.	a. The Margin Money Subsidy will be credited in the term loan account of the borrower through respective Lending Agency. b. Reimbursement of Credit Guarantee fee will be credited to the Term loan a/c of the borrowers through Lending Agency on an annual basis.
10	Issuance of cards/ Passbooks	The lending agency will issue the cards/passbooks to Knit and Knit wear units as per norms of the Lending Agency.	The lending agency will issue the cards/passbooks to Knitting & Knitwear unit as per norms of the Lending Agency.
11	Management Information System(MIS)	An i-PowerTex software has been developed so that all applications can be filed online.	An i-PowerTex software has been developed so that all applications can be filed online.

Safeguards against mis-utilisation of the Scheme.

1. The lending agencies are required to carry out due diligence before sanctioning of the loan under the Scheme.
2. The Regional Office concerned of the Textile Commissioner as well as the senior officers of the Office of the Textile Commissioner will carry out random verification of the beneficiaries.
3. Provision should be made for uploading the documents by Knitting & Knitwear Units after the machinery is purchased and installed under the term loan drawn under Stand Up India Scheme.
4. The scheme applications will be received through online portal i.powertex India. The sanction of loan will be conveyed by lending agency through this portal.
5. All decisions and advices of the lending agency will be communicated to Textile Commissioner's office and the borrowing units online.
6. PAC decision will be final

**FORMAT FOR INCLUSION OF LENDING AGENCY UNDER PRADHAN MANTRI CREDIT SCHEME FOR
KNITTING & KNITWEAR (PMCS)**

(To be submitted to the Textile Commissioner through ipowertex software)

1	Name of the Bank	
2	Address	
3	Name of the Contact Person	
4	Contact No. (O)	
5	Mobile No.	
6	E-mail ID	
7	Fax No.	
8	Name of the Nodal Branch/ Office Nominated by the Bank	
9	IFSC Code of the Nodal Branch/Office	
10	MICR Code of the Nodal Branch/ Office	
11	Contact Person	
12	Contact No. (O)	
13	Mobile No.	
14	E-mail ID	
15	Fax No.	

Signature

Date:

Name & Designation with Seal

List of enclosures:

1. Copy of Banking Licence issued by RBI under Banking Regulation Act 1949.
2. Copy of letter issued by RBI for inclusion in the 2nd Scheduled to the RBI Act, 1934.
3. Copy of letter issued by GOI for registration under Multi State Cooperatives Act, if applicable.
4. Copy of PAN/TAN No.
5. Copies of Audited Balance Sheet for the preceding 3 years.
6. Other relevant information, if any.

ANNEXURE-I

Application Form for Loan under “Pradhan Mantri Credit Scheme for Knit and Knit Wear ”(PowerTex MUDRA)

For Loan upto Rs.10,00,000/-

Name of Bank & Branch from where loan is required

I hereby apply for Cash Credit/Over Draft/Term loan of Rs.....for.....

Name of Applicant (s)	1.	Father's/Husband's name	1.
	2.		2.

Constitution ()		Individual	Joint	Proprietor	Partnership	Other
Residential Address						
		Rented/Owned				
Business Address						
		Rented/Owned				
Date of Birth			Age	Sex : Male/Femat/T.G.		
Educational Qualification ()	Illiterate	Upto 10 th	Upto 12 th	Graduate	Professional	Others
KYC Documents (s)	Voter ID No.		Aadhar No./Udyog Aadhar		Driving License No.	Any Other
ID proof (pl. Specify)						
Address Proof (Pl.specify)						
Telephone No.:		Mobile No.			E-mail:	
Line of Business Activity (Purpose)	Existing		Period			
	Proposed					
Annual Sales (Rs.in Lakh)		Existing:			Proposed:	
Experience, if any						
Social Category (Pl. tick)		General	SC	ST	OBC	Minority Community
If Minority	Buddhist	Muslim	Christian	Sikh	Jain	Zoroastrains Others
Loan Amount Required		CC/OD- Rs.			Term Loan-Rs.	
Details of Existing Account(s), if any		Type (Pls tick) (Deposit/Loan)		Name of Bank & Branch		
A/C No.			If Loan A/c amount of loan taken			Rs.

Declaration:

I/We hereby certify that all information furnished by me/us is true, correct and complete. I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application form. I/We have not applied to any Bank. There is/are no overdue/statutory due owed by me/us. I/We shall furnish all other information that may be required by Bank in connection with my/our application. The information may also be exchanged by you with any agency you may deem fit. You, your representatives or Reserve Bank of India or any other agency as authorised by you, may at any time, inspect/verify my/our assets, books of accounts etc. in our factory/business premises as given above. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.

Date: _____

Place: _____

Thumb Impression/Signature of Applicant(s)

(For Office use only)

Acknowledgement Slop No. _____ Loan Application No. _____ Dated _____

Received by _____

Date: _____

Place: _____

Authorized Signatory(Branch Seal and Sign)

-----Cut here-----

Acknowledgement slip no _____ for loan application under PMMY (Applicant's copy) received with thanks from Sh./Smt. _____ loan application dated _____ for Rs. _____

Date: _____

Place: _____

Authorized Signatory (Branch Seal and Sign)**CHECK LIST: (Document(s) to be submitted along with the application)**

- 1) Proof of identity – Self attested copy of Voter's ID Card/ Driving Licence /PAN Card/ Aadhaar Card/ Udyog Aadhar/Passport / Photo IDs issued by Govt. Authority, IM-Acknowledgement issued by the concerned Regional Offices of the Textile Commissioner etc.
- 2) Proof of Residence – Recent telephone bill/ electricity bill/ property tax receipt (not older than 2 months) /Voter's ID Card/ Aadhaar Card/ Passport for Individual/ Proprietor /Partners Bank Passbook or latest account statement duly attested by Bank Officials/ Domicile Certificate/ Certificate issued by Govt. Authority/ Local Panchyat/Minicipality etc.
- 3) Applicant's Recent Photograph (2 copies) not older than 6 months.
- 4) Quotation of Machinery/Other items to be purchased.
- 5) Name of supplier/details of machinery/ price of machinery and/or items to be purchased.
- 6) Proof of Identity/Address of the Business Enterprise – Copies of relevant Licenses/ Registration Certificates/ Other Documents pertaining to the ownership, identity and address of business unit, if any.
- 7) Proof of category like SC/ST/OBC/Minority etc.

NOTE :

- 1) No collateral/security for PowerTex MUDRA Loan.
- 2) Applicant should not be defaulter of any bank/Financial Institution.

ANNEXURE-II

Name of the Bank:

Bank's Logo

Loan under “Pradhan Mantri Credit Scheme for Knit and Knitwear(Stand Up India)”

(To be submitted along with documents as per the check list)

A. For Office Use:

Enterprise Name	Application Sl. No.	Name of the Branch	Category
			SC/ST/Woman

B. Business Information:

Name of the Applicant / Enterprise										
Constitution	Proprietary	Partnership	Pvt. Ltd.	Ltd. Company	Any Others (specify)					
Business Address										
	State				PIN Code					
	Business Premises				Rented	Owned				
Telephone				Mobile No.	91					
E-mail:										
Business Activity	Proposed									
Date of Commencement(DD/MM/YYYY)										
Whether the Unit is Registered		Yes		No						
If Registered (Please mention: Registration no. And the Act under which registered)										
Udyog Aadhar Registration No. (Non Mandatory)										
Registered Office Address										
Social Category		SC	ST	Minority Community						
If Minority Community	Buddhists	Muslims	Christians	Sikhs	Jains	Zoroastrians				

C. Background Information of Proprietor/ Partners/ Directors of Company and their addresses:

S.No.	Name	Date of Birth	Sex	Residential Address with Mobile No.	Academic Qualification	Experience in the line of activity (years)

--	--	--	--	--	--	--

S.No.	Id proof	Id proof no.	Address proof	Address proof no.	PAN Card/DIN No.	Relationship with the Official/ Director of the bank if any

D. Names of Associate Concerns, if any, of JV Partner or Director of proposed Unit:

Names of Associate Concern	Address of Associate Concern	Presently Banking with	Nature of Association Concern	Extent of Interest as a Prop./Partner/ Director or Just Investor in Associate Concern

E. Banking/Credit Facilities Existing: (In Rs.)

Type of Facilities	Banks Name and Branch	Limit Availed	Outstanding As on.....
Savings Account		N.A	
Current Account		N.A	
Term Loan			
If banking with this bank, customer ID to be given here:			
It is certified that our unit has not availed any loan from any other Bank / Financial Institution in the past and I/we am/are not indebted to any other Bank / Financial Institution other than those mentioned in column no. E above.			

F. Credit Facilities Proposed: (In Rs.)**

Types of Facilities	Amount	Purpose for which Required	Security Offered	
			Primary Security (Details with approx. value to be mentioned)	Whether Collateral Security Offered (If, yes, then provide details on column I) (yes/No)
Cash Credit**				
Term Loan				
LC/BG				
Total				

** Mandatory Fields

G. In case of Working Capital: Basis of Cash Credit Limit applied: (In Rs.)

Cash Credit	Projected						
	Sales	Working Cycle in Months	Inventory	Debtors	Creditors	Promoter's Contribution	Limits

H. In case of Term loan requirements, the details of machinery/equipment may be given as under:

Type of Machine/ Equipment	Purpose for which required	Name of supplier	Total Cost of Machine	Contribution being made by the promoters (Rs.)	Loan Required (Rs.)
Total					

Repayment period with Moratorium period requested for	
-------------------------------------------------------	--

I. Future Estimates: (In Rs.)

Future Estimates (Estimates for current year and projections for first year to be provided for working capital facilities. However for term loan facilities projections to be provided till the proposed year of repayment of loan)				
	Current Year (Estimate)	First Year (Projection)	Second Year (Projection)	Third Year (Projection)
Net Sales				
Net Profit				
Capital (Net Worth in case of Companies)				

J. Status Regarding Statutory Obligations:

Statutory Obligations	Whether Complied with (select Yes/No) If not applicable then select N.A.	Remarks (Any details in connection with the relevant obligation to be given)
1. Registration under Shops and Establishment Act		
2. Registration under MSME (Provisional / Final)		
3. Latest Sales Tax Return Filed		
4. Latest Income Tax Returns Filed		
5. Any other Statutory dues remaining outstanding		

K. Declaration:

I/We hereby certify that all information furnished by me/us is true, correct and complete. I/We have no borrowing arrangements for the unit except as indicated in the application form. There is/are no overdue/statutory due owed by me/us. I/We shall furnish all other information that may be required by Bank in connection with my/our application. The information may also be exchanged by you with any agency you may deem fit. You, your representatives or Reserve Bank of India or any other agency as authorised by you, may at any time, inspect/verify my/our assets, books of accounts etc. in our factory/business premises as given above. You may take appropriate safeguards/action for recovery of bank's dues.

Space for Photo	Space for Photo	Space for Photo
(Signatures of Proprietor/partner/director whose photo is affixed above)		

Date: _____

Place: _____

CHECK LIST

1. Proof of Identity: Voter's ID/ Passport/Driving License/PAN Card/Signature identification from Present Bankers of Proprietor, partner of Director (If a company).
2. Proof of Residence: Recent Telephone Bills, Electricity Bill, Property Tax Receipt /Passport/Voter's ID Card of Proprietor, partner of Director (if a company).
3. Proof of Business Address.
4. Applicant should not be defaulter in any Bank/F.I.
5. Memorandum and articles of association of the Company/Partnership Deed of partner etc.
6. Assets and liabilities statement of promoters and guarantors along with latest income tax returns.
7. Rent Agreement (if business premises on rent) and clearance from pollution control board if applicable.
8. SSI / MSME registration if applicable.
9. Projected balance sheets for the next two years in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan.
10. Photocopies of lease deeds/title deeds of all the properties being offered as primary and collateral securities.
11. Documents to establish whether the applicant belongs to SC/ST Category, wherever applicable.
12. Certificate of incorporation for ROC to establish whether majority stake holding in the company is in the hands of a person who belongs to SC/ST/Woman category.

For Cases with Exposure above Rs. 25 Lakhs

1. Profile of the unit (includes names of promoters, other directors in the company, the activity being undertaken addresses of all offices and plants, shareholding pattern etc).
2. Last three years balance sheets of the Associate / Group Companies (if any).
3. Project report (for the proposed project if term funding is required) containing details of the machinery to be acquired, from whom to be acquired, price, names of suppliers, financial details like capacity of machines, capacity of utilisation assumed, production sales, projected profit and loss and balance sheets for the tenor of the loan, the details of labour, staff to be hired, basis of assumption of such financial details etc.
4. Manufacturing process if applicable, major profile of executives in the company, any tie-ups, details about raw material used and their suppliers, details about the buyers, details about major-competitors and the company's strength and weaknesses as compared to their competitors etc.

(The check list is only indicative and not exhaustive and depending upon the local requirements at different places addition could be made as per necessity).

ANNEXURE-III

Format for verification of claims under “Pradhan Mantri Credit Scheme for Knit and Knitwear”(PowerTex MUDRA)

1	Name & Address of the factory	
	Taluka/Tahshil/Mandal:	
	District:	
	State:	
	Pin code:	
	Phone No./Mobile No.	
	Fax No.	
	E-Mail ID	
	PAN No.	
2	Aadhar Number	
3	Name of Contact Person with Tel./ Mob. no	
4	IM Acknowledgement No./Udhyog Aadhar No & Date along with Registering Authority	
5	Number of Looms	
6	Constitution (Individual/Proprietorship / Partnership/Pvt. Ltd.)	
7	Name of Proprietor / Partner(s) / Director(s)	
8	Gender of the Applicant(Male/Female)	
9	Category of the Applicant (General/ OBC/SC/ST/Minority etc.) In case of Minority pls. mention the detail	
10	Total Cost of Project	
11	Amount of Loan a. Term Loan	
12	Amount of Loan disbursed a. Term Loan	
13	Existing Machineries a. Name of the Machine b. Quantity	

14	New Machineries installed under the scheme (if any) a. Name of the Machine b. Quantity	
15	Basic value of the claimed machineries	
16	Name and address of the Bank (complete Branch details with Pin code, IFS Code & Email id)	
17	Term Loan Account no:	
18	Whether the Project confirms in accordance to the guidelines	
19	Whether JIT recommends for release of	
	a. Margin Money subsidy	
	b. Interest Subvention subsidy	
20	If yes, then eligible	
	a. Margin Money subsidy	
	b. Interest Subvention subsidy	
21	Remarks , if any	

It is certified that the above said claim is found to be in order in all respect as per the Guidelines of **Pradhan Mantri Credit Scheme for Knit and Knitwear[PowerTex MUDRA] under PowerTex India** hence recommended for release of Margin Money subsidy.

Signature of the Joint Inspection Team Member along
with his seal

(Representative from the Branch of the Lending
Agency)

Signature of the Joint Inspection Team Member along
with his seal

(Representative of the Powerloom Service
Centre/Regional Office of the Textile Commissioner)

ANNEXURE-IV**Format for verification of claims under “Pradhan Mantri Credit Scheme for Knit and Knitwear” (Stand Up India)**

1	Name & Address of the factory	
	Taluka/Tahshil/Mandal:	
	District:	
	State:	
	Pin code:	
	Phone No./Mobile No.	
	Fax No.	
	E-Mail ID	
	PAN No.	
2	Aadhar Number	
3	Name of Contact Person with Tel./ Mob. no	
4	IM Acknowledgement No./Udhyog Aadhar No & Date along with Registering Authority	
6	Constitution (Individual/Proprietorship / Partnership/Pvt. Ltd.)	
7	Name of Proprietor / Partner(s) / Director(s)	
8	Gender of the Applicant(Male/Female)	
9	Category of the Applicant (General/ OBC/SC/ST/Minority etc.) In case of Minority pls. mention the detail	
10	Name and address of the Bank (complete Branch details with Pin code, IFS Code& Email id	
11	Total Cost of Machines a. Promoters Contribution b.Term Loan Disbursed	
12	New Machineries installed under the scheme (if any) c. Name of the Machine b. Quantity	
13	Basic value of the claimed machineries	
14	Term Loan Account no:	
15	Whether the Project confirms in accordance to the guidelines	
16	Whether JIT recommends for release of subsidy	
17	If Yes Amount of Margin Money subsidy	
18	Remarks	

It is certified that the above said claim is found to be in order in all respect as per the Guidelines of **Pradhan Mantri Credit Scheme for Knit and Knitwear under PowerTex India** hence recommended for release of Margin Money subsidy.

Signature of the Joint Inspection Team Member along
with his seal

(Representative from the Branch of the Lending
Agency)

Signature of the Joint Inspection Team Member along
with his seal

(Representative of the Powerloom Service
Centre/Regional Office of the Textile Commissioner)

VIII. Guidelines for Facilitation, IT, Awareness, Market Development and Publicity for Knitting and Knitwear Sector Schemes

1.0 Objectives

- To give wide publicity, including event based publicity etc. through multimedia, electronic, print, film media, to the Knitting and Knitwear Sector schemes, programmes being run by the Office of Textile Commissioner, Mumbai (OTxC).
- To create an enabling environment for publicity
- To disseminate information about the modalities and benefits of schemes, programmes being run by OTxC, Mumbai.
- To promote awareness and to trigger the developmental mode of Knitting and Knitwear sector.
- To encourage volunteer action for ensuring effective implementation of schemes, programmes being run by the O/o TxC, Mumbai.
- To extend financial support for National & International events organized by OTxC, Mumbai.

4.0 Period of Operation of the Scheme

The period of operation of the scheme will be from 01.07.2019 to 31.03.2020.

(a) Components of Facilitation Services and IT :

(a) Facilitation Services

- Help – line:** A dedicated toll free **Help-line** would be setup to provide necessary help/guidance/information to the Knitting and Knitwear Sector by making toll free call.
- Registration Facility for Knitting and Knitwear Sector units with the KSCs:** There would be a system to register the Knitting and Knitwear Sector units at the Knitting Service Centers (KSC) so that the KSCs can reach out to these units to disseminate the information on the Government Schemes. The interface will also enable the units to understand the facilities available with KSCs and so as to avail the benefits.
- SMS alerts:** A system will be developed so as to provide SMS alerts to Knitting and Knitwear Sector units on new developments/initiatives on Knitting & Knitwear related subjects.
- Bank Assistance:** The services of the lead bank and the major banks in the Knitting and Knitwear clusters will be facilitated through with the KSCs so that necessary assistance can be extended to the Knitting and Knitwear Sector units to avail credit facilities and MUDRA loans from the Banks.
- Entrepreneur Cell:** An Entrepreneur Cell will be created in each Knitting and Knitwear Service Centre to disseminate information on the various Govt. Schemes.
- Design and Technical Advancement:** The KSCs will provide designing facilities and requisite technical training, suitably structured for the Knitting and Knitwear Sector units.
- Any other facilitation services.**

(b) IT- Development of online-portal / mobile application in respect of schemes implemented by GOI.

- Development of online-portal play a vital role in providing an easy and single point access to information about the various developmental schemes implemented by the Government of India and their various aspects including eligible beneficiaries, types of benefits, scheme details etc.
- Mobile apps further provide a much faster alternative, as it only takes a second to launch a mobile app because the majority of the information is stored in the application itself making it possible to function offline. This helps build loyalty with the end users facilitating in connecting with the information. The advantages of a mobile application is to seamlessly connect and interact with end-users, making it a valuable tool for accessing the schemes implemented by the GOI, consequently reducing staff workload by information requests and phone calls.

1.0 Awareness and Market Development Programmes

- Seminars/ Workshops:** To create awareness about Government schemes, disseminate the information about technology, Services, products for the benefits of Knitting and Knitwear Sector units. Workshops/seminars/awareness programme are conducted by Regional Offices, Knitting and Knitwear Service Centres of the office of Textile Commissioner as well as other Export Promotion Councils, TRAs etc.
- Buyer Seller Meets:** The market development activities like Exhibition/Fair and Buyer-Sellers Meet under the scheme is serving the needs of the Knitting and Knitwear Sector units for marketing their products in national and international level.

Under this scheme, financial assistance is given for organizing exhibitions, infrastructure support, stall rent, stall furnishing, electricity charges, publicity, back up services and administrative expenses.

- International events like Reverse Buyer Seller Meets:**
International events like Reverse Buyer Seller Meet are conducted in India in association with Export Promotion Councils/ Knitting and Knitwear Industry Associations by inviting potential Buyers & Importers from foreign countries. In such events, leading Indian companies exhibit/ showcase the latest range of Knitted fabric and Knitwear Garments before the visiting foreign buyers, to enable participating members to develop / expand their export trade. Thus, the visiting buyers have a unique opportunity to see the latest products of leading textile companies under one roof, interact with the senior representatives of participating companies and conclude profitable business deals.

- E-platform for marketing of Knitted and Knitwear products:**
Promotion of marketing of Knitted and Knitwear products through e-commerce is one of the priorities of Ministry of Textiles. In order to promote e-marketing of Knitted and Knitwear products in a transparent, competitive and effective manner, Office of the Textile Commissioner under Ministry of Textiles will avail the services of any willing e-commerce platform with good track record for participation in online marketing of Knitted and Knitwear products.

- Exposure visits forentrepreneurs of Knitting and Knitwear clusters:**
The exposure visits for entrepreneurs of **Knitting and Knitwear clusters** are organized with a view to understand better technology, product etc. The entrepreneurs of **Knitting and Knitwear cluster** from present level of technology are required to be exposed to the developed cluster having latest technology/manufacturing in order to motivate them to adopt technology and diversify the products.

Financial assistance @ Rs.5000 towards incidental expenses and to & fro train fare restricted to Sleeper-Class fare for each entrepreneur is provided by GOI.

- Conducting Studies, Survey & Evaluation Programmes/ Schemes on special needs:**
The results of analytical studies and surveys help in designing appropriate strategies and measures of intervention by the Government, by itself or in public private partnership mode, to assist and enable the Knitting and Knitwear industry in facing the challenges and availing of the opportunities with a view to enhancing their efficiency and competitiveness and also expanding generation of sustainable employment. The inferences drawn from these studies will help suggest changes to the schemes so that they fulfill their objectives.

Monitoring / evaluation of the schemes helps to obtain feedback on- (i) its performance (ii) how resources have been spent (iii) creditability on continuance of the schemes. Further, evaluation of schemes helps to address problematic issues viz. (i) Strengths and Weaknesses of the project implemented (ii) Bottlenecks/ Implementation problems (iii) Success and failure indicators and (iv) the good practice issues.

(vii) Any other awareness and Market Development Programmes.

For eg. through print media, electronic media, hoardings, mobile-publicity van, adopting different ICT modes for creating maximum awareness.

5.0 Publicity in Electronic and Print Media:

The main intent of any media is to pass information to the public. Electronic media a more advanced form of media could be Internet, Television etc. can be reached faster through different channels, site etc. Print media typically includes Newspapers, Articles, and Journals etc. allowing users to read anytime and anywhere be it Electronic or Print media, the needs of the Stake Holders / Knitting and Knitwear Entrepreneurs can be addressed by these tools through Information Technology in assisting the publicity and creation of awareness of the various Knitting and Knitwear Sector schemes.

6.0 Implementation Agency

Office of Textile Commissioner through its Regional Offices/ Knitting and Knitwear Service Centers (KSCs) alongwith Export Promotion Councils and Knitting and Knitwear Associations will implement the scheme.

7.0 Monitoring of the progress of the scheme

The Textile Commissioner will monitor the progress of the scheme from time to time.